राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का १८वां दिवस [संख्या १२

गुरुवार, ८ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, श्रम, कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, वन, यातायात, विधि एवं पंचायत-विभाग]

गत वर्ष भरतपुर जिले में टूटे हुए बंधों के क्षेत्र से सिंचाई दरें लेने की मनाही

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

४१०. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(1) Did the Government issue orders staying the collection of irrigation rates from the breached Bunds in Bharatpur District for the last year? If so, when were those orders issued and implemented in the district with special reference to Rupbas, Bayana and Kumher Tehsils?

(2) How many bunds were breached or remained unrepaired last year or this year before? Please give a list tehsil-wise and for how many the collection of irrigation rates was stayed?

सिंचाई उप मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, यह आज्ञा २७ फरवरी १९६० को समस्त भरतपुर जिले के लिए निकाली गई थी और उसी समय कार्यान्वित कर ली गई थी।

(२) पिछले वर्ष २२ बांध टूटे हुए थे। जिसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। रिकवरी रोके जाने की आज्ञा सब बांधों के लिए थी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

Page No.2

चूरू जिले में बेरोजगारी की समस्या

४११. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चुरू जिले में पढ़े-लिखे तथा बिना पढ़े कितने आदमी बेरोजगार हैं ? कृपया १ जनवरी, १९५९ से इसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) सरकार जिले में बढ़ती हुई इस प्रकार की बेकारी को दूर करने के लिये क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : चूरू जिले में रहने वाले पढ़े-लिखे तथा बिना पढ़े बेरोजगार व्यक्तियों की सही सही संख्या बताना संभव नहीं है ।

परन्तु इतना कहा जा सकता है कि १ अगस्त, १९६० को नियोजन कार्यालय, बीकानेर के चालू रजिस्टर पर जहां पर कि आम तौर से चूरू जिले के रहने वाले रोजगार पाने में सहायता के लिये नाम लिखवाते हैं इस जिले के २३९ पढ़े-लिखे और २१७ अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ।

इससे पहले के मासिक आंकड़े देना अब संभव नहीं है ।

(२) यह कहना कठिन है कि चुरू जिले में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है किन्तु राज्य में बेकारी की समस्या को हल करने के लिये निम्नांकित योजनायें सरकार के सामने हैं:—

१. नियोजन सेवा सुविधा का विस्तार ।

२. व्यवसायिक मार्ग-दर्शन कार्यक्रम को मूर्त रूप देना ।

३. व्यवसाय चुनाव पुस्तिकाओं का प्रकाशन और वितरण ।

४. औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार ।

५. राजस्थान नहर आदि योजनाओं द्वारा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना ।

६. लघु उद्योगों को सहायता एवं प्रोत्साहन ।

७. राज्य के औद्योगीकरण की शिक्षा में विशेष प्रयास ।

८. इन सब योजनाओं का असर चूरू पर भी पड़ेगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना में चूरू जिले में एक नियोजन कार्यालय स्थापित करने का तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का सरकार का इरादा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

जालोर जिले के कृषि फील्डमैन के टी० ए० बिल्स का भुगतान

४१२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला जालोर के कितने कृषि फील्डमैन के टी० ए० बिल्स माह जनवरी १९५९ से आज तक बकाया हैं और उनका भुगतान न करने का क्या कारण है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम

Page No.3

(श्री दौलतराम)

सारण) : जालौर जिले में जिन जिन फील्डमैनों के यात्रा के बिल दिनांक १-१-५६ के पश्चात् बकाया हैं उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

इनका भुगतान फंड समाप्त हो जाने के कारण नहीं हो सका था। उचित धन-राशि की व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गांव देहातु तहसील शेरगढ़ के हरिजन

४१३. **श्री सूरजमल** (फलौदी यु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील का गांव देहातु के क्षत्रियों ने अनुसूचित जातियों के लोगों को बिना किसी कारण परेशान कर रखा है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवा कर उक्त गांव में अनुसूचित जातियों के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कराने का विचार रखती है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सूरजमल : यह उत्तर आपने किस आधार पर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना मेरे पास आयी है उसके आधार पर।

श्री सूरजमल : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मन्त्री की जानकारी के लिये कह दूँ कि क्षत्री श्री मोतीलाल और श्री फतहलाल ने अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार कर रखा है और मन्त्रीजी कहते हैं कुछ नहीं है!

श्री रामकिशोर व्यास : मोतीलाल का केस अदालती केस है, वह तो सिविल मामला है।

श्री सूरजमल : तो आपने जानकारी किस बात की की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिविल केस जो चल रहा है वह अदालत में है, पुलिस का उससे क्या ताल्लुक है ?

श्री सूरजमल : तो क्या सरकार यह चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर वे अत्याचार करते रहें और उस डर के कारण वे लोग वहां से छोड़ कर भाग जायं।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है।

श्री सूरजमल : मेरे कहने पर क्या माननीय मंत्री इसकी दुबारा जांच करवा कर जो अत्याचार करने वाले गुण्डे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्रीमुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चूरू जिले की अदालतों में पेन्डिंग मामले

४१५. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चूरू जिले की १, २, ३ और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स की अदालतों में १–१–५७ से ३१–१–६० तक कितने मुकदमें दर्ज हुए, कितनों का फैसला हो चुका है और कितने बाकी हैं ? अदालत वाइज़ सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) क्या यह सही है कि मुकदमों में बार बार तारीखें डाल दी जाती हैं जिससे जनता परेशान व खर्चे से हैरान हो उठी है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त मुकदमों का निपटारा शीघ्र करवाने की व्यवस्था करेंगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) १ जनवरी, सन् ५७ से ३१ जनवरी, सन् ६० तक चुरू जिले की प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में दर्ज व फैसले किये गये मुकदमात की संख्या इस प्रकार है :

कोर्ट	गत वर्ष के शेष	नये दर्ज	कुल संख्या	निर्णय	शेष
प्र. श्रेणी	६३३	६४६	१२८२	५७४	७०८
द्वि. श्रेणी	२६१	११०५	१३६६	१०४१	३५५
तृ. श्रेणी	६१	१६५	२२६	१५३	७३

(ख) मुकदमों में तारीखें बदलना मजिस्ट्रेटों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है । ऐसा उसी अवस्था में होता है कि या तो न्याय नियम के अनुसार आवश्यक हो अथवा उन्हें राजस्व व प्रशासन आदि अन्य कार्यों में व्यस्त रहना पड़े ।

(ग) मुकदमों का शीघ्र निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधीशों द्वारा समय-समय पर आवश्यक आदेश दिये जाते रहते है ; अतः उक्त मुकदमों के लिये किन्हीं विशेष आदर्शों की आवश्यकता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जयपुर नगर की सफाई–व्यवस्था

४१६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार क्या–क्या उपाय कर रही है ?

(२) क्या इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्लश की तहारतें लगाने का एक अभियान नगरपालिका ने चालू किया था ? कितनी फ्लश की तहारतें इस अभियान के अन्तर्गत लगायी गई और कितने लोगों को कितनी राशि की सहायता अथवा ऋण इस काम के लिये दिया गया ?

(३) क्या यह अभियान आगे भी चालू रहेगा ? इसके लिये कितनी सहायता अथवा ऋण प्रति व्यक्ति, किन शर्तों पर देने का प्रावधान है ?

(४) चौकड़ी मोदीखाना व चौकड़ी तोपखाना देश में कितनी गलियां व सडकें अब तक भी कच्ची पड़ी है ? क्या उन्हें शीघ्र पक्की कराने की योजना है ?

Page No.5

(डॉ० चन्द्रकला)

(५) घरों के चारों ओर जो गलियां कच्ची हैं और जिनके कारण गन्दगी बढ़ती है उन्हें पक्की कराने के सम्बन्ध में भी कोई योजना है क्या ?

(६) पुराने ढंग की गन्दगी और बदबू फैलाने वाली टट्टियों के सुधार के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) सफाई व्यवस्था के सुधार के हेतु नगरपालिका, जयपुर, कई विशेष योजनायें बना रही है।

(२) जी हां। इसके अन्तर्गत लगभग ३००० तहारत फ्लश के बने हैं।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(४) चौकडी मोदीखाना में १० गलियां व चौकडी तोपखाना देश में २२ गलियां कच्ची हैं। २३ गलियों को पक्की कराने की योजना नगरपालिका द्वारा बनाई गई है।

(५) घरों के चारों ओर गलियां जो कच्ची है और जिनमें तहारत फ्लश के बने हुए हैं पक्की कराने की योजना बनाई गई है। और इस वर्ष उस कार्य के लिये योजना विचाराधीन है।

(६) पुराने ढंग की मोखी, आसार तहारतों के लिये जहां जहां गटर की लाइने डाली जा चुकी हैं सम्बन्धित मकान मालिकों को नोटिस दिये जा रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : नगरपालिका जयपुर ने फ्लश अभियान चालू किया था, वह अब बन्द क्यों कर दिया गया है ?

श्री सम्पतराम : वह तो चालू रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने भाग ३ में बताया था 'जी नहीं'। जो अभियान चालू किया गया था वह अब किन कारणों से बन्द कर दिया गया ? क्या सरकार सन्तुष्ट हो गई है कि अब सफाई की जरूरत नहीं है ?

श्री सम्पतराम : सरकार सन्तुष्ट नहीं है, सफाई की जरूरत नहीं हैं: यह न सरकार कह सकती है और न माननीय सदस्या। वैसी हालत में जब कभी सफाई के इस प्रकार के अभियान चालू होते हैं उनमें बड़े-बड़े फाइनेन्सेज़ डाइवर्ट करने होते हैं। इसलिये अभियान के रूप में तो वह बन्द हो गया है किन्तु नॉर्मल फंक्शन्स हैं वे तो जारी रहेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : पुरानी तहारतों को जो बदलने का नोटिस दिया जा रहा है वे कब से दिये जा रहे हैं और नोटिस द्वारा उनको क्या कहा जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : यही कहा जा रहा है कि आप फ्लश की तहारतें करावें, डेट तो मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उस नोटिस में निश्चित समय दिया गया है कि इतने समय में ये तहारतें बनवा लीं जायं ?

श्री सम्पतराम : समय की अवधि अवश्य होनी चाहिये।

Page No.6

डॉ० चन्द्रकला : जो सार्वजनिक गन्दगी बढ़ रही है उसकी रोक-थाम के लिये नगर-पालिका क्या कर रही है ?

श्री सम्पतराम : इसके लिये नगर-पालिका सफाई सप्ताह मनाती है । उसके अलावा गटर लाइन ड्रेनेज आदि के बारे में यह विचार किया जा रहा है, इसको अन्डर ग्राउन्ड किया जाय । इसके लिये टेक्निकल ओपीनियन एक नहीं है इसलिये इसको पुख्ता तो नहीं कह सकते; लेकिन ये योजनायें चल रही हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि इन नालियों का क्या बच्चे, क्या बूढ़े तहारत के रूप में उपयोग लाते हैं, इस वजह से गन्दगी ज्यादा बढ़ रही है ? क्या नगरपालिका इस ओर भी कोई कदम उठा रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लिमिटेड कम्पनीज द्वारा धन-राशियों के गबन इत्यादि की शिकायतें

४१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Home Minister be pleased to state :-

(1) How many complaints were filed by limited companies for embezzlement and misappropriation of its funds and property in the city of Jaipur since 1957 ?

(2) How much amount is involved in all these cases ?

(3) How many cases have not been challaned in the court and for what reasons ? Please place a list of such cases.

(4) What steps were taken by the higher police authorities to expedite the investigation in the cases ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) Three only.

(2) The investigation conducted so far revealed it to be about Rs. 24,597/14/-.

(3) All the three cases are pending due to non-production of certain relevant record by complainants.

(4) The C. I. City has now been directed to take up the investigation of all the three cases and complete them as early as possible.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What steps did the police take for the production of these account books and relevant documents ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया कि इसकी इन्वेस्टीगेशन करने के लिए कह दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Has the police given any directions to the complainants that they should produce these documents ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दे दिया गया है ।

Page No.7

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As a matter of fact there is a complaint by the complainants that the police is shielding the accused and the cases are pending for last three years and challans are not being put up in the court.

श्री रामकिशोर व्यास : We have asked them to complete the cases as early as possible.

प्रश्न संख्या ४१८

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

गांधीनगर तथा बापूनगर (जयपुर) में प्रसूति गृह

४१९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की गांधीनगर व बापूनगर की बस्तियों में जिनकी आबादी लगभग १०,००० की है कोई प्रसूति गृह नहीं है ?

(ख) क्या सरकार वहां पर एक प्रसूति गृह खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसके खुल जाने की संभावना है ?

(ग) प्रसूति गृह कितनी आबादी पर खोला जाता ?

(घ) क्या सरकार को इस संबन्ध में कोई आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उसका उत्तर भी दिया गया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) प्रसूति गृह खोलने के आधारों की पूर्ति होने पर उस पर विचार किया जा सकता है।

(ग) कम से कम पांच हजार की आबादी पर।

(घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रसूति गृह खोलने के क्या आधार हैं ?

श्री भीखाभाई : एक आधार तो यह है कि पांच हजार की आबादी होनी चाहिये, दूसरा बिल्डिंग का प्रोवीज़न हो, स्टाफ क्वार्टर हों। अगर यह वहां की जनता देने के लिये तैयार हो या ६० हजार रुपये कॉंट्रीब्युशन का दें तो यह खुल सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जिस जगह पूरा भवन तैयार हो वहां आप खोलने के लिये तैयार हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आबादी तो दस हज़ार की है और भवन के लिये भी मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जावे तो आप विचार करेंगे ?

श्री भीखाभाई : प्रोग्राम के अनुसार खोल दी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पहाड़ी जिले में पूरा भवन निर्माण करके दिया गया और वहां की आबादी भी दस हजार से ऊपर है, फिर वहां क्यों नहीं खोला गया ?

श्री भीखाभाई : इससे सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न नहीं है। अलग से पूछें तो उत्तर दे सकूंगा।

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी पोलिसी मैटर से ही सम्बन्धित है। दस हजार की आबादी है, भवन तैयार है, तो इसके सम्बन्ध में ही है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कोलोनी के लोगों की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन भी आपके पास आया और उनको आपने अपने इस निर्णय से पत्र द्वारा सूचित कर दिया है ?

श्री भीखाभाई : रिप्रेज़ेन्टेशन आया, इसकी जानकारी नहीं है। पर जो जानकारी मेरे पास आई उसके अनुसार आदर्शनगर में एक डिस्पेन्सरी और खोल दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदर्शनगर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो बापूनगर और गांधीनगर की बात कह रहा हूं। वहां दस हजार की आबादी है। और जो रिप्रेज़ेन्टेशन हुआ इस कोलोनी की ओर से वह कब हुआ ? और इसके उत्तर में क्या आपने अपनी पॉलिसी से सूचित कर दिया है कि इतनी इतनी व्यवस्था और कर दी जावेगी तो प्रसूति गृह खोल सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपका प्रश्न इस प्रकार का नहीं था, वर्ना जानकारी करके ही आता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न पूरा अच्छी तरह से आपने पढ़ा होता तो आपको यह कहने का मौका नहीं मिलता। मैंने पूछा है कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई, क्या उसका उत्तर भी दिया गया ? यह स्पेसिफिकली पूछी है उत्तर देने की बात, क्योंकि सरकार उत्तर देने तक की कर्टसी करती नहीं कि किसी के पत्र का जवाब तो दिया जाय।

श्री भीखाभाई : इसका भी जवाब दे दिया है, 'जी नहीं।'

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४२०

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

सब इन्सपेक्टर, पुलिस चिड़ावा द्वारा श्रीमती तारामनी देवी के साथ बलात्कार

४२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) :

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्री शिवलाल सिंह ने थाना चिड़ावा की नियुक्ति के समय श्रीमती तारामनी देवी के फरार किये जाने के मुकद्दमा नम्बर ५ दफा ३६३।३६६ आइ. पी. सी. तारीख ३-३-५८ की तफ-तीश की थी ?

(ख) क्या यह सही है कि दौरान तफ-तीश उक्त थानेदार ने १५,१६ मार्च, १६५८ की रात को बगड़ में तारामनी देवी के साथ बलात्कार किया जिसकी शिकायत उसने मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री को भी की है ?

(ग) क्या यह सही है कि थानेदार ने मुलजिमान से मिलकर तफतीश में कई प्रकार की खामियां रख दीं तथा असली मुलजिमान को मामले में शामिल नहीं किया ?

(घ) क्या यह सही है कि शिवलालसिंह ने दौरान तफतीश चिड़ावा से सीकर एक व्यक्ति महावीर प्रसाद के खर्चे पर यात्रा की परन्तु सरकार से द्वितीय क्लास का किराया वसूल किया ?

(ङ) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों की पुलिस विभाग द्वारा जांच की गई तो उपरोक्त बातें जांच पर सही साबित हुई तथा इस जांच में इन तथ्यों के अलावा और भी हुई अनियमितताएं इसके विरुद्ध साबित हुई ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(च) उपरोक्त मामलों पर एस. आई. को विभाग द्वारा क्या चार्ज शीट दिया गया तथा अन्तिम रूप से इस जांच का क्या परिणाम रहा ? कृपया चार्जशीट एवं इन्क्वायरी की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(छ) उपरोक्त मामलों में एस. आई. को क्या सजा दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, ऐसी ही शिकायत की गई थी।

(ग) अभी जांच की जा रही है, अतः कुछ नहीं कहा जा सकता।

(घ) अभी जांच जारी है।

(ङ) पुलिस विभाग द्वारा जांच की गई, जो आरोप लगाये उनमें से कुछ प्रमाणित नहीं हुए। अपील करने पर जांच रद्द कर दी गई।

(च) इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। जांच अभी जारी है।

(छ) जांच जारी है।

श्री भैरोंसिंह : जो आरोप कुछ हद तक प्रमाणित हुए हैं तो क्या इनमें यह भी प्रमाणित हुआ है कि बलात्कार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : बलात्कार साबित नहीं माने, और चार्ज माने।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

कि जांच के दौरान फिर गलत माना बलात्कार का चार्ज सरकार ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार के मानने का सवाल नहीं। एन्क्वायरी अफसर के सामने यह चार्ज प्रूव नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उक्त सब इन्सपेक्टर को सजा दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है कि आई. जी. पी. साहब ने ६ महीने का रिडक्शन उसकी हैड कान्स्टेबल की सर्विस में किया और सस्पेन्शन पीरियड का ३।४ अमाउन्ट फोर्फीट कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सजा इस कारण से दी गई थी कि चार्ज शीट में यह भी चार्ज था कि तुमने फलां फलां तारीख को इसके साथ इस इस तरह का दुर्व्यवहार किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी चार्ज था, पर जांच के दौरान और भी पांच-सात चार्जेज़ थे और चार्ज उसके एप्रूव्ड हो गये थे। यह चार्ज नहीं हुआ !

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि यह चार्ज उसको सुना तो दिया पर इस पर जोर नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि रेप का चार्ज था उसे एन्क्वायरी ऑफिसर ने प्रूव नहीं माना और बाकी इर्रेगुलेरिटी प्रूव्ड मानी और इसके लिए उसको ६ महीने की रिडक्शन की सजा मिली हैड कान्स्टेबल की सर्विस में और सस्पेन्शन पीरियड का ३।४ फोर्फीट कर लिया। मैं फर्दर आपको और इत्तला दे दूं कि इसकी उसने अपील की, कागज़ पी. एस. सी. में गये। वहां सब सजा को सैट असाइड कर दिया गया और दुबारा इन्क्वायरी के लिए कहा। अब दुबारा एन्क्वायरी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : : क्या यह सही है कि डी. आई. जी. हल्का ने जांच की थी और बलात्कार का आरोप सही माना था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जब एक बार उन्होंने बता दिया कि एन्क्वायरी अफसर ने इसको प्रूव्ड नहीं माना। अब अमुक अफसर ने क्या किया और अमुक ने क्या नहीं, इससे क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है साहब, इन्क्वायरी कई बार हुई है। किस एन्क्वायरी का कब क्या नतीजा निकला, यह मैं पूछ रहा हूं और अभी तक मामला पेन्डिंग में है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बलात्कार के चार्ज का मामला भी पेंडिंग में हैं ?

श्री अध्यक्ष : सारी चीजें वापिस आई हैं। सारा केस फिर से जांच में जावेगा, ऐसा मन्त्री महोदय ने बताया है। सारा केस पी. एस. सी. से वापिस जांच कराने के लिए आया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह चार्ज भी वापिस आया जो इन्क्वायरी से गलत माना गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डी. ई. तो एक ही हुई है, कई डी. ई. नहीं हुई हैं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

इसी की फाइन्डिंग हुई और इसी पर सजा तजवीज़ हुई। इस पर अब पी. एस. सी. के आदेश के कारण दुबारा जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस इन्क्वायरी पर सरकार के विभाग ने सजा दी उस विभाग ने इस बलात्कार के मामले में मजिस्ट्रेट के बयान नहीं लिये थे और इस कारण से पी. एस. सी. के कागजात एन्क्वायरी के लिए वापिस आये हैं, अब विभाग ने मन्जूर कर लिया कि बलात्कार किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर जिले के कृषकों हेतु लोहे तथा इस्पात का कोटा

४२३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर जिले में लोहा व इस्पात का कितना कोटा कृषकों के लिए १ जुलाई, १९५९ से आज तक दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि टिन शीट्स का कोई कोटा उक्त अर्से में नहीं दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (क) बीकानेर जिले को १ जुलाई, १९५९ से ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले समय में ४२४ टन लोहे व इस्पात का कोटा कृषकों के उपयोग के लिए अलॉट किया गया है।

(ख) जी, हां। उक्त समय में बीकानेर जिले को ४२४ टन लोहे व इस्पात के कोटे में से निम्नलिखित परिमाण में चद्दरों का कोटा अलॉट किया गया है।

नालीदार चद्दरें	२६० टन
प्लेन चद्दरें	२० टन
काली प्लेन चद्दरें	२० टन

श्री भीमसेन : मांग के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर आप यह कोटा निर्धारित करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कृषक जन-संख्या के आधार पर देते हैं।

स्त्रियों के भ्रष्टाचार की रोक

४२४. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : Will the Home Minister be pleased to State:—

(a) Is it a fact that a section has been created in the women organisation of the C. I. D. for the prevention of immoral traffic in women ? If so, when and under whose orders ?

(b) Whether is it a fact that new hands were to be recruited for this section ? If so, whether the orders were complied with ? If not, then why ?

(c) How many women working in this organisation were transferred to this section and on what posts ? Please lay a list of such women with posts they held in and the length of their service.

(श्री भैरोंसिंह)

(d) What has been the result of this organisation in the prevention of the immoral traffic ? Please state the number of ultimate result of the cases which have been detected or reported by this roganisation.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) No. Some posts for the purpose were created in the District budget and not in the C. I. D. budget of the Police Department for Jaipur City only.

(b) No.

(c) The following women were transferred:-

Name.	Rank.	Length of service yrs. Months.	
1. Miss Sharda Varma	S. I.	4	10
2. Smt. Sushil Varma	H. C.	4	9
3. Smt. Raj Dulari	Constable	(Now no more in Police Deptt)	
4. Smt. Narbada Devi	Constable	2	–
5. Smt. Sarju Devi	Constable	2	–

They were all transferred from C. I. D.

(d) 18 cases of immoral traffic were registered in District Jaipur out of which 12 cases were challaned in the court, one case is under investigation and final report has been given in five cases. Out of the cases challaned, six ended in discharge and six are pending trial.

Two complaints were also instituted under Section 17 of Suppression of Immoral Traffic Act in District Jaipur, of which one resulted in acquittal on appeal and the other is pending trial.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

चराई की दर को वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण

४२५. श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) : Will the Forest Minister be pleased to state:-

1. Did the Government appoint a Committee to go into the question of Rationalisation of Grazing Rates in the State ?

2. If so, has the Committee submitted its report to the Government ?

3. If yes, when will the Government take decision on its recommendations and enforce them in the State ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
1. Yes.

2. Yes.

(श्री सम्पतराम)

3. The report is under consideration of Government.

पुलिस थाना बगडी के क्षेत्र में सन् १९५८ से हुई चोरियां

४२६. श्री चेनाराम गहलोत (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५८ से लेकर अब तक बगड़ी पुलिस थाना के अन्तर्गत कितनी चोरियां कैसी-कैसी कितने कितने की, किस किसके हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) उपरोक्त चोरियों को बरामद करने हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई और कितनी व कौन कौनसी चोरियां बरामद की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) (क और ख) : जनवरी सन् ५८ से १ जुलाई ६० तक पुलिस स्टेशन बगड़ी में चोरी के ३० मुकद्मे दर्ज हुए जिनमें १४६६० का माल चोरी गया व २०२२।।) रु० का माल बरामद हुआ; इसमें १४ नकबजनी, १३ पशु चोरी व ३ सादा सरका है। मुलजिमान व माल मसरूका का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई।

बांसवाड़ा जिले के मुत्तिअल पुलिस कर्मचारी

४२७. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) बांसवाडा जिले के पुलिस स्टेशनों के किन थानों के किन किन थानेदारों को तथा हैड कॉन्स्टेबलों को सन् १९५७-५८, ५८-५९, व ५९-६० में मुअत्तिल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया था उनकी विभागीय जांच समाप्त न होने के पहले ड्यूटी पर लिया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) श्री अब्दुल रजाक	२२-४-५८
श्री कानाराम	८-१०-५७
श्री हैदरअली	२०-१-५८
श्री लाल मोहम्मद	४—३-५८
श्री जयसिंह	१०-६-५८
श्री रशीद अहमद	१४-१०-५८
श्री विक्रमसिंह	२२-६-५९
श्री नानालाल	४-१२-५९
श्री मांगीलाल	५-१२-५९
श्री जयसिंह	२१-१-६०
श्री शंकरलाल	७—३-६०
श्री मुश्ताक हुसैन	७—३-६०

(ख) केवल श्री विक्रमसिंह बी० जे० को विभागीय जांच समाप्त होने के पूर्व ही ड्युटी पर ले लिया गया।

श्री मोगजी भाई : क्या शंकरलाल थानेदार को मई ६० में ड्युटी पर लिया गया था ?

Page No.14

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बतलाया; केवल विक्रमसिंह को लिया गया, और किसी को नहीं लिया गया।

जयपुर नगर की गटर लाइन

४२८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जयपुर शहर में गटर लाइन की सफाई के लिये कुल कितने गैस नाशक व पानी खींचने की मशीनें हैं ? क्या ये सामान पर्याप्त है ?

(२) गटर लाइन की सफाई करते हुए पिछले साल भर में जयपुर शहर में कितने कर्मचारी मर गये और कितने बेहोश हुए जिन्हें अस्पताल भेजना पड़ा ? क्या यह सही है कि इन दुर्घटनाओं का कारण पर्याप्त औजारों का न होना है ?

(३) जयपुर शहर में गटर लाइन की सफाई का स्टाक कितना है ? क्या यह संख्या कम नहीं है ? क्या काम को देखते हुए इस संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जावेगी ?

(४) गटर लाइन की सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को कुल कितना वेतन किस ग्रेड के अनुसार मिलता है ? इसकी कितनी सालाना तरक्की होती है ?

(५) क्या गटर लाइन पर काम करने वाले हरिजन कर्मचारियों को स्थायी ही रखा जाता है अन्य सेवाओं की भांति यहां भी परमानेन्ट करने का कोई नियम क्यों नहीं है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं।

(२) गत वर्ष में कोई कर्मचारी नहीं मरा। दो आदमी बेहोश हो गये थे जो एक दो दिन में ही ठीक हो गये। इनकी बेहोशी का कारण औजारों की कमी नहीं थी बल्कि जल्दबाजी में वे लोग गैस निकलने से पूर्व मेनहॉल में प्रवेश कर गये थे। सीवर लाइन की सफाई व मेन हॉल की सफाई में समुचित साधन सीवर किलिन्ग रॉड्स आदि उनको आवश्यकतानुसार दिये जाते हैं।

(३) गटर लाइन की सफाई करने वालों की कुल संख्या ५१ है, जी नहीं। यदि उचित समझी जावेगी।

(४) गटर लाइन की सफाई करने वाले कर्मचारियों को २५–१–४० की ग्रेड में वेतन दिया जाता है। गटर में कार्य करने का ५)रु. अतिरिक्त अलाउन्स भी दिया जाता है। सालाना वृद्धि एक रुपया मासिक होता है।

(५) सीवर गैंग स्थायी गैंग है। इसमें कार्य करने वाले स्थायी ही समझे जाते हैं तथा सेवाओं के अनुसार ही गैंग के कर्मचारियों को परमानेन्ट करने के नियम हैं।

डॉ० चन्द्रकला : आपने क्या कहा, नियम नहीं हैं ?

श्री सम्पतराम : नियम हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस सम्बन्ध में इन कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल मंत्री महोदय से मिला था ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : तो उस पर क्या मंत्री महोदय ने यह महसूस नहीं किया कि जो सामान है वह पर्याप्त नहीं है और इनको और अधिक सामान और सुविधा देने की आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम : महसूस किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

स्पेशल केसेज में पुलिस जांच

४२६. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि स्पेशल केसेज़ की जांच पुलिस में सी० आई० से नहीं कराने का नियम है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में भीमपुरा एन्काउन्टर केस की तफतीश सब इन्सपेक्टर, काछोला से कराई गई थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री शिवचरणदास : यह जांच किस रेंक के ऑफिसर से कराई जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास: कौन से मुकद्दमे की जांच ?

श्री शिवचरणदास : स्पेशल केसेज़ की जांच कौन से रेंक तक के अफसरान से कराने का नियम है ?

श्री रामकिशोर व्यास: आपका सवाल तो यह था कि 'क्या यह सही है कि स्पेशल केसेज़ की जांच पुलिस में सी० आई० से नहीं कराने का नियम है ?'

श्री शिवचरणदास : मेरा ओरीजिनल प्रश्न जो था वह यह नहीं है, शायद इसमें गलत प्रिन्ट हो गया है। मेरा प्रश्न था कि 'क्या यह सही है कि स्पेशल केसेज़ की जांच सी० आई० से कम दर्जे के अफसरान से नहीं कराई जाती है', तो अब मैं आपको सप्लीमेन्टरी पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे दीजिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर देता हूं। स्पेशल केसेज़ जो होते हैं उनमें सी० आई० से जांच करा सकते हैं लेकिन उसके लिए डी० एस० पी० को मौके पर जाना पड़ता है और उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है।

श्री शिवचरणदास : तो क्या इस भीमपुरा वाले केस के अन्दर केस की जांच के लिए डी० एस० पी० गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस केस में कौन—कौन गये थे, यह तो मेरे लिए कहना सम्भव नहीं है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि इस केस की जांच डी० एस० पी० से इसलिए नहीं कराई गई थी कि एस० पी० गुप्ता के विरुद्ध भीमपुरा के रेप केस की शिकायत थी और उसको छिपाने के लिए सी० आई० से यह जांच कराई गई थी ?

Page No.16

श्री रामकिशोर व्यास : छिपाने का सवाल नहीं है। नॉर्मल कोर्स में जिनका फंक्शन है वही जांच करते हैं।

श्री शिवचरणदास : इस केस में नियमानुसार जांच हुई थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : नियमानुसार ही होती है। जब तक कि आप कोई अनियमितता नहीं बतायेंगे तब तक कैसे मालूम होगा ?

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि इस केस के प्रारम्भ में प्रधान मंत्री के सामने उस औरत ने एक एप्लीकेशन देकर शिकायत की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

जोड़ बीड़, बीकानेर

४३०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या जोड़ बीड़, जिला बीकानेर पशुओं के लिए चरने के लिए खुला है ? अगर हां, तो चराई की दरें क्या हैं ?

(२) क्या सरकार ने हाल ही चराई की दरें बढ़ाई हैं और उन बढ़ाई हुई दरों के सम्बन्ध में ग्रामीणों ने एतराज किया है कि ये दरें उनके सामर्थ्य से बाहर हैं ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। चराई की दरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सूचना दी है कि रेट्स बढ़ाई नहीं गई हैं और वे बहुत बढ़ी हुई हैं और अब तक जो वसूल होती रही हैं वे बहुत कम रेट्स थी ?

श्री सम्पतराम : आपके पास तो स्टेटमेन्ट पहुँच गया है।

श्री भीमसेन : जी हां।

श्री सम्पतराम : पहले रेट ३ आना थी उसका २ रु० ४ आना सालाना होता था उसका हमने २) रु० किया, जो पहले ४ आना थी उसका हमने ३ रु० किया, वह भी ठीक है १ आना थी उसके १२ आने सालाना होते थे उसका हमने १) रु० किया है। तो कहीं तो स्लाइटली बढ़ोतरी हुई है तो कहीं कमी भी हुई है, लेकिन ओवरऑल हमने बढ़ाया नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि सरकार ने ग्रेजिंग को दो ब्लॉकों में बांटा है, एक तो रोडो ब्लॉक और दूसरे बड़े ब्लॉक और ये पहले नहीं थे ?

श्री सम्पतराम : यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन जैसी ग्रेजिंग की पोज़ीशन थी उसके मुताबिक रेटस फिक्स की गई थीं।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

सिटी बस सर्विस, जयपुर

४३१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जयपुर शहर में कितने रूट्स पर सिटी बस सर्विस चालू है ? ये बसें किन-किन बस्तियों में होकर जाती हैं ?

(२) क्या यह सच है कि शहर के विस्तार को देखते हुए ये रूट्स अपर्याप्त हैं ?

(३) क्या जनता की सुविधा की दृष्टि से और रास्तों पर भी बस सर्विस चालू की जायेगी ? यदि हां, तो किस-किस रास्ते पर कब-कब से ?

(४) अजमेर दरवाजे या चांदपोल गेट से जमना डेयरी को जो बस सर्विस चालू की गई थी वह बन्द क्यों कर दी गई ? पुन: चालू करने की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या उसे जल्दी से जल्दी चालू किया जायेगा ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सिटी बस सर्विस के निम्न-लिखित दो मार्ग हैं :

(क) सांगानेरी गेट से आदर्शनगर व

(ख) चांदपोल गेट से झोटवाड़ा।

(२) अपर्याप्त सर्विस की कोई शिकायत नहीं आई।

(३) जनता के मांग लेने से मांग आने पर विचार किया जा सकता है।

(४) अस्थायी पर्मिट की मयाद समाप्त हो जाने से सर्विस बन्द हो गई थी। पर अब स्थाई पर्मिट दे दिये गये हैं, बसें जल्दी ही चालू हो जायेंगी ?

डॉ० चन्द्रकला : यह मांग किस तरह से आयेगी ताकि उनको मालूम हो कि बसें चलाने की जरूरत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आर. टी. ओ. के सामने दरख्वास्तें दी जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि आर. टी. ओ. के सामने एक बस को थोड़ा आगे बढ़ाने की दरख्वास्त दी हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह पेन्डिंग होगी। मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने कहा कि जनता की तरफ से मांग नहीं आई है तो उसके लिये भी तो जनता की तरफ से मांग गई है, तो अब आपको जानकारी नहीं है तो कैसे मालूम है ?

श्री रामकिसोर व्यास : आर.टी.ओ. तो कन्सीडर करके पर्मिट देगा।

डॉ० चन्द्रकला : चांदपोल दरवाजे से जो जमना डेरी की तरफ बस जाती थी इसका पर्मिट पूरा हो गया तो इसको बन्द कर दिया गया तो उसको आगे चलाने की जरूरत क्या सरकार ने नहीं समझी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका तो टेम्पोरेरी पर्मिट था और उसकी आगे जरूरत नहीं समझ कर रिन्यू नहीं किया होगा।

डॉ० चन्द्रकला : शुरू में तो टेम्पोरेरी ही देते हैं लेकिन आवश्यकता समझते हैं तो परमानेन्ट कर देते हैं तो इस रूट पर परमानेन्ट करने की जरूरत सरकार ने नहीं समझी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार को समझने की जरूरत नहीं है। वह तो आर. टी. ओ. ही पर्मिट देता है। हम तो कहीं पिक्चर में ही नहीं आते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इतने बड़े जयपुर शहर में केवल दो रूट्स पर ही बस चलाना क्या जयपुर शहर की जनता के लिए पर्याप्त है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे ख्याल से बढ़ाने की गुंजाइश है लेकिन प्रोसीजर यह है कि एप्लीकेशन आर. टी. ओ. को दी जायें और वे पर्मिट इश्यू करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या जनता की जरूरतों को देखते हुए सरकार कोई रिटन परमिशन आर. टी. ओ. को दे सकती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ओपन में राइटिंग में देना ठीक नहीं है ! अगर वह रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर हमको लिख सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : If the Government feels that the traffic in a particular area demands bus service, is the Government entitled to give a direction to the R. T. A. to permit services on that route ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मोटर विहीकल एक्ट में दिया हुआ है, जो भी पोज़ीशन है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन जब कि सरकार यातायात का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है और अब लोग आकर एप्लाई करें, इससे तो अच्छा तो यह था सरकार अपनी बसें चलाए।

श्री रामकिशोर व्यास : राष्ट्रीयकरण का सवाल सिटी के लिए नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : जिन रूट्स पर आपने पर्मिट नहीं दिये हैं उन रूट्स पर आप अपनी बसें क्यों नहीं चलाते ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजना नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी जो बसें अनयूज्ड पड़ी हैं उनको युटिलाइज़ क्यों नहीं करते; जैसे सांगानेरी गेट से मिर्जा इस्माइल रोड पर और ऐसे ही दूसरे रूट्स पर क्यों नहीं अपनी बसों को चलाते ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे और ओपरेटर्स को रूट्स के लिए एप्लाई करना पड़ता है उसी तरह गवर्नमेंट को भी एप्लाई करना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : सिटी के लिए एप्लाई किया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी के लिए हमारी नीति नहीं है।

पंचायत कटेडा में धर्मार्थ रकम की वसूली

४३२. **श्री शिवचरणदास** (मान्डल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भीलवाड़ा तहसील मांडल की करेडा पंचायत में धर्मादे के नाम से इन दो सालों में किस किस व्यक्ति से कितनी रकम वसूल की गई? तारीख वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या पंचायत का यह रकम वसूल करना वैधानिक है? यदि हां, तो कैसे?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रकम उन्हीं व्यक्तियों से वसूल की गई है जिनके पंचायत में केसेज पेंडिंग थे? यदि नहीं, तो सूची में वे कौनसे व्यक्ति हैं जिनके केसेज पेंडिंग नहीं थे?

(घ) उक्त वसूल शुदा धर्मादे की रकम को कहां, किस मद में जमा की गई और किस मद में किस प्रकार खर्च की गई?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है इसलिए इसका जवाब आगे दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

सरकारी नियमों, आज्ञाओं एवं विज्ञप्तियों का पुस्तकाकार प्रकाशन

४३३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

केन्द्रीय तथा राजस्थान राज्य के कानूनों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अथवा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बनाये नियमों, आज्ञाओं एवं विज्ञप्तियों को पुस्तकाकार में प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? उपरोक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और यह कार्य कब तक सम्पूर्ण कर लिया जायेगा?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): राजस्थान के कानूनों के अन्तर्गत सरकार द्वारा तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियमों का सन् १९४९ से १९५४ तक संकलन करके प्रथम पुस्तकाकार (कोड) मुद्रण विभाग को छपवाने के हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस पुस्तकाकार (कोड) में ८० मुख्य नियम हैं। इस प्रकार कोड केन्द्र के सन् १८६०-१९६० तक व राजस्थान राज्य के कानूनों सन् १९५५ से १९६० के अन्तर्गत बने नियमों आदि को पांच और भागों में छपवाने के हेतु संकलन किया जा रहा है, जो समय-समय पर पूरा होने पर छपवाये जाते रहेंगे।

श्री भीमसेन : यह पुस्तकाकार में कब तक छप जायेगा?

श्री रामकिशोर व्यास: प्रेस में भेजा है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि व्यक्तिगत एफर्ट्स से किसी वकील ने ऐसा प्रकाशन निकाला है तो समझ में नहीं आता कि सरकार की तरफ से देरी क्यों हुई है?

श्री रामकिशोर व्यास: प्राइवेट निकाल सकते हैं, उसके लिए मनाई थोड़ी ही है।

प्रश्न संख्या ४३४

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह!

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३५

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री पुरुषोतमलाल।

Page No.20

किशनगढ़ के पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन–व्यवस्था

४३६. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा [किशनगढ़–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या किशनगढ़ के पुलिस स्टेशन मदनगंज व सिटी कोतवाली, किशनगढ़ से टेलीफोन हटा दिये गये हैं ?

(२) अगर हां, तो क्यों तथा क्या सरकार इन दोनों जगह टेलीफोन वापिस लगाने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां,क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला हैडक्वार्टर्स पर स्थित थानों के अलावा दीगर थानों में टेलीफोन आम तौर से नहीं रखा जाय। यदि आई० जी० पी० कानून तथा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी खास थाने पर टेलीफोन रखने की सिफारिश करें तो वहां टेलीफोन रखने का, वस्तुस्थिति को देख कर, निर्णय लिया जाय।

(ख) प्रश्न आई० जी० पी० महोदय के विचाराधीन है। तथा उस पर सरकार का निर्णय न हो तब तक के लिए वहां टेलीफोन पुनः लगा दिए जाने के आदेश आयुक्त महोदय ने जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

४३७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

1. Has the Government planned to construct roads in Rajasthan Canal Project area ?

2. If so, which roads have been planned to be constructed in that area so far ?

3. If not, how long will it take to formulate plans of road construction in this area ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (१) राजस्थान नहर द्वारा सिंचक योग्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विकास का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें सड़कों सम्बन्धी स्थूल योजना भी सम्मिलित है। मास्टर प्लान आयोजना आयोग के विचाराधीन है और उसको अन्तिम रूप आयोग से विचार-विमर्श करने के बाद दिया जाना है।

(२) राजस्थान नहर क्षेत्र में।

(३) सड़कों का सविस्तार निदर्शन उक्त नहर की प्रत्येक शाखा और उपशाखा द्वारा सिंचन योग्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग बनाये जाने वाले उप प्रादेशिक प्लानों में किया जायगा। अब तक केवल नौरंगदेसर और रावतसर उपशाखा क्षेत्रों, जिनमें कि सिंचाई शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है। निकटवर्ती सड़कों को ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और उनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं :—

१. रावतसर से पीलीबंगा तक सड़क।

२. रावतसर से नौहर तक सड़क।

Page No.21

(श्री दौलतराम सारण)

३. सूरतगढ़ से विर्धवाल तक सड़क ।

४. हनुमानगढ़ से टिब्बी होते हुए तलवाड़ा तक राजस्थान नहर से मिलती हुई सड़क ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि लूणकरणसर से सूरतगढ़ की सड़क राजस्थान नहर की तरफ से होकर बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया था, लेकिन अब वापस बन्द कर दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय मेरे पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के चौधरी ।

चोरियों व डकैतियों के रजिस्टर हुए मामले

४३८. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :—

(1) How many cases of theft and dacoities were registered in the State during last three years ? Figures for each year may be given separately.

(2) In how many of these cases the culprits were apprehended, challaned and convicted.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(1)	1957	1958	1959
Thefts	10212	10538	11366
Dacoities	61	75	81

2. Culprits were arrested in 9351 cases, challaned in 8647 cases and convicted in 3979 cases.

श्री पी० के० चौधरी : यह जो आपके रेट ऑफ थेफ्ट्स एन्ड डेकोइटीज़ हैं उनमें इन्क्रीज़ क्यों हुआ है और आपका जो चालान है थेफ्ट एन्ड रजिस्टर्ड और कन्विक्शन का, इसमें इस प्रकार की वाइड डिस्पैरिटी क्यों है ? नौ हजार रजिस्टर्ड हुए और तीन हजार का कन्विक्शन हुआ, इसका कारण क्या है ।

श्री रामकिशोर व्यास : फिगर्स हमेशा बराबर नहीं होते । पांच-सात का फर्क तो रहता ही है; कभी कम, कभी ज्यादा हो जाते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, there is something basically wrong with them.

श्री रामकिशोर व्यास : आपने डेकोइटीज़ वगैरह के विषय में पूछा है । हमेशा एक ही फिगर तो नहीं आता है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह जो आपने थेफ्ट के लिए बताया कि ५७ में दस हजार और ५८ में दस हजार और ५९ में ग्यारह हजार, तो लगभग ३१००० केसेज़ हैं जिनमें से कुल नौ हजार ही रजिस्टर्ड हुए ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो थेफ्ट की बात है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह नौ हजार जो आपने फिगर्स दिए हैं वे कौन से साल के हैं ?

Page No.22

श्री रामकिशोर व्यास: टोटल दिए हैं।

श्री पी० के० चौधरी : इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ५७ में दस हजार और ५८ में दस हजार और ५९ में ग्यारह हजार कुल मिला कर ३१००० केसेज़ हुए, जिनमें से आप कुल ६००० ही बताते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग बात है। आप और पूछ लीजिए मैं आपको इन्फोर्मेशन दे दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल साफ मामला है। ३१००० केसेस रजिस्टर्ड हुए, and only in 9000 cases they were able to apprehend the culprits, challaned in 8000 cases and convicted only 3,000. Out of 31,000 cases the prosecuting department was able to produce evidence only in 3000 cases.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो हैं सो तो है ही, अब आप इनका कुछ भी कनक्लूज़न निकाल लीजिए।

श्री पी० के० चौधरी : फीगर्स तो ठीक हैं, but does it not show that there is something basically wrong with your investigation methods. Whether you agree with that or not that is a different matter, but if you agree, in that case whether you want to enquire as to what is the procedural defect with the investigation branch. Why there is such a drawback ?

श्री रामकिशोर व्यास : We will look into it.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

दन्त चिकित्सालय

४३९. **श्री मूलचन्द डागा** [(पाली-डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन जगहों पर दांत के अलग अस्पताल हैं और वे किन आधारों पर खोले गये हैं ?

(२) क्या इन अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है ? यदि हां, तो किन किन अस्पतालों को और कितनी कितनी ?

(३) क्या इस प्रकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कोई दांतों का अस्पताल पाली में भी खोला गया है ? यदि हां, तो कब से और उस पर क्या खर्चा किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान में दांतों के कोई अलग अस्पताल नहीं हैं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हटीला की हत्या का मामला

४४०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Home Minister be pleased to state :—

1. Did the Government institute an enquiry into the Hatila murder

(श्री श्रीमानसिंह)

case in the police custody at Bayana in Bharatpur District ?

2. If so, has the enquiry been completed ? If yes, what are the findings ? Please lay a copy of the report on the Table of the House.

3. Who was the Police Officer implicated in the murder case ? Was he suspended during the continuance of the enquiry or did he continue to stay at the same post in Bayana ?

4. If these police officers involved in this case were not suspended, then did they produce Hatila at any stage before the enquiry officer ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
1. Yes.

2. No.

3. Shri Kishan Gopal Gupta was the S. H. O. of P. S. Bayana. He has not been suspended, but he was transferred from there before the commencement of the enquiry.

4. No. The case is sub-judice.

बनास बांध

४४१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बिसलपुर तहसील देवली, जिला टौंक में बनास का बांध बंध रहा है ? अगर, हां, तो किस स्थान पर और कितनी लागत का तथा इससे इस बांध का कितना कितना केचमेंट एरिया होगा तथा इससे कितनी आबपाशी होगी ?

(ख) क्या यह सही है कि उस बांध में बड़े बड़े ग्राम व कस्बे डूब में आवेंगे ? यदि हां, तो कौन कौन से ग्राम और उनका कितना कितना कम्पेन्सेशन सरकार को देना पड़ेगा ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बनास का बांध जिला भीलवाड़ा ग्राम अमरगढ़ के पास भी बांधने की योजना है। अगर हां, तो किस स्थान पर ?

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य हर दो जगह पूरा हो चुका है ? अगर हां तो तो अब तक कितनी कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(ङ) क्या उपरोक्त बांधों से जो बनास में जो बाडीया, खरबूजा, तरबूज, बैंगन, कान्दा, आलुखात लिया हो तो क्या उनमें कोई न्यूनता या उन्नति होगी।

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) :
(क) बनास नदी पर ग्राम बिसलपुर, तहसील देवली के भाग बनास के ऊपर बांध बांधने के लिए भूमापन व अनुसंधान किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत करीब ७.५० करोड़ रुपये होगी। इसका केचमेन्ट एरिया बिसलपुर पर १०, १४२ वर्ग मील है इससे २,००,००० लाख एकड़ भूमि की आबपाशी होगी।

(ख) जी हां, इस बांध के बनने से काफी गांव डूब में आवेंगे जिनकी सूची इसके साथ

Page No.24

(श्री दौलतराम सारण)

संलग्न है। कम्पन्सेशन का तखमीना बनाया जा रहा है जिसके पूरा होने पर ही मुआवजे की रकम का पता लग सकेगा।

(ग) जी हां, इसका भूमापन व अनुसंधान भीलवाड़ा ग्राम अमरपुरा व खासुन्दा पर भी किया गया था, बांध दोनों में से एक ही जगह पर बांधा जायेगा।

(घ) जी हां, इसके अनुसंधान का कार्य दो जगह, यानी अमरपुरा व खासुन्दा पर हो चुका है।

(ङ) सम्भव है कि बांध बंधने से बनास का हमेशा चलता हुआ पानी कम हो जायगा और इसलिए शायद इस तरह की खेती में कुछ न्यूनता आ जावे।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि बनास का बांध बंधने से जो हमारी परमानेंट आमदनी आती थी, मैं, यह निवेदन करूं कि जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है उस वक्त इस बात का आधार ले लिया जाता है या नहीं कि मौजूदा जो आमदनी होती है, ऐसी मौजूदा जो बड़ी २ नदियां बनास आदि, इनमें जो आमदनी अभी हो रही है, उसके मुकाबले में बांध बंध जाने से आमदनी न्यूनतम तो नहीं हो जायेगी।

श्री भीखाभाई : जी हां, बांध बंधने से बहुत ज्यादा आमदनी होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस वक्त बहुत ज्यादा आमदनी है या उस वक्त हो जायेगी। आपने कोई इस तरह के आंकड़े एकत्रित किए हैं।

श्री भीखाभाई : आमदनी तरबूज या बाड़ीया की हो, यह अच्छा है कि अनाज का उत्पादन ज्यादा बढ़े इससे माननीय सदस्य खुश हैं। बांध बंध जाने से दो लाख एकड़ भूमि का सिंचन होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि बनास जहां से चली है और जहां बनास का अंत होगा वहां तक अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है या नहीं, मैं तरबूजों की बात नहीं कर रहा।

श्री भीखाभाई : इससे पहले ही अभी अर्ज किया कि कुछ न्यूनता हो सकती है लेकिन आगे जाकर उससे काफी लाभ होने वाला है, जो लाभ आज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा लाभ बनास का बांध बंध जाने से होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इस तरह का भी अनुसंधान हो रहा है या नहीं कि यह बांध उदयपुर डिविज़न में बनाया जायगा या टोंक डिस्ट्रिक्ट में।

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे अर्ज किया कि कई जगहों पर सर्वे हो रहा है जैसे कि आपके कैकड़, अमरपुरा और एक जगह है घोरिया। वहां पर सूटेबिलिटी होगी वहीं पर बांध को बांधना होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जैसा कि आपने फरमाया कि इसमें बहुत से गांव डूब में आवेंगे तो क्या इस बात का भी ध्यान

Page No.25

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इन गांवों को और दूसरी जगह आबाद करके ही कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाय ।

श्री भीखाभाई : जी हां, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर प्रोजेक्ट में और इसमें भी गोगुन्दा के अन्दर बहुत से गांव सबमर्ज होते थे, तो वहां पर रोक लिया गया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ध्यान की बात नहीं है । बहुत से इन्स्टान्सेज़ मौजूद हैं कि बान्ध बन चुके हैं और उन लोगों को जमीन नहीं मिली है । पहले सरकार उन बस्तियों को बसा कर फिर कन्स्ट्रक्शन शुरू करे ।

श्री भीखाभाई : जी हां, इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर फाइनल हो जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अनुसंधान की बात आपने कही तो अनुसंधान हो रहा है उसके पहले ही आपने बता दी कि लागत इतनी लगेगी तो बिना अनुसंधान के लागत कैसे फिक्स कर दी ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को इन्वेस्टीगेशन और सर्वे का ध्यान नहीं है । वह अलग अलग स्टेज पर होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको खुद को यह ध्यान नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि अनुसंधान हो रहा है कि कहां पर बान्ध बनेगा और आप बतला चुके हैं कि कितनी लागत लगेगी । बांध बनने के बाद तो यह सोचा जा सकता है, लेकिन उसके पहले ही कैसे अन्दाज लगा लिया ?

श्री भीखाभाई : इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर बहुत सी बातें शामिल हैं, सर्वे भी शामिल है, फाउन्डेन्शन भी शामिल है, हाइड्रोलोजिकल डेटा भी शामिल हैं और मैंने निवेदन किया है कि इसका फाउन्डेशन और इन्वेस्टीगेशन करके उसका एस्टीमेट बनाया गया कि कितने स्टेज में होगा और कितनी लागत होगी, यह बतलाया गया है । उसके साथ साथ यह बताने की जरूरत है माइनर इर्रिगेशन में कि ओवरफ्लो होता है, अगर होता है तो कितना होता है, फाउन्डेशन उसका है या नहीं ; यह सब इन्वेस्टीगेशन और सर्वे में दर्ज है ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस जगह पर बनेगा यही पता नहीं है, और आप फाउन्डेशन की सारी बात बतला रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : जगह का नाम बतला दिया कि बीसलपुर के पास में बनेगा वह उसी साइट पर बनेगा या दूसरी जगह, फाउन्डेन्शन के लिए अलग अलग जगह पर देखना पड़ता है । बोरिंग होता है, पिट्स खोदे जाते हैं । उसके बिना रिवर बैड नहीं मिलता है ।

सीकर के पुलिस थानेदार सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा थानों का मुआयना

४४२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) सीकर के वर्तमान एस. पी. ने सन् ५६ में सीकर जिले में तथा ५७-५८ में जब वे चुरू जिले में थे तब वहां हर वर्ष में किस किस थाने का किस किस तारीख को मुग्रायना किया ?

(ख) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित थाने को अविलम्ब भेजी जानी होती है ?

(ग) क्या यह सही है कि सन् ५७ में निरीक्षण किये गये कई थानों की रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है ?

(घ) प्रश्न (क) में निरीक्षण की तिथि के साथ वहां कब निरीक्षण की रिपोर्ट भेजी गई है, इसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अविलम्ब भेजी जानी चाहिए तो कितना समय होना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा कोई नियम नहीं है। जल्दी ही भेजी जानी चाहिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ६-७ महीनों के विलम्ब से भेजी गई है तो क्या यह विलम्ब उचित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६-७ महीने लग गये हैं तो ज्यादा हैं। उतना नहीं लगना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह समझा जाना चाहिए कि जो ऑफिसर इन्सपेक्शन करता है तो यह उसके डिस्क्रीशन पर डिपेन्ड करता है कि मर्जी आये उस समय भेज दे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह उनको जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : 'जल्दी से जल्दी' को किस तरह से डिफाइन करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई तिथि तो मुकर्रर है नहीं। उनको जल्दी ही भेजना चाहिए। 'कितने' की बात नहीं है। इन्सपेक्शन करें तो जल्दी भेजना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : विभाग की तरफ से 'जल्दी से जल्दी' की क्या परिभाषा मानी जानी चाहिए ? महीना दो महीना ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी कोई परिभाषा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि कोई पुलिस ऑफिसर इन्सपेक्शन करता है और अपना इन्सपेक्शन नोट एक साल के बाद भेजे तो विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है ?

Page No.27

श्री रामकिशोर व्यास : यह चीज़ वाजिब नहीं है । आपका hypothettical क्वेश्चन है । यह गैरवाजिब है इतनी देर से भेजना ।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर कहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दुनिया में सबसे बड़ा आधार कॉमनसेन्स का है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार में इतनी कॉमनसेन्स नहीं है कि अगर कोई इन्सपेक्शन नोट तैयार करके ६ महीने के बाद भेजे विभाग में तो वह उस पर कोई एक्शन ले ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई जगह ऐसा होता है कि कई जगह उन्हें जाना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अधिकारी देर से निरीक्षण रिपोर्ट दे सकता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मतलब जो कुछ भी आप समझें वह है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय समझते हैं कि यह उचित नहीं है कि ६ महीने या साल भर में रिपोर्ट भेजे ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कह दिया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का एक सक्यूंलर है कि इन्सपेक्शन रिपोर्ट ज्योंही तैयार हो वह तुरन्त भेज दी जाय लेकिन विधान सभा में आपके उत्तर के कारण एस. पी. को लिबर्टी मिल गई कि इन्सपेक्शन करें और एक साल के बाद में रिपोर्ट भेज दे ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि ६ महीने उचित नहीं हैं। जल्दी दे देनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वे क्यों उनको संरक्षण देते हैं । उचित नहीं बताया तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं । जिस चीज़ को अनुचित मानते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं ?

गांधी अस्पताल भीलवाड़ा को भूमि

४४३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में गांधी अस्पताल के लिये कई लोगों की भूमि एक्वायर की गई थी ? यदि हां, तो कब और किन किन की ?

(ख) इस भूमि का अब तक किन किन को और कितना कितना मुआवजा दिया गया और कब, तथा जिनको नहीं दिया गया उनको क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि जिन लोगों की काश्त की भूमि ली गई उनको भीलवाड़ा के पास भूमि नहीं दी गई तथा उनके मुकाबले में अन्य लोगों को काश्त की जमीन भीलवाड़ा के पास दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां । सूची सदन की मेजपर रख दी गई है ।

(ख) मुआवजा अभी तक किसी को भी

Page No.28

(श्री भीखाभाई)

नहीं मिला क्योंकि मुआवजे के कागजात सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इन लोगों को मुआवजा देना चाहती है ?

श्री भीखाभाई : मुआवजे के कागजात चल रहे हैं। यह साफ सबूत है कि मुआवजा उनको दिया जाने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : दिये जाने की नीति है या नहीं ? सरकार देना चाहती है या नहीं, कागज चल रहे हैं उससे रेफरेंस नहीं निकलता है कि सरकार मुआवजा देना चाहती है।

श्री भीखाभाई : जहां पर वाजिब होगा और जमीन जिसकी ली गई है और वाजिब है और क्लेम साबित होता है, तो देगें।

श्री भैरोंसिंह : अभी तकरीबन किन २ को कितना कितना मुआवजा देना है इस बात का एसेसमेंट हो गया है क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया है कि कागजात चल रहे हैं। मुफस्सिल कागजात तो हमारे पास में नहीं हैं। पहले राजस्व विभाग में चल रहा था और अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास आया है।

श्री भैरोंसिंह : ये कागजात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास किस बात के लिए आये हुए हैं ?

श्री भीखाभाई : पहले जो एक्वायर करने का प्रोसीजर था और कम्पेन्सेशन दिया जाता था वह रेवेन्यू विभाग में होता था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करके जमीन एक्वायर कर सकता है, इसलिए उस विभाग से कम्पेन्सेशन के कागजात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि कम्पेन्सेशन देने के लिए लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट के मातहत यह प्रोवीज़न है कि नोटिस दिया जाना चाहिए सो वह प्रारम्भिक नोटिस उनको नहीं दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बहुत पुराना मामला है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के सामने जो कागजात पड़े हैं उन कागजात में इस तरह का क्या जिक्र आया है कि उनको इस प्रकार का प्रारम्भिक नोटिस दिया गया है।

श्री भीखाभाई : मैं इसके बारे में उत्तर निवेदन कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपका उत्तर बिल्कुल इनकम्प्लीट है और ऐसा कहना चाहिए कि बिल्कुल इर्रेस्पोन्सिबल है। सन् ४६ में उन गरीबों से जमीन खाली करवाई है, सरकार ने आज तक पैसा नहीं दिया है और कहते हैं कि कागजात विचाराधीन हैं, और पूछते हैं तो पूरी तरह से उत्तर नहीं देते हैं।

श्री भीखाभाई : Sir, my reply is quite responsible.

श्री भैरोंसिंह : It is quite irresponsible. No reply can be more irresponsible than that. यह कोई जवाब है, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कई बार सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि कम्पेन्सेशन के मामलों को जल्दी से जल्दी निबटाया जाय। इस प्रकार का प्रश्न मैं लगातार ३ साल से पूछता आ रहा हूं, और सरकार यही उत्तर देकर निकल जाती है कि कागजात विचाराधीन हैं। तो, किस बात के लिए विचाराधीन है जब कि प्रारम्भिक नोटिस नहीं दिया गया है तो विचार किस बात का कर रहे हैं। कम्पेन्सेशन देना चाहते है तो प्रारम्भिक नोटिस नहीं देना चाहिये। न नोटिस देना चाहते है और न कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : मैं अर्ज कर चुका हूँ कि नोटिस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया है कि कम्पेन्सेशन का जहां तक सवाल है सरकार कम्पेन्सेशन देना चाहती है। उसके बारे में सरकार के मुख्य सचिव ने एक ऑर्डर निकाला है कि एक साल के अन्दर तमाम कम्पेन्सेशन के केसेज जहां भी हैं, असिस्टेन्ट इन्जीनियर और तहसीलदार सब केसेज़ को निबटा दें। सरकार की जागरुकता का जहां तक सवाल है वह स्पष्ट जाहिर है, लेकिन जहां तक इम्प्लीकेशन का सवाल है उसमें स्लेकनेस हो सकती है तो सरकार उसको देखेगी।

श्री भैरोंसिंह : इन गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उन्हें देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यही आपने, अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें इस प्रकार आश्वासन मेरे पहले क्वेश्चन के ऊपर दिया था कि मंत्री महोदय ध्यान देंगे। इस प्रकार का आश्वासन आपकी तरफ से पहले भी मिला था, लेकिन एक वर्ष का पूरा समय निकल गया और फिर प्रश्न पूछा गया तो भी वही उत्तर है कि विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिन मंत्री महोदय से जवाब पूछा था वे तो हैं नहीं और जो जवाब दे रहे हैं वे मंत्री महोदय दूसरे हैं! वे फिर अलग हो जायेंगे कि मुझे मालूम नहीं है।

दिनांक २५. ८. ६० का स्थगित प्रश्न

मत्स्य निरीक्षकों की नियुक्तियां

१२५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

1. What qualifications have been prescribed for the post of Fisheries Inspector and how many persons have been appointed on these posts ?

2. Is it a fact that Mr. Pooran Singh has been promoted to this post ? If so, what are his qualifications ?

3. Have the aggrieved persons represented for their priority in this promotion ? If so, what action has been taken in this regard ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) फिशरीज़ इन्सपेक्टर के पद के लिए

नाथूराम मिर्धा)

...नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है : ...। एस. सी. परन्तु मत्स्य सम्बन्धी कम से कम ५ वर्ष का अनुभव रखने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में शिथिलता की जा सकती है।

(२) जी हां, नॉन मेट्रिक है और ७ साल का मत्स्य सम्बन्धी अनुभव है। मत्स्य विकास से सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवहारिक योग्यताएं उनमें हैं।

(३) जी हां, एक फील्डमैन जेसाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When this gentleman does not fulfil the qualifications laid down for the post, how he has been appointed ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि ५ साल का अनुभव रखने वाला चुना जा सकता है प्रमोशन के लिये और इनको ७ साल का अनुभव है।

पुराने अनुभवी कम्पाउन्डर्स की पदोन्नतियां

४१४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या राजस्थान के पुराने अनुभवी कम्पाउन्डर्स जो कि पहिले ट्रेनिंग की सुविधा न होने के कारण ट्रेनिंग न पा सके, उन्होंने कोई दरख्वास्तें सरकार के पास दी हैं ?

(२) क्या विभागीय अधिकारियों ने भी इस बात की सिफारिश की है कि उन्हें ट्रेन्ड माना जाय तथा उन्हें प्रथम श्रेणी का ग्रेड दिया जाय व उनकी सीनियोरिटी नहीं मारी जाय ?

(३) क्या स्वास्थ्य मन्त्री ने इन कर्मचारियों की स्थिति पर पुनः विचार करने का कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले विचार क्यों नहीं किया जा सका जब कि डिपार्टमेंट की तरफ से यह बात ध्यान में लाई गई कि राजस्थान में पुराने कम्पाउन्डर्स हैं जिनको उस समय नहीं ट्रेनिंग मिल सकी थी लेकिन आज वे बड़े कम्पाउन्डर की हैसियत से काम कर रहे हैं; तो क्यों नहीं उनको ग्रेड दिया जाता ? उनके बारे में जो सिफारिश की गई थी उस पर क्या विचार किया गया ?

श्री भीखाभाई : उनके बारे में विचार किया गया था लेकिन निर्णय वही रहा जो पहले था।

श्री मुरलीधर व्यास : वही निर्णय क्यों रहा ? हम यह सोचते हैं कि जिन लोगों के साथ ज्यादती होती है उनके साथ न्याय किया जाना चाहिये। पुरानी स्टेट्स में कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, कहीं नहीं थी। जब कि पी. एम. ओ. और दूसरे

Page No.31

(श्री मुरलीधर व्यास)

अधिकारी उनके बारे में सिफारिश करते हैं कि उनको ट्रेन्ड मान लिया जाय तो यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उस पर विचार किया जाय, यह सारे राजस्थान की प्रोबलम है। किन कारणों से इनको सुविधा नहीं दी जा रही है ?

श्री भीखा भाई : मैंने निवेदन किया कि थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर मैट्रिक पास किया हुआ हो और कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिये, या मैट्रिक पास हो और १५ साल तक सर्विस की हो तो ग्रेड (२) में उसे लिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो अभी आपने कानून बनाया है, लेकिन जिनकी आयु आज ५५ साल के करीब होने आई है और २०–२० साल काम करते हो गये तो क्या वे ट्रेनिंग लेने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया !

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत जरूरी है, इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पास नहीं हैं, उनको ले रहे हैं। उन्होंने विचार किया और पुनः विचार किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वे यह तो कहते कि किन कारणों से नहीं दे सकते, इस पर उनको विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : 'विचार' का मतलब यह होता है कि फिर से सोचें। उन्होंने फिर से सोच लिया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि नहीं दिया जा सकता।

श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम मुलासिया।

(अनुपस्थित)

अस्पताल बाडमेर

४३४. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला बाडमेर के अस्पताल को बढ़ाने का सरकार ने निश्चिय किया था ? अगर हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

(ख) बाडमेर जिला अस्पताल में अभी कितने बेड्स हैं और वर्ष के अन्त तक कितने बढ़ाये जायेंगे ?

(ग) अस्पताल की नई इमारत बनाने के लिये क्या कदम उठाए गये ?

(घ) अस्पताल में वर्तमान स्टाफ पेटर्न क्या है और वर्ष के अन्त तक क्या हो जायेगा ?

(ङ) अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): (क) जी हां, अस्पताल के विस्तार की योजना बनाने के लिये पी० डब्ल्यु० डी० विभाग को लिखा

Page No.32

(श्री भीखा भाई)

गया है तथा भूमि अवाप्त करने के लिये विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है ।

(ख) इस समय २४ रोग शैय्याएं हैं तथा विस्तार के पश्चात् ५० रोग शैय्यांए हो जावेंगी ।

(ग) इसका उत्तर (क) में दे दिया गया है ।

(घ) वर्तमान में जो स्टाफ है तथा विस्तार के पश्चात् जो स्टाफ होगा उसका विवरण निम्न प्रकार है :

	वर्तमान में	विस्तार पर
प्रथम श्रेणी डॉक्टर	२	३
द्वितीय श्रेणी डॉक्टर	२	३
स्टाफ नर्स	१	१
कम्पाउन्डर ग्रेड २	१	१
कम्पाउन्डर ग्रेड ३	४	६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	५	५

(ङ) बाडमेर अस्पताल में एक एक्स–रे मशीन लगाने के हेतु जिलाधीश बाडमेर ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें यह लिखा था कि जनता एक्स-रे मशीन लगाने के लिये चन्दा इकट्ठा करेगी । अत: मेडिकल ऑफिसर से पूछा गया है कि उक्त रकम जमा हुई या नहीं। इसका उत्तर अभी नहीं आया है । एक्स–रे मशीन के लिये आवश्यक धनराशि इस विभाग को मिलने पर मशीन शीघ्र लगादी जावेगी ।

श्री अनोपसिंह : आपका यह क्या अजीब कायदा है कि गांवों के लिये हर जगह पब्लिक कॉन्ट्रिब्यूशन होगा तो कोई चीज होगी और शहरों के लिये बिना कॉन्ट्रिब्यूशन के भी लगा दी जाती है । क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ कि बाड़मेर बोर्डर पर है इसलिये वहां पर इन्डिपेन्डेन्टली एक्स–रे मशीन की आवश्यकता है ?

श्री भीखाभाई : वहां की जनता जब कांट्रिब्यूशन देने को तैयार है तो उस पर सोचना पड़ेगा ।

श्री अनोपसिंह : यदि जनता जल्दी पैसा इकट्ठा नहीं कर सके तो काम रोकना तो नहीं चाहिये ।

श्री भीखाभाई : जनता की तरफ से जब यह बात आयेगी कि चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकते तब विचार किया जायगा ।

ग्राम पंचायत रतनपुरा (चूरू)

४३५. **श्री मोहरसिंह (चूरू) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रतनपुरा, तहसील राजगढ़ जिला चूरू, के सदस्य बचनसिंह, गिरधारीराम, जोधाराम व पूरणराम को गत वर्ष से पंचायत की बैठकों में भाग न लेने के कारण पं० ए० की धारा १७ (२) के तहत सदस्यता से पृथक कर दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री मोहरसिंह)

(४) उपरोक्त पंचगण आज तक पंचायत की कुल कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रह चुके हैं ?

(५) इन स्थानों को रिक्त घोषित करके इनकी पूर्ति कब तक करा दी जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी नहीं।

(२) उपरोक्त उत्तर के पश्चात् प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(४) दिनांक १-१-५६ से १५-१२-५६ तक कुल २० बैठकें हुई उनमें श्री वचनसिंह लगातार १० एवं ६ बैठकों में, श्री जोधाराम लगातार १३ एवं ६ बैठकों में, श्री पूर्णाराम १३ एवं ६ बैठकों में, श्री गिरधारीराम ७ एवं ६ बैठकों में अनुपस्थित रहे।

(५) स्थान रिक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि पंचों को मीटिंग की बैठक की सूचना राजस्थान पंचायत सामान्य नियम १६५४ के नियम ४ के अनुसार ४८ घंटे पहले नहीं दी गई थी।

श्री मोहरसिंह : सूचना ४८ घंटे पहले नहीं दी गई, इसकी जांच किससे कराई गई थी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चांदपोल दरवाजा (जोधपुर) की पुलिस गार्ड

(१) **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जोधपुर शहर के चांदपोल दरवाजा पर पुलिस की गार्ड रहती है ? यदि हां, तो उक्त पुलिस की क्या क्या ड्युटी है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस के कर्मचारी सारी रात्रि को शराब आदि का नशा करते रहते हैं और अपनी ड्युटी पर हाजिर न रह कर जनता को काफी परेशान करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की शीघ्र जांच करेगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं। चांदपोल दरवाजे पर पुलिस की चौकी अवश्य है। चौकी के कर्मचारी अनुसंधान (investigation) के अतिरिक्त अन्य सभी पुलिस कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

(ख) जी नहीं। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

सहकारी समिति के हिसाबात में गड़बड़

(२) **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों के हिसाब में गड़बड़, गबन तथा दुरूपयोग के मामले पाये गये हैं ?

(ख) इनमें किन २ सहकारी समितियों के मामले पुलिस में दिये जाने के संबंध में आदेश दिये गये हैं और कब २ ? कृपया

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) किन २ सहकारी समितियों के मामले पुलिस के हवाले कर दिये गये है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) जिन सहकारी समितियों के मामले पुलिस के हवाले कर दिये गये हैं उन मामलों में प्रत्येक में कितनी २ रकम का गबन या दुरूपयोग पाया गया है ?

प्रश्नों से सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला भीलवाड़ा के लिये के मदिरा के ठेकों की नीलामी

(३) **श्री शिवचरणदास** (मान्डल) : क्या आबकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के लिये भीलवाड़ा में दिनांक १५-२-६० को मदिरा की दुकानों के ठेके नीलाम हुए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक दुकान का ठेका कितने में नीलाम हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जिला भीलवाड़ा की उपरोक्त प्रत्येक दुकान का ठेका सन् ५० से ६० तक कितने में नीलाम हुआ ? सालवार नीलाम रकम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) सन् ५० से ६० तक प्रत्येक दुकान पर कौन कौन सी मदिरा कितनी कितनी बिकी ? सालाना सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) नियमानुसार प्रत्येक गैलन पर कितना मुनाफा लेने की दुकानदार को इजाजत है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

कुल मदिरा की बिक्री की सूची (ग) दुकानदार व सालवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

किस किस प्रकार की मदिरा पिछले १० साल में बिकी इसका पूरा विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि हर साल ठेकेदार बदल जाते हैं और गोदामों के पिछले १० साल के रजिस्टर्स को तलाश करना व उनके आंकड़े प्राप्त करना कठिन है।

(४) सूची (ज) संलग्न है।

सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

सदन की मेज पर रखी गई राजस्थान यातायात सेवा नियमावली, १९६०

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. १ (४) (१४) एच बी-जी एन I।६० दिनांक १६।८।६० जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट सर्विस रूल्स, १९६०, प्रकाशित किये गये हैं, उनको सदन की मेज पर रखता हूं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप–रेखा पर अग्रेतर वाद–विवाद

श्री अध्यक्ष : तृतीय पंचवर्षीय योजना पर अग्रेतर वाद-विवाद ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज तीन दिन से...

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Some time limit may be fixed so that everybody may get chance.

श्री अध्यक्ष : टाइम लिमिट फिक्स करने के बजाय यह अच्छा होगा कि माननीय सदस्य स्वयं कम समय लें । १५ मिनिट में ही समाप्त कर लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि आज सरकारी पक्ष की ओर से मुख्य मंत्रीजी उत्तर भी देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : रिसोर्सेज़ के बारे में हाउस ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर को भी सुनना चाहेगा ।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर सदन में दो दिन से वाद-विवाद हो रहा है । प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रान्त में ५ वर्षों में किस प्रकार का उत्पादन हो सकता है, किस प्रकार से वे आगे बढ़ सकते हैं, उस पर सोचने-विचारने और सही रास्ता निर्धारित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । भारतवर्ष के आयोजना आयोग का जो १८ महीनों का लगातार परिश्रम है जिससे उन्होंने यह योजना तैयार की है उसके अन्तर्गत हमारे राजस्थान में २१२ करोड़ रुपयों की योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूप में निर्धारित की है वह कितनी सफल होती है और कितनी नहीं होती है इसके ऊपर हमको यहां पर सोचना है और जो जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उन पर सोच–विचार करके हमें सही रास्ता अपनाना है ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने यहां पर जो प्रथम और द्वितीय योजनाएं निकाली हैं उनमें हमने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है । जहां तक खेती से उत्पादन करने का सवाल है, अन्न के उत्पादन का सवाल है, आज से १० वर्ष पहले जहां हम एक डेढ़ लाख टन अनाज बाहर से मंगाते थे वहां आज हम १०–१२ लाख टन अधिक अनाज उत्पादन करते हैं और तृतीय योजना में भी हम इसे काफी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रथम और द्वितीय योजना में खेती पर हमने विशेष ध्यान दिया है, सिंचाई के लिये हमने बड़े बड़े बांध बांधे हैं, काफी तालाब दुरुस्त किये हैं । उसी का परिणाम है कि जो काफी जमीन बेकार पड़ी रहती थी वह नये तौर से सिंचाई के अन्तर्गत आई है । इस संबंध में मैं यह ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज जितने बांध राजस्थान में बंधे हैं उनसे एक साइड को कोप सिंचित की जाती है और दूसरी साइड बिल्कुल वैसे ही रह जाती है । जैसे भीलवाड़ा जिले में ४–५ बांध; जैसे मेजा वगैरह जितने बांध हैं उन सब में उसकी राइट केनाल बराबर वर्क करती है लेकिन लेफ्ट केनाल वर्क नहीं करती है । राइट केनाल से उस स्थान के १० मील, २० मील, ३० मील दूर पानी ले जाया जाता है, लेकिन लेफ्ट केनाल से दो मील, चार मील तक तो काफी खेती हो सकती है, लेकिन

श्री तेजमल बापना)

उसके बाद नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, ये सिंचाई के आंकड़े कतई गलत बनाये गये हैं, जैसे आप मेजा बांध को लीजिये, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। जिस वक्त योजना सदन के सामने प्रस्तुत की गई, उसकी सिंचाई ३५ हजार एकड़ हमको बतलाई गई। आज मेजा डेम पूरा भर गया है, काफी सिंचाई होती है, लेकिन केनाल के डिफेक्ट्स की वजह से आज उससे सिंचाई केवल १८ हजार या २० हजार एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, जब कि डिपार्टमेंट स्वयं इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। तो ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं, केवल उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगायें कि दरअसल सब योजना सफल हो गई है, तो ठीक नहीं होगा। जहां जहां कमी है, जहां जहां खामियां हैं, उनको दुरुस्त करके, जो टार्गेट्स हमको बतलाये गये हैं, उनको अचीव करना हमारा पहला फर्ज है, तब जाकर सिंचाई के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में हमारे लक्ष्य हम पूरे कर सकेंगे।

इसके बाद मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो योजनायें बनती हैं, वे आया ऐसी होती हैं कि हमारे देश में कितना उत्पादन होता है, कितने हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं और कितना, उसके बाद कन्ज़म्प्शन करने के लिए हमारे पास मेटीरियल है जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा में काफी बढ़ोतरी हमारे यहां राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में काफी हो रही है। शिक्षा में हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन हमारी प्लानिंग जो है, क्या शिक्षा के मायने में आज सही नीति के ऊपर निर्धारित हो रहा है। मैं आपका ध्यान, जिसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो बहुत बड़े बड़े उन्नत देश हैं इस दुनियां में, जिनमें स्विट्ज़रलैंड को ले सकते हैं, जापान को हम ले सकते हैं, वहां पर जब योजनायें बनती हैं, तो सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर मुख्य ध्यान दिया जाता है कि हम देखें कि जो शिक्षित हमारे सामने आते हैं राष्ट्र में, क्या उनको शिक्षा उस प्रकार की दी जाती है कि जिस प्रकार की आवश्यकता है और वहां की नीति जिसके ऊपर निर्धारित रहती है। हमको सर्विस में इतने मिकदार व्यक्तियों की जरूरत है, उतने मिकदार के व्यक्ति सर्विसेज में लिये जायेंगे, जितने टैकनिकल हैं इसकी जरूरत है, उनको टैकिनकल शिक्षा दी जायगी। लेकिन हमारे यहां इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार का अंग्रेजों के वक्त से शिक्षा का ढांचा चला आ रहा है, कुछ सुधार हो रहा है साधारण सा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के मामले में जो प्लानिंग है, वह सही नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी है, वह बढ़ती जा रही है। आज हम देखते है कि साधारण व्यक्ति चाहे वह मेट्रिक है, मिडिल है, इन्टर है, बी. ए. है, एम. ए. है, सब के सब एक तरफ भागते हैं, सर्विस की तरफ; लेकिन सर्विसें, बहुत सीमित हैं और कितनों को वहां एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इसको देख कर हम शिक्षा के सम्बन्ध में सही तरह से प्लानिंग करके हमारे यहां के नवयुवकों को और किसी धन्धे में लगाने का प्रयत्न करें, तो हमारी योजना काफी

(श्री तेजमल बाफना)

सफल हो सकेगी ।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज देश का ध्यान हमारे यहां बढ़ती हुई महंगाई की तरफ है ! हमने काफी तरक्की सिंचाई में की, काफी तरक्की उत्पादन में की, उत्पादन में, अन्न के उत्पादन में की लेकिन फिर भी हमारे यहां पर जो कीमतें हैं, वे बहुत बढ़ रही हैं। इनकी ओर आज हमारे राष्ट्र के जो कर्ण-धार हैं, उनका ध्यान गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है । इसकी वजह से हमारे यहां पर जो जन-साधारण गरीब वर्ग है, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है और यह हमारे प्लानिंग के समय सोचने के लिए बाध्य करता है कि दरअसल कौनसी नीति अपनाई जाय हमारे यहां कि जो ऊंची दरें हैं, वे नीचे आयें और जन साधारण जो एक तरफ काफी सामान इकट्ठा कर रहे हैं वे काफी एकत्रित न करें। इसके साथ ही जो गरीबी की अवस्था चल रही है, वह गरीबी की अवस्था न रहे और समान अवस्था में खाने को मिले, पहनने को मिले और रोजी-रोटी मिले । इस बात की तरफ सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, अब तक जो ध्यान योजना में चला आ रहा है, उस रास्ते पर चलने से देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, यह बात सही है लेकिन दरअसल खेती तक ही हमको सीमित नहीं रहना है । आज आवश्यकता हमारे यहां पर खेती के साथ साथ इन्डस्ट्रीज़ लगाने की भी है, छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । आज बड़ी इन्डस्ट्रियां भी लगा रहे हैं और काफी ध्यान हमारे राष्ट्र का बड़े बड़े उत्पादनों पर, बड़े बड़े उद्योगों पर लग रहा है, लेकिन जहां तक जन-साधारण का, जीवन स्तर का प्रश्न है, एक तरफ हम बिहार प्रान्त को ले सकते हैं, जहां काफी कोयला उत्पादन होता है, दूसरे सामानों का उत्पादन होता है, लेकिन वहां के जन-साधारण का स्तर है, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है, वह बहुत नीचा है । इसके विरोध में अगर हम पंजाब को लेते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ बहुत कम है, छोटे छोटे उद्योग काफी हैं, खेती और खेती के साथ में छोटे छोटे उद्योग काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, तो वहां का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा उठ रहा है। हमको इस देश के दूसरे प्रान्तों की स्थिति को देखते हुए यह भी सोचना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि दरअसल हमारे यहां पर किस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ लगाई जायं, जिससे हमारे यहां का जो ग्रामीण है, उसको रोजगार भी मिले और उसका जीवन-स्तर ऊंचा बने और राजस्थान में काफी गुंजाइश है । अध्यक्ष महोदय, अगर एग्रो और इन्डस्ट्री को साथ जोड़ कर उत्पादन बढ़ाने की ओर और छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ लगाने की ओर ध्यान दिया जाय । हमारे यहां पॉवर की कमी की वजह से बिजली की कमी की वजह से हजारों की तादाद में जो ग्रामीण हैं, उनके सामने यह सवाल है कि उनके रिसोर्सेज़ हैं, वे आज काम में नहीं आते हैं । बड़ी खुशी की बात है कि आयन्दा वर्ष में बिजली का काफी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। जो फिगर्स हमको बतलाये गये हैं, उनके अनुसार १९६१ तक, मेरे ख्याल से, २००, ३००, ४०० मील तक हमको भाखरा और चम्बल डेम से बिजली मिल जायगी और उससे कोटा

(श्री तेजमल बापना)

डिवीज़न के अलावा, उदयपुर डिवीजन जयपुर डिवीजन का बहुत हिस्सा पॉवर उपलब्ध करने में सफल होगा और हमारे ये आंकड़े हैं, ये फिगर्स हैं, ये टार्गेट्स हैं, ये सही अनुमान से ठीक समय पर कामयाब होते हैं, तो हमारे यहां राजस्थान की काफी बड़ी उन्नति कर सकेंगे। हमारे यहां स्कोप काफी है, आज लोगों में चेतना काफी है। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारे यहां पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना २ अक्टूबर, १९५९ से लागू हुई और जब से उनको अपने पैरों पर खड़े होने का, जन साधारण को, ग्रामवासियों को, अवसर मिला है, तो दर असल उनको नई चेतना मिली है। वे समझने लगे हैं कि यह काम हैं उत्पादन बढ़ाने का, जीवन स्तर को बढ़ाने का, यह हमारा फर्ज है। उन लोगों में चेतना काफी है लेकिन उनके पास साधन इतने नहीं हैं, जिससे जो एनर्जी है, उसका उपयोग कर लें। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार का विशेष तौर पर कि पॉवर के सम्बन्ध में जो आंकड़े बतलाये गये हैं, उनको सही निर्धारित स्थिति में उपलब्ध कर सकेंगे तो हमारे यहां पर काफी तरक्की कर सकते हैं।

एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा जायं या पब्लिक सेक्टर की तरफ ज्यादा जायं। कुछ आवाजें आती हैं कि हमको इन्डस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन करना चाहिए। जहां तक कुछ इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है, उनको नेशनलाइज़ करना बहुत जरूरी है लेकिन नेशनलाइजेशन के बहुत बड़े खतरे भी हैं। अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान हिटलर और मुसोलिनी की तरफ आकर्षित करूं जिन्होंने कुछ पॉवर गेन किया, कुछ पोलिटिकल पॉवर गेन करने के साथ साथ उन्होंने इन्डस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ किया और वे अपने पॉवर के नशे में मद-मस्त हो गये और सारी दुनिया को परेशान किया। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यहां पर भारतवर्ष में नेशनलाइजेशन कहां तक सफल हो सकता है यह सोचने की चीज है। हमने भारतवर्ष में कुछ जगह नेशनलाइजेशन किया है और कुछ को और करना है लेकिन हमारे यहां पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केवल यही चाहें कि नेशनलाजेशन पब्लिक सेक्टर में हो, जैसे रूस में हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि रूस और हिन्दुस्तान की पद्धति में काफी अंतर है। हम रूस की पोलिसी को लागू करके यहां पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते है। यदि हम उस तरीके को अपनावेंगे तो हम अपने देश के निर्माण कार्यों में सफल नहीं हो सकते। हम तभी सफल हो सकते हैं जब सहकारिता को अपनावेंगे और हमने इस तरफ काफी ध्यान अपना लगा रखा है और लगा रहे हैं। मगर आज हम इस बात की तरफ सोचने और मालूम करने की कोशिश में हैं कि हमारे यहां का जो डिविज़न ऑफ प्रोड्यूस है उसके तरीकों को हम सहकारिता से अपनावें तो काफी उन्नति कर सकते हैं। जहां तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है, इसमें २१२ करोड़ की योजना के साथ साथ राजस्थान कैनाल के ४५ करोड़ रूपयों का खर्च भी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार पर डाला है। यह भारत सरकार की बहुत बड़ी ज्यादती है। देखा जावे तो राजस्थान में हम बिना राजस्थान

(श्री तेजमल बापना)

केनाल के बने ही आत्म निर्भर है । लेकिन राजस्थान के नाम की भूमिका और इतिहास जो हमारे सामने बताया गया है वह यह है कि बीकानेर में १६४८ में भारत सरकार ने इसके लिये कोशिश की थी और इस प्लान को चलाया था। फिर समझ में नहीं आता कि इसका खर्चा राजस्थान सरकार पर क्यों डाला जा रहा है ? इसके लिये मैं पुरजोर शब्दों में अर्ज करूंगा कि भारत सरकार को राजस्थान केनाल के लिये रुपया देना चाहिये । हमारे यहां जो रिसोर्सेज के लिये, हमें जितना करोड़ रुपया इकट्ठा करना है और जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। इसमें टैक्सेशन को हम लें । आज हमारे यहां ७ प्रतिशत टैक्स पहले ही लग चुके हैं । अब कितना टैक्स इसके कारण और बढ़ेगा और बढ़ाने की गुंजायश है, यह तो नेता देखेंगे । अगर हम नोर्वे और स्वीडन में देखें तो हमको मालूम होगा कि वहां पर २५ प्रतिशत तक टैक्स लगा हुआ है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि यहां पर भी वही लगे । मैं नहीं चाहता कि वह टैक्स हमारे यहां भी लग जावे क्योंकि वहां की स्थिति और हमारी स्थिति में काफी फर्क है । हमारा देश गरीब है । इस सम्बन्ध में हमारे यहां के अर्थशास्त्री हैं वे बताते हैं कि ८ या १० प्रतिशत तक टैक्स लगाये जा सकते हैं और हमारे यहां जो पंचायत समितियें हैं और दूसरे लोकल इन्स्टिट्यूशन्स हैं वे भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी अपनी आमदनी बढ़ावें । तो मैं नहीं समझता कि जो आंकड़े इसके लिये निश्चित किये गये हैं उसमें कहां पीछे रह जावेंगे ।

इसके साथ साथ हमें अल्प बचत की ओर भी ध्यान देना चाहिये और अगर इस तरफ ध्यान दें तो काफी राशि इकट्ठी कर सकते हैं । अभी अल्प बचत की तरफ जो नीति निर्धारित हो रही है और जो ढांचा बनाया गया है वह एक ऑफिशियल ढांचा है और इसमें जन साधारण का एप्रोच बहुत कम है । हम राजस्थान में देखते हैं कि ७ या ८ प्रतिशत सेविंग करते हैं, इसके अतिरिक्त यदि हम चीन और अमेरीका आदि दूसरे मुल्कों को देखें तो मालूम होगा कि वे ३० प्रतिशत सेविंग करते हैं । इस प्रकार हम अल्प बचत से भी काफी धन बचा सकते हैं । यदि जनता का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें और हमारा फोर्स ठीक तरह से लगावें तो हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं ।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हम अपने यहां की ऐनिमल हस्बेन्ड्री की जो योजना है, उसकी ओर ध्यान मैं आपका आकर्षित करूंगा । इस सम्बन्ध में हमारे यहां बीकानेर से आने वाले साथी ने मुख्य मन्त्री पर यह दोषारोपण किया कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी उदयपुर से आये हैं इसलिये वहां पर अधिक पैसा खर्च करते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका यह दोषारोपण गलत है । माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कल भी बताया और समय समय पर बताया कि आंकड़ों में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ । लेकिन एनिमल हस्बेन्डरी के आंकड़े जो दिये हुए हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आप उसकी आलोचना करेंगे कि लाखों रुपया जोधपुर और बीकानेर में लगाया जा रहा है, जबकि उदयपुर में कुछ भी नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : In one division you are investing in animals and in the other division you are investing in human beings.

श्री तेजमल बाफना : हमारे यहां भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये । हमारे यहां राजस्थान में पशुधन है वह बहुत बड़ा धन है लेकिन जैसा कृषि मंत्री ने बताया कि इससे २० या २५ करोड़ रुपये की आमदनी प्रतिवर्ष पशुधन से प्राप्त होती है तो क्या माने हैं कि दूसरे डिवीज़नों में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और केवल बीकानेर और जोधपुर में ही इसके लिये पैसा दिया गया ! दूसरे भी उम्मीद करते हैं कि उनका पशुधन भी सुधरना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि १० या १२ वर्ष हुए हैं जब भारत वर्ष आजाद हुआ है और बागडोर अपने हाथ में आई । इन १०, १२ वर्षों में भारतवर्ष ने तरक्की की है लेकिन अभी तक हमारा आर्थिक ढांचे का स्तर जितना होना चाहिये, नहीं है । हिन्दुस्तान में प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं और वे ७५ के करीब हैं। वे ऐसे हैं जो आज चाहें कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को ऊंचा ले जाना चाहिये तो ले जा सकते हैं । उन्होंने हमारे इन्डिया के इकोनोमिक प्लानिंग को कन्ट्रोल कर रखा है । इस चीज़ को हमें देखना है और जब तक हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन लोगों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी क्योंकि एक तरफ तो वे लोग पैसा एकत्रित करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब पिसते जा रहे हैं । जब इनको खत्म करेंगे तभी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हो सकेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना विचारार्थ है । इस सिलसिले में पॉवर क्षेत्र का जहां तक स्वाल है इस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं । उनमें से कई विचार महत्वपूर्ण हैं और इस बात की कोशिश की जावेगी कि जहां तक हो सके उन विचारों को हम कॉन्क्रीट शेप देकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में अमल में ला सकें । तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले यह निहायत जरूरी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स किये हैं और आगे साल के आखिर तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक हम क्या क्या अचीवमेंट्स कर पावेंगे इसके लिये मैं चन्द बातें सदन के सामने पेश करना चाहूंगा । यह इस वास्ते जरूरी है कि सदन में इस बात पर भी जोर दिया गया और क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लॉन में हमारे जो टार्गेट्स थे उन टार्गेट्स को हमने अचीव नहीं किया । जो भी आंकड़े और फैक्ट्स सदन के सामने रखे जावेंगे, मुझे यह विश्वास है कि सदन इस बात को मानेगा कि जो भी टार्गेट्स हमारे सामने थे उन टार्गेट्स को हमने अचीव किया है । सेकिन्ड फाइव इयर प्लॉन के शुरूआत में राजस्थान में टोटल इन्स्टाल्ड केपेसिटी किलोवाट्स में ३४,६०० थी । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के आखिर में भी हम इतनी केपेसिटी डेवलप नहीं कर पायेंगे । मेरा यह निवेदन

Page No.41

(श्री हरिश्चन्द्र)

करना है कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी, हो सकता है कि जो फीगर्स मैंने आपके सामने दिये हैं, इसके माने यह नहीं है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वह खपत भी हो रही है। जो एनर्जी पहले थी वह ३६६ किलोवाट थी। सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान की शुरूआत हुई और टार्गेट्स मुकर्रर हुये तो थर्मल स्कीम के नीचे २२ हज़ार किलोवाट बिजली जेनरेट करने का प्लान था। उसकी मैं ब्रेक अप सदन के सामने पेश करना चाहूँगा :

जयपुर	८	हज़ार किलोवाट
जोधपुर	६	,, ,,
कोटा	२	,, ,,
भरतपुर	४	,, ,,
अलवर	२	,, ,,

इसका टोटल अगर लगाया जावेगा तो वह २२ हज़ार किलोवाट होगा। कोटा में २ हज़ार किलोवाट के सेट्स चालू हो गये हैं। जयपुर में ३ हज़ार किलोवाट के सेट्स चालू हो गये हैं। बाकी के सेट्स हैं उनमें से कई इस साल के आखीर में चालू हो जावेंगे। और कोई ऐसा सेट नहीं रहेगा जो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के आखीर तक चालू न हो। ये जो २२ हज़ार किलोवाट्स के टारगेट्स थे वे सारे के सारे पूरे होंगे।

इसके अलावा डीज़ल सेट्स में ५,८७० किलोवाट जेनरेट करने का प्रावधान था। उसकी मैं ब्रेक अप वेल्यू सदन के सामने पेश करना चाहूंगा :

भरतपुर के टार्गेट्स थे	५१२ किलोवाट	सारे के सारे अचीव हो गये।
अलवर	३०० ,,	,,
किशनगढ़	२०० ,,	,,
टौंक	२५० ,,	,,

और निवाई की लाइन कम्प्लीट हो गई है। ट्रान्सफोर्मर निवाई पर लगाने के बाद निवाई इनरजाइज़ किया जावेगा।

जैसलमेर टार्गेट्स के	थे	६२ किलोवाट	कम्पलीट हो गये।
सागवाड़ा	,,	१२० ,,	,,
भीलवाड़ा	,,	५०० ,,	,,
शाहपुरा	,,	२२५ ,,	,,
डीड	,,	१२० ,,	,,
रतनगढ़	,,	३०० ,,	,,
चित्तौड़	,,	३०४ ,,	,,
बिलाड़ा	,,	२५० ,,	,,

बिलाड़ा से सोजत की लाइन इनरजाइज़ होगी और सोजत को पॉवर मिल रहा है।

नागोर के टार्गेट्स थे		२५०
जालोर	,,	३५०
सुमेरपुर	,,	३०४। उसके अगेन्स्ट २०० किलोवाट के सेट चालू हो गये हैं।

शिवगंज के लिए सप्लाई करने का प्रावधान था उसमें १०० किलोवाट इन्स्टाल हो गई है, लेकिन लाइन इनरजाइज़ नहीं

Page No.42

(श्री हरिश्चन्द्र)

हुई है क्योंकि ट्रान्सफोर्मर्स नहीं आये हैं इसलिये २०० का प्रावधान था।

विजयनगर	२५०	किलोवाट	कम्पलीट हो गये।
केकड़ी	१००	,,	,,
मालपुरा	१२५	,,	,,
झालावाड़	१२५	,,	,,
करोली	३००	,,	,,

करोली से हिन्डौन का इलेट्रिफिकेशन हो गया है।

राजसमन्द	२३३	किलोवाट	कम्पलीट हो गये।
डीडवाना	२५०	,,	,,

डीडवाना से दौलतपुरा के वर्क्स चालू हैं। वर्क्स इन प्रोग्रेस :

टोडा भीम	१५०	किलोवाट	कम्पलीट हो गये।
डूंगरपुर	२८५	,,	वह कमीशन जल्दी से जल्दी किया जायेगा।

यों करके ५,८७० किलोवाट के ये हमारे टार्गेट्स थे। मैं यह कह सकता हूं कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के, कोशिश यह की जायगी कि इस साल के, आखीर तक उनको पूरा कर लें।

इसके अलावा नोनप्लान वर्क्स अलग हैं। उसके लिए टोटल केपेसिटी पॉवर की प्रोड्यूस हुई वह ५३१३ किलोवाट है। ये जितने सेट्स लगे हैं वे ओवर एन्ड अबव दी प्लॉन लगे हैं, क्योंकि ऐसी आवश्यक जरूरीयात आ गई थी; जैसे बीकानेर में या जोधपुर में जहां पॉवर सिचुएशन प्रिकेरियस हुई एक्स्ट्रा खर्चा करके सेट्स लगाये। जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, भीलवाड़ा में, सिरोही और धौलपुर में लगाये। टोटल ५३१३ किलोवाट ओवर एन्ड अबव दी प्लान खर्च हुआ।

अब मुझे यह निवेदन करना है कि राजस्थान को जो पॉवर सप्लाई हो रही है उसको आप मोटे तौर से चार सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिस्टम स्टीम टर्बाइन का है, दूसरा डीज़ल का, तीसरा भाखरा का और चौथा चम्बल का सिस्टम है। मैंने ये दो तो निवेदन कर दिये डीजल और स्टीम।

जहां तक भाखरा का प्रश्न है, उसके सिलसिले में मुझे सदन से यह निवेदन करना है कि भाखरा, जो नांगल और कोटला पॉवर हाऊस है, उससे राजस्थान को ४,६०० किलोवाट मिलने का प्रावधान था। उसमें से आज हमको ३ हज़ार किलोवाट मिल रहा है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो एक्स्ट्रा १६०० किलोवाट हैं उनको जल्दी से काम में ला सकें। इसके अलावा जब लेफ्ट बैंक भाखरा चालू होगा, जो सेकिन्ड फाइव इयर के आखीर तक चालू होगा, तो हमको १६,४३७ किलोवाट भाखरा से पॉवर मिलेगा। जो ४,६०० फीगर पहले मैंने कहा था वह इस १६,४३७ किलोवाट में इन्क्ल्यूडेड है! तो टोटल भाखरा के लेफ्ट बैंक से हमको १६,४३७ किलोवाट बिजली मिलेगी।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में या थर्ड फाइव ईयर प्लॉन में ?

श्री अध्यक्ष : सेकिन्ड फाइव इयर प्लान ।

श्री हरिश्चन्द्र : तो टोटल भाखरा, जिसके अन्दर नांगल और कोटला शामिल हैं १६४३७ किलोवाट पॉवर मिलेगी । जिसमें से ४६०० किलोवाट बिजली आपको इस वक्त मिलेगी उसमें से तीन हज़ार किलोवाट एक्चुअली ले रहे हैं । सोलह हज़ार में से ४ हज़ार मिल रहा है । अभी लेफ्ट बैंक चालू नहीं हुआ इसलिए अभी पूरी नहीं मिल रही है, उसके बाद सोलह हज़ार मिलने लगेगी ।

श्री अध्यक्ष : अभी जो जेनेरेट हो रही है उसमें से अपना हिस्सा चार हज़ार किलोवाट का है ।

श्री हरिश्चन्द्र : उसमें अपन तीन हज़ार किलोवाट ले रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या राजस्थान को इतना ही दिया जा रहा है या हम इतना ही ले रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : ४६०० की मेज़िम्मम केपेसिटी है। आज दिन, तीन हज़ार किलोवाट ले रहे हैं । यह ऑलरेडी कन्ज्यूम कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हम तीन हज़ार ही ले रहे हैं और इससे ज्यादा वे क्या दे नहीं रहे हैं या हमारी तैयारी नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : एक्चुअली हम तीन हज़ार किलोवाट ले रहे हैं और जो बाकी का १६०० किलोवाट है वह हम दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक कन्ज्यूम कर लेंगे । इसी सिलसिले में मैं भाखरा के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं, जो एक प्रकार इमोशन है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है, इसके लिए मैं सदन के सामने जो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं ।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा था कि चूरू जिले में एक भी नया कनेक्शन नहीं मिला ?

श्री हरिश्चन्द्र : श्री गंगानगर में जनवरी में बिजली शुरू हुई, श्री करणपुर में जुलाई में शुरू हुई, रायसिंह नगर में जुलाई में शुरू हुई, हनुमानगढ़ में मार्च से शुरू हुई, संगरिया मन्डी में अगस्त से शुरू हुई, केसरीसिंहपुर में अगस्त से शुरू हुई, गजसिंहपुर में अप्रेल में शुरू हुई । रतनगढ़ में अप्रेल में, सीकर में अप्रेल में, चूरू में अप्रेल में, ताल थापड़ में अप्रेल में, सरदारशहर में अप्रेल में, पिलानी में मई में, रतनगढ़ में अप्रेल में, रामगढ़ में अप्रेल में, जयदेलसर में अप्रेल में, डूंगरगढ़ में अप्रेल में, नापासर में अप्रेल में व बीकानेर में अप्रेल में शुरू हुई । बीकानेर में इस वक्त हम ८०० किलोवाट के आस-पास ले रहे हैं । करासू में अप्रेल, भोमसर में अप्रेल में,सुडसर में अप्रेल,तारापुर में अप्रेल मे देवकुन्ड सागर अप्रेल में बीदासर में अप्रेल में थावना में अप्रेल में सुजानगढ़ में अप्रेल में चिड़ावा में जुलाई, झुंझनूं में मई, शादूल शहर में अगस्त में व पृथ्वीराजपुर, अगस्त में ।

इसके अलावा गंगानगर डिवीज़न में

(श्री हरिश्चन्द्र)

ये ये विलेज आये ।

विजयनगर : Work in progress.

पीलीबंगा : Work in progress.

रायसर : Work in progress.

हनुमानगढ़ : Now done

शेरगढ़ : Survey is finished, work will be finished.

चुरू डिविज़न में :

तारानगर, भादरा नौहर : Work Yest to start.

सूरजगढ : Work yet to start.

खेतड़ी : Work yet to start.

फतहपुर :

लक्ष्मणगढ़ : Line ready. Local distribution will take soon.

बिसाऊ : Line ready. Local distribution will take soon.

इससे मेरा यह निवेदन है कि भाखरा से हमने इतनी जगहों पर लाइट दी है, और जगहों के लिये लाइट देने का काम चालू है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी जगह हम लाइट ले आयेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जिन शहरों की सूची आपने बतायी उनमें से अधिकांश शहरों में पहले से ही बिजली थी । अधिकांश बीकानेर के म्युनिसिपल टाउन्स हैं जहां पहले से बिजली थी ।

श्री चन्दनमल वैद: इन इलाकों में तो सन् ४५-४६ से बिजली चली आ रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले बीकानेर से होती अब भाखरा से हो रही है । जब कि हम रतनगढ़ और बीकानेर शहर तक एक्सटेन्शन करते हैं, नई लाइन डालते हैं; वह तो हम नया ही काम मानेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : हम यह पूछना चाहते हैं कि जिन गांवों में पहले से बिजली नहीं थी उन कितने गांवों को दी गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। गंगानगर इलाके में तो पहले बिजली थी ही नहीं, वहां तो सारा का सारा नया है और बीकानेर डिवीज़न के अन्दर कई गांव ऐसे हैं जिनको हम नई तौर से बिजली दे रहे हैं । रतनगढ़ से बीकानेर तक जो पुरानी लाइन थी उससे बिजली हम ले जा नहीं सकते, वहां नई लाइन डाली गई; सारी की सारी लाइन तब्दील कर रहे हैं । इस तरह से यह काम तो नया ही हुआ है । आखिर कोई क्रिटिसिज्म हो तो करेक्ट होना चाहिये....

श्री चन्दनमल वैद : मेरा तो यह कहना है कि भाखरा की बिजली आने के बाद चुरू जिले में एक भी नया कनेक्शन दिया गया क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरदारशहर के आठ कुओं को हमने पानी के लिये बिजली दी है।

श्री चन्दनमल वैद : It is absolutely wrong.

श्री हरिश्चन्द्र : चार को तो पहले दे

(श्री हरिश्चन्द्र)

दी गई थी और चार को एक हफ्ते पहले मन्जूरी दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाखरा के बाद चम्बल योजना से जो बिजली मिलने वाली है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक चम्बल योजना का सवाल है मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि राजस्थान में चम्बल नदी ही एक ऐसी नदी है जिससे राजस्थान को हाइडल पॉवर मिल सकती है । इसके अलावा दूसरी योजनायें भी हो सकती हैं जैसी ऑटोमिक पॉवर स्टेशन या माही का प्रोजेक्ट है इनसे भी पॉवर मिल सकती है । लेकिन जहां तक मेग्ज़िमम हाइडल पॉवर का ताल्लुक है हमें राजस्थान में चम्बल से ही मिलेगी। चम्बल के तीन स्टेजेज़ हैं । गांधीसागर, राणा प्रतापसागर और कोटा डेम; इन तीनों डेम्स से बिजली पैदा होगी जिसमें से पचास प्रतिशत राजस्थान को मिलेगी और पचास प्रतिशत मध्यप्रदेश को मिलेगी । जहां तक गांधी सागर का सवाल है आप सब को मालूम है, गांधीसागर का काम खत्म होने आया है और नवंबर से गांधी सागर से लाइट जेनरेट होगी ! गान्धी सागर के पॉवर सेक्शन में इस वक्त तीन टर्बाइन्स लगे हुए हैं इन तीनों टर्बाइन्स से हमको ३७,५०० किलोवाट बिजली मिलेगी और चौथा टर्बाइन और लगता है तो सात हजार किलोवाट की केपेसिटी और बढ़ जायगी और इस तरह से ४६ हज़ार किलोवाट तक बिजली हमें प्राप्त हो सकेगी। ये तीनों सेट्स विदिन दी प्लान कोई ६ मीहने में शुरू होगा तो कोई नवम्बर में चलेगा; इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक तीनों टरबाइन हमारे चलने लगेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है जहां तक चम्बल योजना के युटिलाइजेशन का सवाल है हम इसमें पिछड़े हैं, इसमें दो राय नहीं। हम किस वजह से पिछड़े हैं इसके वजुहात देने की आवश्यकता नहीं है। सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी क्या क्या वजह थी। मुख्य कारण इसमें यह था, अगर वहां के लिये हम टॉवर बाहर से इम्पोर्ट करते तो हमारा फोरिन एक्सचेन्ज काफी इन्वोल्व हो जाता; इसीलिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने यह मुनासिब समझा कि इसका निर्माण इन्डिया में ही होना चाहिये ।

इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जहां तक प्रश्न था उसने हमको यह प्रोमिज़ किया था कि ५८ में हमको यह स्टील उपलब्ध हो जावेगा। कई वजह से वह स्टील नहीं आ सका। हमारे इण्डिया में स्टील मेनुफेक्चरिंग के सवाल में भी डिले हुई। बाहर से आने को जो था, वह भी कई कारणों से टाइम पर नहीं आ सका। अगर यह स्टील हमको ५८ में मिल जाता तो कोई वजह नहीं थी कि जो टॉवर्स हैं वे आज आपको खड़े हुए नजर नहीं आते। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमने इस बीच कोई कोशिश नहीं की। सदन के सामने मैं यह रखना चाहूँगा कि इसके बाद भी जहां तक चम्बल का सवाल है, काम शुरू हो गया। गांधीसागर और कोटा के बीच में काम शुरू हो गया और वहां का जो टोटल लोकेशन है वह २२५ हैं, इनमें से १४० फाउन्डेशन्स तैयार हो गये और आगे की फाउन्डेशन्स के काम शुरू हैं। हमारी यह कोशिश थी कि हम साथ के साथ ही इस काम को बारिश के अन्तिम समय में शुरू करके

(श्री हरिश्चन्द्र)

सारे फाउन्डेशन का काम और टॉवर इलेक्शनेस का काम कम्पलीट कर लेते, पर ज रीज़न्स स्ट्राइक के आपके सामने हुए, उससे हमको थोड़ी देरी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे जो ३६ वैगन्स थे जो साउथ इन्डिया से आने वाले थे उनके आने में देरी हुई।

अब मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें यह है कि ३६ में से ३८ वैगन्स आ गई हैं और एक वैगन अभी मिल नहीं रही है। वह कहीं रह गई है। मैं आशा करता हूँ कि वह वैगन भी आ जावेगी और जल्दी से जल्दी हम टॉवर इरेक्शन का काम शुरू कर देंगे।

तो यह होने के बाद टॉवर्स का इरेक्शन होने के बाद हम गांधीसागर से कोटा लाइन जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अनएक्सपेक्टेड इन्सीडेन्स नहीं हुई तो कोटा को हम इस साल के आखीर तक इनेंजाइज़ कर लेंगे।

इसके अलावा जहां तक स्टील का प्रश्न है, जो अभी लेटेस्ट इन्फोर्मेशन हमारे पास है, उससे कह सकता हूं कि टाटा आयरन और इण्डियन आयरन कम्पनियों का जितना सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोटा दिया था उसका उन्होंने ५० पर्सेन्ट हमें दे दिया है और टावर्स मैन्युफेक्चर हो रहे हैं और अपने यहां सितम्बर के आखीर तक आने भी शुरू हो जावेंगे। तो जहां तक प्रश्न कोटा गांधी सागर, कोटा सवाई माधोपुर, जयपुर; इन लाइनों का है, अभी तक जो हमारे सामने प्लान है और जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोटा में साल के आखीर में और जयपुर में मिडल आफ ६१ तक हाइडल पॉवर पहुंचाने की हम पोजीशन में होंगे।

इसके अलावा जहां तक प्रश्न नीम व उदयपुर लाइन का है, और कोटा अजमेर का है जो कि अब भीलवाड़ा अजमेर हो गई है इसके लिये भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कि जो इण्डियन स्टील है वह हमको टाटाज़ से और इण्डियन आयरन कम्पनी से, थ्रू दी आयरन स्टील कन्ट्रोलर हमको जल्दी से जल्दी अलोकेट हो जावे ताकि उसके टावर्स बनने शुरू होकर इस रूट पर लग जावें। हमारी कोशिश यह है कि जहां तक इन दोनों लाइनों का प्रश्न नीमच, उदयपुर का वारिश के बाद हम जो हैं फाउन्डेशन के काम को कम से कम शुरू कर दें ताकि टॉवर बन कर आ जावें तो जल्दी से जल्दी उनको खड़ा करके लाइन को लगाकर उसे इनेर्जाइज़ कर दें।

(१. म. प.)

कोटा और गांधीसागर के अलावा लोकल डिस्ट्रिब्यूशन लाइन का काम भी शुरू करवा दिया गया है। कोटा से बूंदी का काम चल रहा है। पोल्स लग गये हैं, क्रोस आर्म्स लग गये हैं और उन पर इन्सुलेटर भी लग गये हैं। इसके अलावा भानपुरा से भवानीमण्डी की लाइन का काम भी शुरू हो गया है, झालावाड़ रोड से रामगंजमण्डी का काम भी शुरू हो गया है।

तो मेरा यह अनुमान है कि साल के आखीर तक हम कोटा के साथ-साथ भवानी-

(श्री हरिश्चन्द्र)

मण्डी, रामगंजमण्डी झालावाड, उनको भी इनेर्जाइज़ कर लेंगे ।

अब जहां तक तीसरी योजना का सवाल है इसके सिलसिले में मुझे आपके सामने चन्द बातें रखनी हैं। इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा कि राजस्थान में अनएम्प्लोयमेंट को रिड्यूस करने के लिये और इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये पॉवर की निहायत जरूरत है और इस बात की जिम्मेदारी लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पॉवर स्ट्रक्चर ठीक तौर से काम नहीं करता है तो राजस्थान का डेवलपमेंट पीछे रह जायेगा और इसको देखते हुए ही हम तीसरी प्लान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक कि पॉवर डिपार्टमेंट का सवाल है हम हर चन्द इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी शिड्यूल हमने बनाया है उसके मुताबिक हम हमारी प्लान को और काम को एग्जीक्यूट करें।

जहां तक तीसरी योजना का सवाल है टोटल प्लान का आउट ले ४५ करोड़ का हमारा है। मैं मान सकता हूं कि यह हाईएस्ट एलोकेशन हमें मिला है पॉवर के लिये। पर ये भी फिगर्स टेन्टेटिव फिगर्स हैं। अगर ये फिगर्स आखीर में जाकर और रिड्यूस होते हैं तो हमारे राजस्थान की प्रोग्रेस जितनी तेजी से हम करने की सोच रहे हैं, नहीं हो पावेगी।

४५ करोड़ रुपये की जो ब्रेक-अप वेल्यू है वह आप लोगों के सामने सर्कुलेट हो गई है। उसमें से मैं आपके सामने सिर्फ चन्द बातें रखना चाहूंगा। जहां तक भाखरा का सवाल है हमने ८३४.५० लाख रुपये भाखरा के लिए एलोकेट किये हैं। भाखरा का जब राइट विंग चालू होगा उस समय राजस्थान में २८ हजार किलोवाट पॉवर मिलेगी।

28 thousand klwt, in addition to the 25 thousand klwt which has been sanctioned. तो २८ हजार वह और २५ हजार यह, इसको यूटीलाइज़ करने के लिए और भाखरा में जो पैसा लगेगा उसका पेमेंट करने के लिए हमने ८३४.५० लाख रुपया थर्ड फाइव इयर प्लान में रखा है। इसके अलावा १,५८४.६२५ लाख चम्बल के लिए रखे है विच इन्क्यूलड्स राणाप्रतापसागर एज़ वैल एज़ कोटा डैम" क्योंकि जब तक कोटा डैम और राणाप्रताप सागर फुल्ली डेवलप होकर राजस्थान को पॉवर सप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमारे राजस्थान का इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और एनी अदर डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस बात की बहुत जरूरत है कि थर्ड फाइव इयर प्लान के आखिर तक कम से कम हमारा राणाप्रतापसागर चालू हो जाना चाहिए और उसके नीयर फ्यूचर में ही कोटा डैम भी चालू हो जाना चाहिए। अब सदन के सामने बड़ा भारी प्रश्न यह है कि १९६२ से लेकर जब तक राणाप्रतापसागर एनर्जाइज़ नहीं होता है उस समय के लिए हम क्या करें क्योंकि जैसा कि आपके सामने मिनिस्टर फोर इन्डस्ट्रीज़ कहेंगे कि पॉवर की इतनी डिमाण्ड आ रही है कि हम उसको कोप विथ

Page No.48

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं कर पा रहे हैं । इस समय विलेजेज़ में जाते हैं तो एग्रीकल्चरल लोड के लिए पॉवर की जरूरत है, इन्डस्ट्रियल सेक्टर के लिए पॉवर की ज्यादा मांग है; तो पॉवर की डिमान्ड राजस्थान में इतनी ग्रो हो रही है, इतनी बढ़ रही है कि हम हमारे टार्गेट्स को १९६२ से लेकर १९६४ तक का जो पीरियड है, इसको कैसे मीट करें; उसके लिए जो आपके सामने प्लॉन सर्कुलेट हुआ है उसमें हमने स्टीम टर्बाइन्स के लिए प्रपोज़ किया है। हम सवाई माधोपुर या कोटा दोनों जगहों में से एक जगह के ऊपर ३ सैटस ३० हज़ार किलोवाट के लगायेंगे और इसी तरह से हनुमानगढ़ में दो सैटस ३० हजार किलोवाट के लगायेंगे। तो यह आपके सामने यों मिलकर ६० और ३०; यों आपके सामने कुल ९० मैगावाट तो सवाई माधोपुर में लगा और ६० मैगावाट यानि ६० हज़ार किलोवाट हनुमानगढ़ में लगेगा। यह तो हमारे स्टीम टर्बाइन का प्रपोज़ल है और यह हमने इसलिए बनाया है कि जो ६२ और ६४ के बीच के टाइम में पॉवर की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए यह टर्बाइन सैट बहुत जरूरी है। जब ये लग जायेंगे तो हमारी जो ६२ और ६४ के बीच की डिमाण्ड होगी वह इनसे फुलफिल हो जायेगी। उसके बाद में राणा प्रतापसागर और कोटा डैम की स्कीम पूरी हो जायेगी और उसके बाद जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इस बात की कोशिश की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि शायद सेन्ट्रल गवर्नमेंट राजस्थान को एक एटोमिक स्टेशन भी दे, ताकि हमारी जो पॉवर की डिमाण्ड है वह जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। इसके अलावा जो आपके सामने प्लान है उसमें टोकन प्रोवीज़न फोर लिग्नाइट प्लॉन्ट्स भी रखा है। यह टोकन प्रावीज़न इसलिए रखा गया है कि इसके ऊपर एक्सपेरीमेंट हो रहा है और देखा जा रहा है कि लिगनाइट के द्वारा हम इस पॉवर को युटीलाइज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यह टोकन प्रोवीज़न फोर लिगनाइट प्लान्ट भी रखा गया है। इसके अलावा माही के लिए एक प्लान्ट प्रोवीज़न रखा गया है। माही से जो बिजली पैदा होगी वह डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरे इलाके के लिए हाईडल पॉवर मिल सकती है। इसके अलावा हमने १३ हजार ९०० किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए डीज़ल सैट का प्रोवीज़न किया है। वह इसलिए किया है कि कई ऐसी जगह आपको राजस्थान में मिलेंगी कि जहां हाईडल पॉवर नहीं पहुंच सकती है, टर्बाइन की पॉवर नहीं पहुँच सकती है और वहां पर लोड जो है वह डेवलप हो रहा है और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए १३,९०० किलोवाट डीज़ल सैट से प्रोड्यूज़ करने का प्रोवीज़न किया है और हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जहां जहां भी इस तरह के एग्रीकल्चर के लोड हैं या इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लोड हैं उनको हम इनके द्वारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह भी मैं समझता हूँ कि हमारा एक कदम आगे ही है कि ऐसे गांव कि जहां कुए हैं और कुओं का लोड मिल सकता है और ऐसी जगह हैं कि जहां हाईडल पॉवर भी नहीं ली जा सकती है, स्टीम टर्बाइन के द्वारा भी पॉवर नहीं पहुँच सकती है, तो ऐसी जगह पर हमने डीज़ल सैट लगाकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह प्रावधान रखा है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

थर्ड फाइव इयर प्लान में जो डीज़ल पॉवर डेवलप होगी जो प्लान में रखी गई है वह है १५३ मैगावाट और डीज़ल की है १३.६० मैगावाट, यों करके १६६.६० मैगावाट डेवलप होगी। इसके अलावा हाईडल जो है वह १६७.५० होगी। यों डीज़ल ३३४.४० मैगावाट थर्ड फाइव इयर प्लान में सोचते हैं कि हम जेनरेट कर पायेंगे। इसके अलावा मैं साथ ही साथ थोड़ा सा रोड प्लान के बारे में भी कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : जी हां, संक्षेप में वह भी बता दें।

श्री हरिश्चन्द्र : रोड के सिलसिले में भी मैं हाउस के सामने कुछ बातें पेश करना चाहूंगा। पॉवर का जहां तक सवाल है मैंने उसका आउटले हाउस के सामने रख दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के जो मेम्बरान हैं....

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्री महोदय क्लियर कर दें ,अभी एग्रीकल्चर के काम के लिए बिजली की बात बताई। तो जो १०,००० की आबादी या १०,००० से कम की आबादी वाले गांव होंगे उनको एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए बिजली देंगे तो वह कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने थर्ड फाइव इयर प्लान के प्रारूप में पढ़ा होगा कि हर ५००० की आबादी वाले गांव को लाइट देंगे।

श्री रामकरणसिंह : कब तक देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान में दे देंगे। थर्ड फाइव इयर प्लान के आखिर तक हर ५००० के विलेज को लाइट सप्लाई करेंगे, यह हमने फर्म डिसीज़न लिया है और उसी के अनुसार चल रहे हैं। जहां तक पॉवर का सवाल है और उसके एक्सपेन्शन के लिए कहा है तो उसके लिए निवेदन करना है कि हमारे सामने जो डिफिकल्टी आ रही है वह दो चीजों की है; एक तो पोल की। पोल का जहां तक सवाल है हमने रेल्वे ऑथोरिटी और रेल्वे बोर्ड को लिखा है कि वह जल्दी से जल्दी हमें पोल्स रिलीज़ करे और मुझे आशा है कि वह अक्टूबर के आखिर तक हमारे यहां पर रेल आने लग जायेगी कम से कम १००० रेल एक महीने में तो आ ही जायेंगी तो जब यह प्रोवीज़न हो जायेगा तो जहां तक हमारा लाइन्स ले जाने का एक्सपेन्शन है उसमें थोड़ी बहुत सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा दूसरी जो डिफिकल्टी है हमारे सामने वह यह है कि हमें ट्रान्सफार्मर्स नहीं मिल रहे हैं। जो बेंगलौर में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए हमने ८०० या १००० का ऑर्डर भी प्लेस कर रखा है जब वह रिलीज़ होकर राजस्थान में आयेंगे तो जैसा मैंने कहा कि दो-तीन जगह लाइन लग चुकी हैं और ट्रान्सफार्मर्स नहीं लगे हैं तो उनके आने के बाद जो जो आइडिया है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पॉवर मिलनी चाहिए उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हम कामयाब हो सकेंगे; मगर यह दो ढाई महीने की अभी हमको देरी हो रही है। हमको पोल्स नहीं मिल रहे हैं

(श्री हरिश्चन्द्र)

ट्रांसफार्मर्स नहीं मिल रहे हैं, इनके मिलने तक हमें टाइम लग जायेगा ।

श्री सम्पतराम जैन (अकलेरा) : तीसरी पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ और भवानी मंडी में बिजली मिलने की व्यवस्था है तथा क्या झालावाड़ के और स्थानों में भी बिजली मिलेगी, इस योजना काल में ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस विषय में पी० डब्ल्यू० डी० ने लोड सर्वे की है और उसके बाद अगर लोड के आंकड़े जस्टीफाई करेंगे और वहां लाइन ले जा सकते हैं तो अवश्य लाइन ले जाई जायेगी ।

जहां तक कि रोड का सवाल है सैकिंड फाइव इयर प्लान में जो टोटल आउटले बिगिनिंग आफ दी सैकिंड फाइव इयर प्लान था वह ८६६ का था. उसके बाद १-११-५६ को जब अजमेर मर्ज हुआ तो जो टोटल प्लान बना वह ६४१.५ लेक्स का प्रोविज़न किया गया, जो फिगर, रिवाइज्ड फिगर सैंक्शन हुई वह ६४३.० लेक्स की टोटल सैंक्शन हुई । जब उसका जो ब्रेक अप आया ६५३ का वह इस प्रकार है कि स्टेट रोड ७७८.४८, रोड इन भाखरा ७४.६७, अप्रोच रोड्स ४४.७६, अप्रोच रोड्स टू माइन्स एन्ड क्वेरीज़ १.०६ सी. डी. वर्क्स ३.०३, टोटल ६५३.३३....

श्री रामचन्द्र : यह थाउजेन्ड में है या लेक्स में ?

श्री हरिश्चन्द्र : लेक्स में है ।

अब इसके साथ ही साथ अपने थर्ड फाइव इयर प्लान को कंसीडर करें तो मैं सदन के सामने यह पेश करना चाहूंगा कि अचीवमेंट्स क्या हैं । जयपुर में ओरिजिनल प्लान के लिए ५५.७८ लेक्स रखा गया था और सैकिंड फाइव इयर प्लान के अन्त तक ६०.६४ लेक्स खर्च हो जायेगा और २६४ एन्ड हाफ माइल्स कंस्ट्रक्शन होगी या इम्प्रूवमेंट होगा, यह इम्प्रूव्ड एन्ड ओरिजिनल कम्बाइन्ड है । झुंझुनूं में २३.४७ ओरिजिनल प्लान का था उसके अगेंस्ट २३.४८ और कुल माइल ८४ एन्ड हाफ । सीकर में जो है वह ५५.६६ वाज ओरिजिनल फिगर एन्ड अप टू दी एन्ड आफ सैकिंड फाइव इयर प्लान ५२.६५, टोटल माइलेज २३५. यह मैं टोटल रोड्स पेश कर रहा हूं । इसमें प्रपोज्ड रोड्स एज़ वेल एज़ इम्प्रूव्ड रोड्स हैं ।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय मंत्री महोदय बतावें कि अप्रूव्ड रोड्स जो हैं उनमें अप्रोच रोड्स भी शामिल हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : भरतपुर में ३५, अलवर में ३०.०७ था ओरिजिनल और ४०.१२ खर्च कर देंगे और....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सारे डिस्ट्रिक्टवाइज़ फिगर्स बतायेंगे तो बहुत समय लग जायेगा और ये फिगर्स तो लिखित में भी बांटे जा सकते हैं मेम्बर्स में । जो कोई विशेष बात बहस के दौरान में आई हो और उनका स्पष्टीकरण करना हो तो प्राथमिकता से कह दें तो उचित होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इस तरह संक्षेप में सदन के सामने पेश करूंगा कि ओरिजिनल फिज़िकल टार्जेट जो हमारा था वह था २७०८ माइल और १६४२ माइल्स प्रपोज्ड था। इस सैकिंड फाइव इयर प्लान के अन्त में जो ओरिजिनल वर्क हुआ है वह १४६७ माइल्स पर हुआ है और इम्प्रूवमेंट होगा १५७७ माइल और इस ६०-६१ में ६७३ माइल्स जो हैं ओरिजिनल वर्क होगा और इम्प्रूवमेंट ३६७ माइल्स का होगा। तो यह जो शोर्ट फाल है इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि लेबर की कोस्ट बढ़ने से और मेटीरियल की कोस्ट बढ़ने से यह जरा बहुत फिज़िकल टार्गेट कम हुआ है, यही इसका सबब है। जहां तक थर्ड फाइव इयर प्लान का सवाल है इसके लिए मुझे यह निवेदन करना है कि जो फिगर्स सदन के सामने सर्कुलेट हुए हैं से १८ करोड़ की है लेकिन अभी यह टैंटेटिव फिगर है। यह फिगर बढ़ती है या घटती है यह हमको जो है प्लानिंग कमीशन से जब एलोकेट होगा बातचीत करने के बाद, तब यह मालूम होगा कि ये फिगर्स कहां तक स्टैंड करते हैं। तब भी हमने १८ करोड़ रोड्स के लिए प्रपोज़ल फ्रेम किए हैं। इस १८ करोड़ का डिस्ट्रिब्यूशन जो है वह इस तरह से होगा :

रोड्स इन भाखरा कमान्ड एन्ड राजस्थान कैनाल एरिया १.७५ करोड्स। रोड्स इन चम्बल एरिया १.६ करोड्स स्टेट हाइवेज़ १.७८ करोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स १.८१ करोर्डर्स माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स ७.२७ करोड्स माइनर सी. डी. वर्क्स १.६४ करोड्स रोड्स टू माइन्सक्वेरी ०.४५, अप्रोच रोड्स टाउन्स एन्ड विलेजेज़ १.५० । यह ग्रान्ट जो है यह ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जायेगी। हर पंचायत समिति को ३५०००) रु० तृतीय पंचवर्षीय योजना में अप्रोच रोड्स बनाने के लिए दिया जायेगा। इस बात की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम अप्रोच रोड्स और श्रमदान की निकाली है जिसके अन्दर फिफ्टी पर्सेन्ट मदद वे देते हैं, उसके लिए भी यह कोशिश की जा रही है कि ३५०००) रुपया जो स्टेट देगी इसको वह कंट्रीब्यूशन मान कर इक्वल अमाउन्ट का श्रमदान होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और ग्रान्ट दे ताकि हर पंचायत को और रुपया मिल सके। पहले जो प्रोविज़न किया गया था वह बहुत ज्यादा था लेकिन प्लान की सीलिंग श्रिंक होने से यह स्कीम भी श्रिंक हुई है।

तो हर पंचायत समिति को ३५,०००) रु० सड़कों के लिए एप्रोच रोड्स के लिये दिये जायेंगे।

इसके अलावा सी० डी० वर्क्स में एप्रोच रोड्स पर ·६५ और ·३२ टूल्स एन्ड इम्प्लीमेंट्स पर है।

इन्टर स्टेट्स रोड्स पर ·२५ है। पहले इंन्टर स्टेट्स रोड्स का प्रोवीज़न नहीं था। यह नया प्रोवीज़न क्रियेट किया गया है इस वास्ते कि कई ऐसी सड़कें हैं जैसे पंजाब से अपनी सरहद मिलती है। वह कई दफा एप्रोच रोड बना देते हैं अपनी सरहद तक और अपन नहीं बना पाते हैं। इसलिए यह प्रावधान किया गया है जिससे बोर्डर टाउन्स पर इन्टर स्टेट्स कॉम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यह पैसा खर्च किया जायगा। इसके अन्दर ·२५ रखा है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

थर्ड फाइव इअर प्लान में जो अनुमान किया जाता है प्रेजेन्ट प्राइस लेवल को देखते हुए, फिगर्स को देखते हुए, वह यह है कि मैटल्ड रोड्स जो हैं हम थर्ड फाइव इअर प्लान में नई १६७५ माइल्स कन्स्ट्रक्ट कर लेंगे और पेन्टेड रोड्स जो हैं ५६६ माइल्स हम और बना देंगे और ग्रेवल्ड रोड्स जो हैं ६२६ माइल्स का कन्स्ट्रक्शन करेंगे। यों करके ३४७० माइल्स की नई रोड्स को हम कन्स्ट्रक्ट थर्ड फाइव इयर प्लान में करने जा रहे हैं।

इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्ज़िस्टिंग रोड्स के अन्दर भी यह रखा है। बीचमेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्ड रोड्स ११०६ माइल्स, मेटलिंग ऑफ ग्रेवल्ड रोड्स एन्ड फेअर वेदर रोड ३१० माइल्स, ग्रेवलिंग ऑफ फेअर वेदर रोड १३० मील, टोटल १५४६। देट मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्ज़िस्टिंग रोड्स। तो यह जो है, मैंने सदन के सामने पेश किया है और मुझे आशा है कि सदन इस बात को मन्जूर करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूछना चाहता हूं!

श्री अध्यक्ष : पूछिये!

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : केबिनेट मीटिंग्स में जिस जिस रोड को मैटल्ड रोड बनाने का डिसीज़न लिया है क्या उसको इसमें इन्क्लूड कर दिया जायगा?

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब जो है वह जालोर–सांचोर रोड के लिए है। उसके लिए मैंने आज ही आपसे बात की है। मैं समझता था कि आप इस बात पर विचार करेंगे और मुझे बतायेंगे कि क्या करना है। मगर मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि पूरी रोड को मेटल्ड और बीचमेंट ट्रीटमेंट बनाते हैं तो वह ३३ मील लम्बी सड़क है, तो इसमें कम से कम ३३–३४ लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो मैं केबिनेट डिसीज़न के विरुद्ध यह नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूरी है कि या तो आप उस सड़क को बना लें और बाकी सड़कों को हम बन्द कर दें तो आपकी यह सड़क बन सकती है। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि ३४–३५ लाख रुपया उस पर ही खर्च हो और बाकी और भी जालोर की सारी सड़के हैं। लेकिन यह मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो पैसा है उसको देखते हुए खर्च नहीं कर पायेंगे। यह आपके ऊपर डिसीज़न है कि क्या लेना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, केबिनेट ने यह उचित समझा है....

श्री अध्यक्ष : बहस का सवाल नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते इस मौके पर।

माननीय सदस्य, कृपया १०–१५ मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, हम पिछले २ दिनों से इस राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं। इस संबन्ध में जो माननीय मुख्य मंत्री ने संबंधित सूचनाएं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

-दीं और जो साहित्य यहां पर वितरित किया गया वह काफी आशाजनक और उत्साहवर्धक है। लेकिन यदि जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किये हैं और जिस तरह का इसमें प्रावधान किया गया है यदि ये तमाम सुख-सुविधाएं जुटाने की भावना वास्तव में वैसे ही क्रियान्वित हो जाती हैं तो, मैं समझता हूं, हमारा राज्य बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। जो हमारे सामने आंकड़े दिये हैं कि किस किस मद में क्या क्या व्यय होगा इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसके अनुसार हम उन मदों के महत्व को समझ सकते हैं कि हमारे राज्य के लिए किन किन चीजों का कितना महत्व है। हमारे सामने इस संबंध के जो आंकड़े आये हैं उसमें सबसे ज्यादा व्यय विद्युत् पर, बिजली पर, खर्च करने का इसमें दिखलाया है। बिजली का इस राज्य में कितना महत्व है, उसकी कितनी आवश्यकता है, इस संबंध में हमारे संबंधित मंत्री महोदय बहुत कुछ प्रकाश डाल चुके हैं।

१.३० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा भी यह विश्वास है और सारा सदन इस बात में मुझसे सहमत होगा कि बिजली हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। वह केवल इसलिए नहीं कि बिजली के पंखों के नीचे हम लोग बैठते हैं, या बिजली की रोशनी में हम लोग पढ़ते हैं, बल्कि आज मैं समझता हूं कि बिजली जन जीवन के संबंध में बड़ी ही आवश्यक हो चुकी है और खासतौर से हमारे किसानों के लिए आज बिजली की बहुत जरूरत है, छोटे-बड़े उद्योगधन्धों में बिजली की बहुत जरूरत है। लेकिन इस बिजली का फायदा इन तमाम कामों में तभी हो सकता है जब कि बिजली की दरें कम की जायं। खाली बिजली उपलब्ध कराने से ही काम नहीं चलेगा। बिजली के संबंध में मैं तो यही सुझाव दूंगा कि कोशिश की जानी चाहिए कि बिजली जिस प्रकार से बम्बई, मैसूर और दूसरे दूसरे राज्यों में जहां २ पैसे युनिट पर मिलती है अथवा कम या ज्यादा इसी के बराबर होता है, उतनी ही सस्ती बिजली यदि हमारे राज्य में मिलती है तो किसान भी फायदा उठा सकता है और छोटे उद्योग-धन्धे भी उससे चल सकते हैं और तभी हमारे राज्य का पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए बिजली के संबंध में मैं केवल इतना ही सुझाव दूंगा कि बिजली की दरें सस्ती की जायं।

उसके बाद राज्य की जो दूसरी बड़ी आवश्यकता है वह है सिंचाई की। सिंचाई भी हमारे राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और वह इसलिए कि हमारे राज्य में ऐसे साधन प्रकृति ने नहीं दिये हैं कि जिनसे हम अपने राज्य को पंजाब या यू० पी० या बिहार या दूसरे उन राज्यों की तुलना में ला सकें जहां कि हमेशा बहने वाली नदियां बहती हैं। हमारे राज्यों में केवल एक ऐसी नदी है जिसको बारहमासी नदी कह सकते हैं और वह है चम्बल और चम्बल के अतिरिक्त जितनी नदियां हमारे राज्य में हैं, ज्यादातर बरसाती नदियां हैं। इसलिए यदि इस राज्य की भूमि को उर्वरा बनाना है और इस भूमि पर अधिक अन्न उत्पन्न करना है तो हमें सिंचाई के साधन बढ़ाने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

होंगे । यह एक बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है तथा हमारे राज्य के लिए एक अनुपम देन है कि यहां पर राजस्थान केनाल जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी नहर होने का दावा करती है, बनने जा रही है। उसके संबंध में सदन में कई माननीय सदस्यों ने यह बतलाया है कि उसका भार हमारे राज्य पर न होकर वह सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार ले, क्योंकि उसका असली लाभ राजस्थान को तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त सारे देश को काफी लाभ मिलने वाला है।

लेकिन हमारे राज्य के लिये इन सब से और भी अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वह है-कृषि । तो कृषि के संबंध में कुछ विस्तार से बातें कहूंगा । यद्यपि आंकड़ों की दृष्टि से कृषि का नम्बर चौथा या पांचवां आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि कृषि के उत्पादन की हमारे राज्य में और भी अधिक बढ़ने की जरूरत है और वह बढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं कि हमारे राज्य में खाद्यान्न का अभाव है, यह तो सौभाग्य की बात है और हमको जो साहित्य वितरित किया गया है उसमें भी यह बतलाया गया है कि हमारा राज्य न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो चुका है, बल्कि वह अब बाहर निर्यात भी करने लगा है । लेकिन मैं इस बात की ओर इंगित करता हूं कि हमारे देश में केवल राजस्थान ही एक राज्य नहीं है । हमारा देश बहुत बड़ा है और जब तक हमारे देश में अन्न का अभाव रहता है, राजस्थान को यह अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि वह देश के खाद्यान्न की पूर्ति अपनी ओर से करे । इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे देश के खाद्यान्न की जो स्थिति है वह राजस्थान सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार अपने ऊपर ले । जैसा कि अभी हम यह कह चुके हैं कि जो राजस्थान नहर बनने जा रही है उससे हमारे राज्य का खाद्यान्न उत्पादन बहुत बढ़ेगा और उसका असर इस राज्य के अतिरिक्त सारे देश पर होगा । तो मैं यह बताना चाहता हूं कि और भी कितने ही साधन इस राज्य में ऐसे हो सकते हैं जिनका खाद्यान्न पर प्रभाव पड़े ।

हमारे सामने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रखा गया है उसमें कई रिपोर्टों का वर्णन है जो इस राज्य के साधनों पर असर करने के लिये अपनाई गई । यद्यपि इस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट का वर्णन नहीं मिला कि यहां की भूसर्वेक्षण के लिये राज्य ने क्या किया और कितनी भूमि ऐसी है जो अभी कल्टीवेशन में या कृषि में आ चुकी है और कितनी बाकी है । मैं समझता हूं सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस संबंध में संकेत था । मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में ऐसी कितनी ही भूमि है जिसको अंडर कल्टीवेशन नहीं लिया गया है । मैं तो राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को यह कहना चाहूंगा कि यदि वे इस देश की खाद्यान्न समस्या को हल करना चाहते हैं तो राजस्थान में जो हजारों और लाखों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है उसको उर्वरा बनाया जाय तो खाद्यान्न की समस्या हल हो सकती है । हमारे राज्य में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जिसको रेगिस्तान या मरूभूमि कहते हैं । आज विज्ञान तरक्की कर रहा है । इसलिये इस तमाम भूमि को

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सिंचित किया जाय तो मुझे विश्वास है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। अभी मैंने पढ़ा था कि जैसलमेर के मरुस्थल में ५ स्थानों पर बहुत पानी मिला है। तेल की खोज में अन्वेषक लोग जाते हैं तो उनको तेल के स्थान पर पानी मिलता है। मैं समझता हूं जैसलमेर में पानी मिलना तेल की अपेक्षा अधिक कीमती है, खाली प्यास बुझाने के लिये ही नहीं बल्कि भूमि को उर्वरा बनाने के लिये यह आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि कुछ यंत्र और अन्वेषक वहां भेजे जाने चाहिये जो अंडर ग्राउन्ड पानी निकालने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हो सकते, लेकिन भारत सरकार अधिक साधन सम्पन्न है और खाद्यान्न के लिये कितने ही करोड़ रुपये बाहर भेजती है, फोरिन एक्सचेन्ज जाता है। कितना अच्छा हो कि राजस्थान में वह रुपया लगाया जाय।

इसी तरह से एक नयी चीज़ की ओर उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह यह है कि हमारे राज्य में कितनी ही भूमि नदियों के किनारे ऐसी है, खास करके चंबल के किनारे, मेरे पड़ौस में करौली और धौलपुर में बड़े बड़े टीबे हैं जिनको खादर या रेवाइन्स कहते हैं। वे ऐसे हैं कि यदि इनकी तलाश की जाय तो कितनी ही हजारों या कितनी ही लाखों एकड़ भूमि निकल सकती है जिनके बारे में राष्ट्रपति ने भी संकेत किया था कि बड़े बड़े टीले पड़े हैं, उनको यदि समतल बना कर कृषि योग्य बनावें तो खाद्य की समस्या हल हो सकती है। बुल्डोजर आदि के जरिये इनको समतल बनाया जा सकता है। उससे केवल खाद्य समस्या ही हल नहीं होगी बल्कि मैं विश्वास करता हूं कि डाकू समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार की पुलिस प्रयत्न करती है और जिसको हल करने के लिये संत विनोबाजी भी प्रयत्नशील हैं, उसका हल भी इसके द्वारा हो सकता है। यदि चंबल के किनारे जो खादर हैं उनको समतल कर दिया जाता है, खड्डों को पाट कर बराबर कर दिया जाता है तो डाकुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यह भी एक ऐसा काम है जिसको राज्य सरकार नहीं कर सकती क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये व्यय होंगे लेकिन यह उपयोगी सिद्ध होगा। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार के पास जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े लेकर जावें तो यह भी सुझाव लेकर जावें कि इस तरह से हम हमारी भूमि को अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली कर सकते हैं।

हमारे सामने जो पुस्तक आई है उसमें बताया है कि हमारे राज्य में ८१.८२ फी सदी लोग गांवों में रहते हैं और केवल १८.१६ फी सदी लोग शहरों में रहते हैं। यदि हम लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और पर केपिटा इन्कम की बात करते हैं और उसको ऊंचा करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की ओर जाना चाहिये। हम शहरों में बड़े बड़े उद्योग और इन्जिन लगाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो मैं साथ ही साथ गांवों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

समय क्योंकि थोड़ा है, मैं थोड़े समय

Page No.56

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मैं और भी चीजें बताऊंगा । इस सम्बन्ध में खास तौर से पशु-पालन की ओर ध्यान दिलाऊंगा । पशु-पालन की चीज बताई उसमें कुकुट, मुर्गे आदि का जिक्र किया है लेकिन मैं समझता हूँ गौ वंश के उत्थान की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया गया है । यह वह राज्य है जहां नागौरी गायें ऐसी हैं जो सारे देश में प्रसिद्ध रही हैं । आज भी उनके उत्थान के लिये जरूरत है । इसके लिये जो कुछ भी बजट है उसको ज्यादा से ज्यादा गौ-पालन और गौ संवर्धन की ओर लगावें और शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले, इस ओर प्रयत्नशील हों तो ज्यादा अच्छा हो ।

इसके साथ साथ मैं दूसरी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । उद्योग के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छोटे उद्योग को पनपाया जाय । हम बड़े बड़े उद्योग की बात करते हैं । उनसे उत्पादन बढ़ सकता है लेकिन उनसे लोगों की बेकारी नहीं मिटा सकते । गांवों के लोग खाली जमीन पर ही निर्भर नहीं रह सकते । हर गांव में कुम्हार होंगे, बढ़ई और दूसरे लोग भी होंगे, लोहार होते होंगे; आज उनसे उनका धंधा छूटता जा रहा है और वे शहरों की ओर आते जा रहे हैं । यह दुर्भाग्य की बात है । वे छोटे-छोटे धंधे अपने अपने गांवों में ही कर सकें, इसके लिये उनको सहायता देनी चाहिये ।

कुछ शब्द मैं शिक्षा के बारे में भी कहूंगा । यद्यपि शिक्षा के जो आंकड़े दिये गये हैं वे उत्साहवर्धक हैं । हमारे राज्य में शिक्षा का प्रसार और प्रचार काफी हो रहा है । लेकिन मैं एक चीज की कमी पा रहा हूं वह यह है कि शिक्षा पुरानी प्रणाली पर ही चली जा रही है । हमें स्वराज्य के अनन्तर जो शिक्षा देनी चाहिये थी उस ओर हमने कदम नहीं उठाया और खास कर शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी अत्यन्त आवश्यकता थी उस संस्कृत शिक्षा की ओर कुछ नहीं किया जा रहा है । इस मामले में राज्य सरकार ज्यादा कंजूस रही है केन्द्रीय सरकार से । जब हम पढ़ते है कि संस्कृत शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार क्या क्या खर्च करती है, बोर्ड बनाती है, विद्वानों को पुरस्कृत करती है लेकिन हम कितना काम करते हैं संस्कृत शिक्षा के लिये ? मैं केवल इसलिये नहीं कहता कि संस्कृत शिक्षा राज्य के लिये हो लेकिन देश की एकता के लिये इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है । हम हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं तो दक्षिण की ओर से उसका विरोध हो जाता है लेकिन संस्कृत ऐसी शिक्षा है कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी जायेंगे वहां संस्कृत समझने वाले हैं । हमारे राज्य में इसकी वृद्धि करने की आवश्यकता है । नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये भी संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता है । मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, दुःख होता है जब कि यह बतलाया तो जाता है कि हम संस्कृत के साथ भी एकसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हमारे अंग्रेजी के प्राध्यापकों और प्रवक्ताओं को जो वेतन शृंखला दी जाती है, वह संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों और प्रवक्ताओं को नहीं दी जाती । मैं इसको उदाहरण के साथ निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : I would like you to conclude please.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संस्कृत के लेक्चरार, जो संस्कृत कॉलेज में हिन्दी पढ़ाने, दूसरी चीजें पढ़ाने के लिए लेक्चार रखे जाते हैं, उनका वेतन हायर सैकन्डरी स्कूल के सीनियर टीचर के जितना भी नहीं होता है। जहां हायर-सैकन्डरी के सीनियर टीचर का वेतन २०० से प्रारम्भ होता है और कॉलेज के लेक्चरार का वेतन २५० से प्रारम्भ होता है, वहां संस्कृत कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, उनका वेतन १५०रु. से प्रारम्भ होता है। मैं समझता हूं, संस्कृत भाषा के साथ, देव वाणी के साथ राज्य सरकार इस प्रकार दुर्व्यवहार करती है, उसको, संस्कृत को प्रोत्साहन देना नहीं कह सकते। सरकार केवल रस्म के तौर पर संस्कृत का उद्धार करने की बात करती रही है। मैं चाहूंगा कि संस्कृत के लिए राज्य सरकार इस ओर विशेष प्रयत्नशील हो।

इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble Member please to conclude his debate. He has already taken 20 minutes whereas the time prescribed is 15 minutes.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दो मिनट में।

तो मैं यह बतला रहा हूं कि हमारे देश को, मैं यह नहीं कहता, एलोपैथी से लाभ नहीं है, लेकिन एलोपैथी अधिक सुलभ और सस्ती नहीं हो सकती। आज एक तरफ गांव गांव में उस चिकित्सा की सुविधा को पहुँचाने की बात करते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि दो मेडीकल कॉलेज और भी खोल दें तो भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते। मैं राज्य सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि औषधालयों की व्यवस्था करे, जब कभी जहां कहीं औषधालय खोलना चाहे, आपको वैद्य मिलेंगे। इसके अलावा लोगों को इस पर विश्वास है और वनस्पति और औषधि भी उपलब्ध होती हैं। इस तरह जो करोड़ों रुपया दवाइयों के लिए विदेशों में जाता है, वह देश में रहेगा। इसलिए आयुर्वेद की ओर जरूर ध्यान दें।

सड़कों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। नई सड़कें तो बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन पुरानी सड़कों के लिए इस पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र की सम्पत्ति सड़कें हैं।

(घंटी)

उनकी ओर कम ध्यान दिया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सड़कों की ओर ध्यान दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि सरकार, मैंने जो सुझाव रखे हैं, उन पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना आज अन्तिम रूप हाउस के अन्दर धारण कर रही है। योजना के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जो पहली बात सामने आती है वह

(श्री आबिद अली)

यह है कि राज्य सरकार के सामने रिसोर्सेज़ किस प्रकार के हैं। रिसोर्सेज की तरफ अगर राज्य सरकार या यह सदन ध्यान नहीं देता, तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्लान डिफेक्टिव रहता है, इन्कम्प्लीट रहता है। चुनाचे इन रिसोर्सेज की तरफ, जो आंकड़े राज्य सरकार ने लगाये है, मैं प्लान डिस्कस करने से पहले उनकी तरफ सदन का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। राज्य सरकार ने लिखा है :

"The Plan frame seems...

श्री उपाध्यक्ष : You are not audible to us. If you can fix up the mike.

श्री आबिद अली : I don't think this mike is in working order. I am coming over here.

(ध्वनि-विस्तारक यन्त्र के पास की बैठक पर आने के पश्चात् पुन:)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि रिसोर्सेज़ की तरफ हमारा खास तौर से ध्यान जाना चाहिए। अगर रिसोर्सेज को नहीं देखते हैं तो मेरी मान्यता ऐसी है कि हमारा प्लान डिफेक्टिव रहता है। अब हम रिसोर्सेज़ को देखते हैं, जो आंकड़े राज्य सरकार ने इस सदन को बताये हैं, उसमें मैं विशेषत: एक तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है एडीशनल टैक्सेशन एन्ड अदर रिसोर्सेज़, उसमें रखा है ३४,२३ करोड़। ३४.२३ करोड़ रुपया एडीशनल टैक्सेशन और अदर रिसोर्सेज़ से वसूल किया जायगा, ऐसी राज्य सरकार की पोलिसी है। जहां तक डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज़ का सम्बन्ध है, मैं यह जानता हूं और सदन के माननीय सदस्य यह जानते हैं कि टैक्सेशन के बगैर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी के अन्दर जो टैक्स पेअर हैं, वे जो कमाते हैं, उसमें से उनको टैक्स पे करना चाहिए। जब हम आम तौर से देखते हैं, साधारण तौर से देखते हैं तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि यह टैक्सेशन पब्लिक के ऊपर किस प्रकार का होगा और उस टैक्सेशन का असर अपर क्लास पर होगा, मिडिल क्लास पर होगा या लोअर क्लास पर होगा। अगर तीनों क्लासेज़ पर होता है तो इन तीनों में कौनसी क्लास ऐसी है जिस पर टैक्सेशन का असर ज्यादा होगा। एपेरेन्टली इन्कम टैक्स का सम्बन्ध सेन्ट्रल गवर्नमेंट से है। अब दूसरे टैक्स, जिस पर ध्यान जाता है, वह या तो इन्टोक्सीकेशन की चीजों पर, एक्साइज़ ड्यूटी, उसकी तरफ ध्यान जाता है, इसके बाद देखते हैं सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की तरफ ध्यान जाता है, फिर नजर जाती है कोर्ट्स की तरफ, रजिस्ट्रेशन की तरफ, स्टाम्प्स फी, कोर्ट फी जो लगाई जाती है, उसकी तरफ ध्यान जाता है। इससे आगे अगर हम जाते है, उपाध्यक्ष महोदय, बैटरमेंट लेवी की सूरत में एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान जाता है। यह टैक्सेशन की रूप-रेखा मैंने रखी है और निश्चित् रूप से मेरा मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, ३४.२३ करोड़ के टैक्स का डाइरेक्ट हिट होगा, वह लोअर क्लास पर होगा, या मिडिल क्लास पर होगा। मैं मानता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है, इसका असर अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर होता है। लेकिन जैसी अंग्रेजी की कहावत है, "Last straw over

Page No.59

(श्री आबिदअलि)

the back of the camel wrecks him."

ऐसा हो सकता है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन हो, ज्यादा बर्डन आफ टैक्सेशन हो। इसके साथ ही कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प फीस इसका बोझ लोअर व मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। मैं समझता हूं कि जहां ऊपर की क्लास का विश्वास डेमोक्रेसी के उपर जम सकता है, वह लोअर क्लास का विश्वास डेमोक्रेसी से हट जायगा। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हालांकि इसमें डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि ३४.२३ करोड़ का टैक्सेशन है, वह किस प्रकार रियलाइज़ किया जायगा, लेकिन जो यह रूप-रेखा सदन में रखी और सदन के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा बताई, उसमें एक रास्ता, आम तरीका यह होने वाला है, यह हो सकता है कि इसमें सारी क्लासेज़ का हिस्सा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जहां तक लोअर क्लास का ताल्लुक है, एग्रीकल्चर क्लास का सवाल है, लेबर क्लास का ताल्लुक है, अब उन पर टैक्सेशन का बर्डन न किया जाय, इसलिए कि अभी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट पास किया, उसमें पंचायत समितियों को अधिकार दिया है कि पंचायत समिति अपने क्षेत्र में टैक्स रियलाइज़ करके अपने खर्च को चलाये। इसके अलावा सेल्स टैक्स इम्पोज्ड हैं, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि पांच वर्ष पहले, निश्चित् तारीख नहीं कह सकता, एक रुपया १०० रुपये की रजिस्ट्री हो जाया करती थी, अब उसको डबल कर दिया है। जहां तक लिटिगेंट पब्लिक का सवाल है, डाइरेक्ट हिट लोअर क्लास, मिडिल क्लास पर होता है, स्टाम्प फी और कोर्ट फी देती है, वह भी यही क्लास देती है; सेल्स टैक्स भी देती है। मैं मानता हूं कि अपर क्लास देती है, लेकिन उस टैक्स का बर्डन भी लोअर क्लास पर है। इसलिए मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, जो टैक्स का रुपया लिया जाना है, इसको जरूर लिया जाय लेकिन इसको लेने का तरीका होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार मान कर चलता हूं कि जो ग्रामों में रहने वाले भाई हैं और जो अपर क्लास के लोग हैं, उनका कम्पेरिज़न करके देखिये, यह सही बात है कि इस देश को ऊंचा उठाने के लिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास ने जितना सहयोग दिया है, उतना अपर क्लास ने सहयोग नहीं दिया है। इसका सादा उदाहरण दूँ। एक गांव में बिल्डिंग बनती है ३० हजार की, तो ग्रामीण भाई ३० हजार का श्रमदान कर सकते हैं, जबकि अपर क्लास, मैं समझता हूँ दो हजार, तीन हजार तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, वकील हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनका कोई श्रमदान नहीं होता। आज हम देखते है कि श्रमदान और दूसरे कार्यों के लिये मिडिल क्लास में जो सेक्रीफाइस की भावना दिखाई देती है वह दूसरों में नहीं आ सकती। यह सही है कि वे लोग इन्कम टैक्स देते हैं, वह उन पर कोई बर्डन नहीं होता है। वे लोग हजारों रुपये कमाते हैं तो उस पर कुछ इन्कम टैक्स देते हैं तो यह कोई उन पर बर्डन नहीं होता है। मगर दूसरे लोगों को वे यह अपील करते हैं कि अगर अपने गांवों और देश को ऊंचा

(श्री आबिद अली)

उठाना चाहते हैं और जनता को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो श्रमदान करना चाहिये। मगर जब हम देखते हैं कि एक १००० जन-संख्या का गांव है और वहां पर श्रमदान के काम की बात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अपर क्लास के लोग श्रमदान देने में नहीं आते। जहां तक श्रमदान का ताल्लुक है, बड़े बड़े लोग उसमें भाग नहीं लेते जैसे जजेज़ हैं, वकील हैं, जैसे मैं ही हूं। हम कहने के लिये कह सकते हैं कि हम श्रमदान करते हैं लेकिन जहां एक्चुअली श्रमदान का प्रश्न आता है और श्रमदान करने का मौका आता है तो एक भी आदमी आपको ऐसा श्रमदान देने वाला नहीं मिलेगा जो वकील हो या बड़ा बिज़नेसमैन हो। श्रमदान देने में अपर क्लास बहुत कम है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लोअर क्लास में तो श्रमदान और लेबर कर सकते हैं और अपर क्लास के लिये यह हो कि साल भर में १५ दिन श्रम करें या १५ दिन का नोमिनल पैसा जो प्राप्त करता है उसको देना चाहिये। अगर ऐसा हो तो यह तो एक प्रकार की बड़ी अच्छी बात हो सकती है। अब यह हो सकता है कि अपर क्लास में टैक्सेशन एन्ड अदर मेजर्स का प्रश्न है यह हो सकता है। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार को ऐसी व्यवस्था इसमें करनी चाहिये कि जिससे ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है, वह बच जाए।

इस सम्बन्ध में, सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में कमिश्नरों की पोस्टों का सम्बन्ध है, वे हटा दी जावें। उनके पास कोई काम नहीं रहता है; ज़्यादा से ज्यादा वे कलेक्टर या एस. डी. ओ. से किसी को स्थानान्तर करना हो या किसी की नियुक्ति करनी हो तो वह कर सकता है। यह काम उनके पास है या कोई अपील करनी हो तो वह है। लेकिन आज माननीय उपाध्यक्ष, हमने रेवेन्यू बोर्ड की व्यवस्था कर रखी है। इस बोर्ड में एक आदमी नहीं, कई आदमी हैं। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बढ़ाया जाकर हम ५ पोस्टों को हटा सकते हैं। कमिश्नर एक इन्टरमीजियरी की तरह है। अगर आज हम कमिश्नर की पोस्टों को हटा देते हैं तो प्रश्न यह आता है कि राइट ऑफ अपील किसके पास रहेगा! हम जुडिशियरी की तरफ जाते हैं तो वहां पर अपील सिविल एन्ड डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास हो सकती है और उसके बाद में हाई-कोर्ट में जा सकते हैं। रेवेन्यू साइड में तहसीलदार और एस. डी. ओ. के फैसले की अपील कलेक्टर के पास जानी चाहिये लेकिन कमिश्नर के पद को कायम रखने के लिये उनके फैसले की अपील बजाय कलेक्टर के यहां जाने के एडीशनल कमिश्नर के यहां जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इनके पदों को तोड़ देंगे तो खर्चा कम होगा तो जहां तक कमिश्नरों की पोस्ट का सम्बन्ध है अगर ५ कमिश्नरों की पोस्टों को खत्म कर देते हैं तो आज जो हम एडीशनल टैक्सेशन की बातें करते हैं उसमें एक हद तक कमी आ सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको मन्जूर और एडॉप्ट करे तो मैं समझता हूं कि टैक्सेशन को बढ़ाने में एक हद तक कमी हो सकती है। इसी तरह से....

(कुछ ध्वनियें)

श्री उपाध्यक्ष : Will not be disturbed by the Hon'ble Member.

श्री आबिदअली : दूसरी बात मैं यह अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर ५ डिविज़न्स हैं। जब हम भारतवर्ष की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने भी पहले से डिविज़न कम कर दिये हैं तो क्या वजह है कि जब हमने हमारे यहां डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन किया है और आपने जनता को अपने अपने कामों के लिये रेस्पोन्सिबल बनाया है तो आज आपको ५ डिविज़न की क्या जरूरत है ? आज आप ५ डिविज़न्स के बजाय दो डिविज़न्स क्यों नहीं कर देते ? अगर आप दो डिविज़न्स कर देते हैं तो आपका कितना खर्चा कम हो जाता है और वह रुपया पंचवर्षीय योजना में काम आ सकता है। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन हो जाने के बाद, मेरा यह प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स है कि पहले कलेक्टरों के पास बहुत काम रहता था मगर अब उनके पास वह काम नहीं है। पहले वे काम से ओवर बर्डर्ड रहते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनके पास रहता था। लेकिन वह काम आज उनके पास नहीं है। जब कलेक्टर के पास भी इतना काम नहीं है तो फिर एडीशनल कमिश्नर के पास क्या काम है ? एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट का काम पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पास चला गया और अब कलेक्टर के पास क्या रह गया है ? अगर आप इस सम्बन्ध में हाउस का ट्रेन्ड देखें तो आपको मालूम होगा कि अभी हमारे यहां पर जितने जिले हैं उनको भी घटा कर १५ या १८ कर देते हैं तो भी काम ठीक तरह से चल सकता है और टैक्सेशन की बात समाप्त हो सकती है।

इसी तरह से दूसरा मेरा सुझाव जो है वह यह है कि जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है इस पर से बान हटाया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हमने तीन लाख टन अनाज अपने टारगेट से अधिक उत्पन्न किया है। यह हमारी सफलता की निशानी है और जब हमारी यह सरप्लस स्टेट हो गई धान के मामले में, तो निश्चित रूप से हमारे यहां से अन्न भारत के दूसरे हिस्सों में जाना चाहिये और उसके लिये राजस्थान सरकार द्वारा पर्मिट दिये जाते हैं और अनाज बाहर भेजा जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कार्य को राजस्थान सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? जिस तरह से नेशनेलाइजेशन की स्प्रिट है, इसको भी हाथ में ले लें। इससे क्या होगा कि जो होल्डिंग की संभावना है वह भी कम हो जावेगी। इससे दो एक्सपीरियेन्स होंगे और वे ये कि आज जो अन्न बाहर जावेगा उसकी व्यवस्था राजस्थान सरकार अपने हाथ में लेगी तो ब्लेक मार्केट समाप्त हो जावेगा और दूसरा राज्य सरकार का बिज़नेस ट्रेन्ड पैदा होगा और इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। यह मेरी निश्चित भावना है कि इससे सरकार को काफी फायदा पहुंच सकता है।

इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से काम हैं जिन पर मैं कहना चाहता हूं, लेकिन समय कम है। एक माननीय सदस्य ने बताया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी है। मैं यह कहूंगा कि हमारी जनता ८० प्रतिशत गांवों में निवास करती है और वे लोग खेती करते हैं इसलिये एग्रीकल्चर पर ज्यादा जोर देना है और उसको कामयाब बनाने के लिये प्रयत्न करने

(श्री आबिद अली)

और प्रोत्साहन देने की कोशिश करनी चाहिये ।

यह सही है कि द्वितीय प्लान में इसमें काफी वृद्धि हुई है और तीन लाख टन की जो बात कही जाती है, कि हमने टार्गेट से ज्यादा अन्न उत्पन्न किया है वह ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, निश्चित आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियेन्स है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे कि जहां तक गेहूं का मामला है, हमारे यहां राजस्थान में कम पैदा हुआ है। मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पर गेहूं की पैदावार कम होने का क्या कारण है, यह तो कृषि मंत्री बेटर जानते हैं लेकिन यह एक एसेन्शियल कोमोडिटी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये। हो सकता है कि डबल क्रोपिंग की वजह से यहां पर कोई कमी इसमें आई हो या यह हो सकता है कि लोगों ने दूसरी कॉमर्शियल क्रोप की खेती की हो। वे यह चाहते हों कि इसको पैदा करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो इसको मिटाने के लिये लैन्ड एक्विज़िशन एक्ट का फायदा उठाया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह गेहूं की कम पैदावार हमारे यहां पर क्यों हुई, इसको वे देखें। यह सही है कि अन्न दूसरी पंचवर्षीय योजना में टार्गेट से ज्यादा पैदा हुआ, लेकिन जब आप गेहूं की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि व्हीट में हम डेफिसिट में गये हैं। इसलिए मेरा कृषि मन्त्रीजी से यह सुझाव है कि कॉमर्शियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से लैंड का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसको मीट आउट करने के लिए लैंड एक्वीज़िशन एक्ट का फायदा लेना चाहिये।

२ म. प.

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर यह कही गई है कि जहां तक राजस्थान केनाल का सम्बन्ध है ४५ करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च करेगी और उसका लाभ दस वर्ष तक तो कोई मिलने की सम्भावना नहीं, अतः यह खर्चा बेकार है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह उनका किस प्रकार का दृष्टिकोण था ? मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करना चाहूंगा कि एक काश्तकार आम का वृक्ष लगा रहा था। एक राहगीर ने कहा कि तुम तो बूढ़े हो गये हो, आम तुम तो इसके नहीं खा सकोगे। उसने कहा कि मैं तो नहीं खा सकूंगा लेकिन यह मैं मेरे बेटे और पोतों के लिए लगा रहा हूं। पहले से ही माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान केनाल से आज हम फायदा उठा लें यह नहीं मान कर चलना चाहिये, किन्तु आगे आने वाली जो जेनरेशन है वह उसका फायदा उठायेगी और अभी से ही उस योजना को चालू करना आवश्यक है। इसलिये जो ४५ करोड़ का प्रावधान राजस्थान केनाल के लिए किया गया है वह वाजिब है और उसका उपयोग होगा राजस्थान के लिए। उन्होंने कहा कि कुओं के खोदने के लिए तकावी ज्यादा मिलनी चाहिये; जरा फीगर्स लें तो मैं मोटे से आंकड़ों में बता देना चाहता हूं कि कुओं से खेती मंहगी पड़ती है। दिन भर में आठ बीघा से अधिक की पिलाई एक कुएं से नहीं

(श्री आबिदअली)

होगी। उसके लिए दो आदमी होंगे, दो बैल होंगे, चरस और लाव की जरूरत पड़ेगी। यदि इसका टोटल ले लें तो निश्चित रूप से एक दिन के पिलाई के लिए ८ रुपयों का खर्चा होता है। उसके अगेन्स्ट में हम देखें कि केनाल का कितना सस्ता पड़ता है। उससे केनाल इर्रिगेशन से, खेती इकोनोमिक होती है। जहां तक कुओं से आबपाशी करने का ताल्लुक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, जरूर होना चाहिये लेकिन यदि केनाल के जरिये इर्रिगेशन होती है तो ज्यादा सस्ती और अच्छी होती है और इस ओर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिये जिससे कि काश्तकार पर ज्यादा बर्डन न पड़े। मेरा मानना तो ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी चाही जमीन काश्त करने वाले हैं, कुओं से काश्त करने वाले हैं उनकी इकोनोमिक कन्डीशन इसीलिए खराब होती है कि वे उन्हीं पर काबिज हैं, दूसरी ओर नहीं जाते। तो जहां तक राजस्थान केनाल का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ४५ करोड़ रुपया राजस्थान केनाल पर खर्चा किये जाने को है, वे कुओं पर लगा दिये जांय, यह जो आर्ग्युमेंट है वह कोई अच्छा आर्ग्युमेंट नहीं है। हमको केनाल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये, इससे किसान की माली हालत सुधरेगी, ज्यादा पैदावार भी होगी।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude within a minute.

श्री आबिद अली : उपाध्यक्ष महोदय, और बातों के साथ-साथ थोड़ा मुझे शिक्षा के विषय में भी हाउस के सामने विचार रखने हैं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। राजस्थान ने शिक्षा के माने में बहुत ज्यादा तरक्की की है। गांव गांव में शिक्षा का फैलाव कर दिया है। जो शिक्षा के फैलाव के लिए राजस्थान सरकार ने पहले टार्गेट्स रखे थे उनसे भी अधिक टार्गेट्स अचीव कर लिये गये हैं। राजस्थान सरकार को इतनी बधाई मिलनी चाहिये कि उससे पहले से भी बहुत ज्यादा जहां मिडिल स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले जाने थे उनसे भी अधिक मिडिल स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल खोल दिये हैं और सरकार इस माने में काफी सफल हुई है। जब हम तीसरी योजना बनाने जा रहे हैं तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे आज ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वे सीधे ही बाबू बनने की कोशिश करते हैं। बी. ए, बी. एस. स., एम. ए. डिग्री लेते हैं उनको पहले से उनकी रुचि के अनुसार टेक्निकल विषयों की ओर भेजने में काफी सहायता करनी चाहिये। मिसाल के तौर पर जैसा कि आज कल एग्रीकल्चरल की ओर विशेष ट्रेन्ड है तो मिडिल स्कूलों में ही पहले से एग्रीकल्चरल फार्म खोल देने चाहिए जो प्रेक्टिकल वे में वहां सीखेंगे वे थ्योरी से नहीं सीख सकेंगे। प्रेक्टिकल वे का असर उनके दिमाग पर ज्यादा पड़ता है। दूसरे और भी धन्धे हैं, कारपेन्टरी है, गृह उद्योग हैं। जो फील्ड में जाकर चीजें करते हैं उसका असर उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है। इसलिए जितनी व्यवस्था हम कर सकें

(श्री आबिदअली)

उतनी व्यवस्था मिडिल स्कूलों के स्टेन्डर्ड तक ही कर दें, एक फार्म हो जो सैल्फ सफिशियेन्ट हो । इससे मैं, समझता हूं, हम ज्यादा अचीव कर सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव, सिर्फ पांच मिनिट ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर मेरे मित्रों ने प्रकाश डाला । सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो तीसरी योजना का डिज़ाइन रखा है वह सही रूप से रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद में ही समय ज्यादा खर्च कर देंगे ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन करूं कि पहली पंचवर्षीय योजना....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण पढ़ा जा रहा है क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं ।

सबसे पहले यह निवेदन करूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०५ करोड़ का प्रावधान था । हमारे राजस्थान के माननीय नेता ने १०५ करोड़ का प्रावधान रखा और जब वह लागू हुई तो राज्य सरकार के अधिकारी उसको सफल बनाने में असफल रहे । आप तीसरी पंचवर्षीय योजना में २१२ करोड़ का प्रावधान है । यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना में २१२ करोड़ रुपया सब मदों में है तो हमारी सरकार के जो सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले अधिकारी हैं अपने दिमाग और दिल से काम करें तो राजस्थान को खुशहाल बना सकते हैं ।

वैसे मैं सड़कों की ओर ध्यान दिलाऊं कि एक सिटी से दूसरे सिटी को उत्पादन लाने, ले जाने, चलने फिरने के लिए सबसे पहले प्रदेश के रहने वाले नर-नारियों को सड़कों की जरूरत होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : भोपालसागर की सड़क के लिए रख दीजिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : वह नगर में नहीं आता ।

श्री हरिप्रसाद यादव : द्वितीय पंचवर्षीय योजना का करोड़ों रुपया लेप्स हो गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में रखेंगे उसको तो मैं निवेदन करूं कि करोड़ों रुपयों का प्रावधान इसमें भी रखा है । १८ करोड़ का प्लान है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दें, एप्रोच रोड, विलेज रोड का कार्य शुरू करें सरकार और यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और भी मदद लेना चाहें तो आपको हमको मिल सकती है । मैं आप से निवेदन करूं कि आज का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके लिए आपकी कृपा से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक अधिकारी है, ओवरसियर है वह सर्वे करने जायगा । छोटे से दस मील के टुकड़े का सर्वे करने में वह एक साल का समय

(श्री हरिप्रसाद यादव)

लगा देता है । इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि आपके विभाग से एक रिमाइन्डर उनको ऐसा मिले कि जिससे सर्वे का काम जल्दी हो जाय । किसी रोड का एस्टीमेट बन कर विभाग से सैंक्शन हो गई तो उसमें अधिक देर न हो और सफलता से जल्दी काम कराया जाय ।

दूसरा, पिछड़े वर्ग का सवाल है । जहां राजस्थान के सवर्ण और हरिजन दो भाइयों का कन्धा से कन्धा मिलने का प्रश्न है उसके लिए १॥-२ लाख रुपया रखा है । सरकार बधाई की पात्र है । लेकिन समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि वे अपने अधिकारियों से काम लें ताकि, मैं उदाहरण पेश करूं कि जैसे चतुर्वेदीजी और मैं कन्धे से कन्धा मिला कर मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी मिलाप नहीं हो रहा है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : सदन में मिलाप करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में मिलाप का प्रश्न नहीं होता, बाहर मिलें, यहां नहीं ।

श्री हरिप्रसाद यादव : आपका ध्यान अगर मैं खींचूं इस ओर कि हमारे राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं तो जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि फलां फलां जगह बिजली दे दी, माननीय मंत्री महोदय ने यह साफ साफ जाहिर नहीं किया कि कहां कहां कुओं को बिजली दी गई जिससे पानी खींचा जाता हो और आप कब तक ऐसी जगहों पर बिजली पहुँचा देंगे, यह बताया नहीं । आप जयपुर, जोधपुर इन बड़े शहरों में बिजली दे देते हैं तो क्या बड़ी बात है ? यहां तो पहले से ही बिजली है । बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो है, आप किन किन गांवों में कुओं के लिये दे रहे हैं यह बतलाइये ताकि जहां एक फसल होती है वहां दो फसलें हो सकें और इस तरह से हमारे देश का उत्पादन बढ़ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिप्रसाद यादव : दो मिनिट में सिंचाई के बारे में ही निवेदन कर दूं । आज जहां खेती के लिये पानी की जरूरत है वहां मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि बड़े बड़े दो तालाब बना दें ताकि इस दिशा में उत्पादन बढ़ सकता है ।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना का आज तीसरा दिन है, जो अन्तिम दिन है । सभी माननीय सदस्यों ने इसके मुत्तल्लिक अपने अपने विचार प्रगट किये हैं । मैं भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के बाबत कुछ निवेदन करना चाहूँगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सारे राजस्थान के संबंध में कहिये ।

Page No.66

रावराजा श्री सरदारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त, १६४७ को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सब लोग इस बात की आशा लगाये बैठे थे कि हमारे यहां की पूंजी जो विदेशों में जाकर लगती थी वह अब हमारे ही देश में लगेगी और इस पूंजी से इस देश के रहने वालों को सब को बराबर फायदा मिलेगा ! इसके बाद के अन्दर सन् १६५२ में प्रथम आम चुनाव हुआ उसके साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और इसी वर्ष से हमारे यहां इन पंचवर्षीय योजनाओं का श्री गणेश हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना, हमारा दूसरा चुनाव हुआ उस समय बनी । इसी तरह से तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ साथ हमारे तीसरे चुनाव भी आ जायेंगे । अब हमें देखना यह है, इसका लाभ किनको मिला है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसका लाभ आपने भी लिया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो महरबानी है । अब देखा यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उससे हमें कितना लाभ मिलने वाला है । पहली योजना से और दूसरी योजना से कितना कितना लाभ हमें मिला, इसकी हमें तुलना करनी है....

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष जी, औरतों की गेलेरी में कोई पुरुष बेठे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर से कहिये । क्या कहा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमें यह देखना है कि फायदा किस प्रकार से हुआ ! मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं वे सेन्टर से चलती हैं, वहीं से योजनायें तैयार होती हैं, उसके बाद पहले वहां बंटवारा होता है, उसके बाद में बंटवारा होता है । जिनका ज्यादा जोर होता है उनके पास ज्यादा धन-राशि चली जाती है । इसके बाद में जो नीचे नम्बर होता है उनमें बंटवारा होता है, आखिर कुछ न कुछ तो मिलता ही है । अब हमें देखना यह है कि उसको कार्यान्वित किस तरह से किया जाता है । पहली पंचवर्षीय योजना निकल गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी खत्म होने वाली है और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूं, आज के युग में भी वहां पर रेलवे नहीं है यह आप भी रिअलाइज़ करेंगे, ऐसा हिस्सा भी राजस्थान का है वहां पर रेल्वे तक नहीं है । आप यह समझिये, वहां से तीस तीस और पच्चीस पच्चीस मील के फासले पर रेल्वे स्टेशन्स हैं । टौंक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ सुधार हुआ हो, यह दिखाई नहीं देता । आज लोग इसी चीज़ को ज्यादातर देखते हैं कि उनके यहां रेलवे है या नहीं । हमें ये साधन मिलने चाहिये, इसके लिये धन-राशि होनी चाहिये । मेरा डिस्ट्रिक्ट टौंक जैसा कि सन् ४७ में था वही का वही आज भी है । उस समय जो शासक थे अगर वहां पर जो फ्रेज़र ब्रिज़ है वह नहीं बना देते तो टौंक डिस्ट्रिक्ट से आवागमन होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है । आज दो योजनायें पूरी हो रही हैं और हम तीसरी योजना बना रहे हैं और डिवीज़न वाइज़ पैसा अलॉट कर रहे हैं, लेकिन हमारा टौंक डिस्ट्रिक्ट काफी पीछे रहा है । वहां सड़कें होनी चाहियें, रेलवे

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

स्टेशन होने चाहिये; इसके लिये मैं निवेदन करूं कि आज इस युग में भी जो लोग यह आशा करते थे कि हमें स्वतन्त्रता मिलने के बाद ये साधन भी मिल जायेंगे, वे आज निराश हो रहे हैं। जितनी भी योजनायें बनती हैं उनमें कम से कम यह तो ध्यान में रखा जाय कि पिछड़े हुए जो इलाके हैं, जहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और देना अनिवार्य है।

दूसरी बात यह है कि बिजली के जो साधन हैं उनके लिये भी सभी लोग यह चाहते हैं कि हमें बिजली मिले, आज सब नये दिमाग के लोग हो गये बिना बिजली काम नहीं चल सकता। आज पढ़ने वाला किसान का लड़का भी है तो वह भी बिजली की रोशनी चाहेगा; गडरिये का लड़का है, मैट्रिक हो जाता है तो वह भी बाबू बनने की इच्छा रखता है। इसलिये बिजली का साधन तो सभी जगह होना चाहिये। मैं अपने उनियारा का जिक्र करूं, जहां पांच–छः हजार की आबादी है; चंबल से बिजली आती है, उसका खंभा खड़ा हुआ है आठ मील की दूरी पर, उसके बाद टौंक की तरफ चला जाता है। इस युग के अन्दर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी बिजली नहीं देते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसके अलावा एक प्रत्यक्ष बात है कि हमारे देवली के अन्दर इतना बड़ा पॉवर हाउस लगा हुआ है कि वह तीस मील की दूरी तक लाइट दे सकता है। लेकिन आज वह बन्द पड़ा हुआ है इसके मुतल्लिक कई दफा मैंने हाउस में भी निवेदन किया लेकिन कहा यह जाता है कि हम भारत सरकार से इस बारे में लिखा–पढ़ी कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि सन् ४७ से आज ६० तक अभी तक क्या लिखा–पढ़ी ही पूरी नहीं हुई। इतना करोड़ों रुपया हम पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका जो फल है वह लोगों को बराबर नहीं मिल रहा है। सड़कों का भी यही हाल है। जिनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिये उनको न देकर हम नई नई सड़कों को ले रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि देवली तक हाइडल पॉवर जाने वाली है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो जब आयगी तब आयगी, लेकिन जोइ न्जिन पड़ा हुआ है उसी इन्जिन से आप बिजली क्यों नहीं दे देते ? तो इसलिये मैं कहता हूं आपसे कि....

श्री हरिश्चन्द्र : वह एन्जिन चालू होने लायक ही नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो चालू होने लायक है।

श्री हरिश्चन्द्र : बहुत समय का हो गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोई उसका निरीक्षण करे। तो यह बिजली का हाल है।

रोड का यह हाल है, टौंक टू जयपुर तक जो रामपुरा से देवली होकर आता है ६० मील का चक्कर पड़ता है। टौंक वाया

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

उनियारा रामपुरा रोड का दूसरी योजना में नम्बर भी आया, रुपया भी अलॉट हुआ, पर वह रुपया दूसरी जगह लगा दिया गया। तो जहां पर आवश्यकता है वहां नहीं लगाया जाता। जिसके लिये जो स्वीकृत हो गया तो पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिये।

इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि एजूकेशन का भी यही हाल है। इसके बारे में अधिक तो नहीं कहना चाहता। पर जो सरकार कहती है कि आप इतने कमरे पहले बना लो, इतना काम पहले कर दो तो बाद में बाकी सरकार कर सकती है, पर यह भी सरकार पार नहीं डालती। जनता कमरे बना देती है। हाई स्कूल मेरे यहां चल रही थी। उसके लिये कहा कि नहीं, दूसरी जगह तुम बाहर बनाओ, बाहर चार कमरे तैयार कर दिये। पर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। बच्चे तकलीफ पा रहे है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनिट। मैं यह निवेदन करूं कि चम्बल नहर का, बनास की नहर का यह हाल है, मेरा इलाका है राजोवा खेरवाड़ा। यह जहाजपुर से मिला हुआ है। यहां न बनास नहर जावेगी, न चम्बल। वहां के लिये कई बार अर्ज कर चुका हूं कि वहां मीणों की आबादी है, वहां पर अच्छी खेती वे कर सकते हैं क्यों कि जमीन काफी अच्छी है, पानी का इन्तजाम अवश्य आप करिये और इसके लिये वहां पर बन्ध बांधना चाहिये। पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अगर टोंक की उन्नति करनी है तो रेल की व्यवस्था जरुर करिये और बिजली भी जो है उसका क्राइटेरिया आप निश्चित कर दीजिये कि पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे। आप जिला हैड क्वार्टर को और इम्पोर्टेन्ट टाउन्स को अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो इनको अभी तक क्यों नहीं दिया। अगर आपके पास और साधन नहीं तो डीज़ल से बिजली देते। पर सब को कम से कम आप यह तो बताते कि प्लान से सबको फायदा होगा। योजना में अनेक जिलों में काफी काम किया गया पर कहने के लिये भी इधर कुछ नहीं किया गया। आप थोड़ा करिये। हाइड्रोइलेक्ट्रिक नहीं आवे तो एन्जिन के जरिये ही बिजली देने का प्रयत्न करिये। तो मेरा निवेतन यह है कि आप चाहे जैसी योजना बनावें पर सबसे पहले इसको क्रियान्वित करने के लिये पिछड़े गांवों की ओर जहां पर साधन नहीं है किसी किस्म की उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, इससे पूर्व कि मैं राजस्थान की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं अखिल भारतीय योजना और उसके उद्देश्यों पर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, उपभोग, उत्पादन विनियोग और व्यापार का आपसी समन्वय जो है उसी का नाम योजना है। हमारे पिछड़े देश की योजनाओं और इन्डस्ट्रियली और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हाइली एडवान्स्ड देशों की योजनाओं में अन्तर है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने, आबादी की अधिकता, इन सब चीजों को देखते हुए हमें अपनी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को प्रगतिशील और दृढ़ अर्थ-व्यवस्था में बदलने के लिये, और तरह की योजनाओं की आवश्यकता थी और इसके लिये हमने पहले दो योजनाएं जारी कीं। पहली योजना में हमारी ज्यादातर जो आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी पार्टीशन की वजह से उसको सुस्थिर करने और उसका पुनर्स्थापन करने का लक्ष्य था। इसमें हमें सफलता मिली और दूसरी योजना आई तब हम और आगे बढ़े और हमारी आर्थिक व्यवस्था स्थिर होकर प्रगतिमान बनी। इसको भी सफलता मिली और इससे हमें उत्साह मिला। हम पहली योजना से भी अधिक उत्साह के साथ इस योजना पर चले। समय कम है इसलिये मैं दूसरी योजना के उद्देश्य और इसकी सफलताओं के अन्दर नहीं जाऊंगा पर इतना अवश्य कहूंगा कि दूसरी योजना का उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना और कम से कम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और अन-एम्प्लॉयमेन्ट में कमी करना। अब इसमें हमने सफलता प्राप्त की है, यह देखना है।

आकड़ों से स्पष्ट है कि दूसरी योजना मे २० प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई; औद्योगिक क्षेत्र में ५० प्रतिशत और बिजली और परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हमने की।

आज हम तीसरी योजना के प्रारूप पर विचार करने जा रहे हैं। इसमें हमें दूसरी योजना के अन्त तक ७० लाख बेकारों का बैकलाग मिलेगा, पर फिर भी दूसरी योजना में हमने ६५ लाख लोगों को अधिक रोजगार दिया है। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि दूसरी योजना में हमें सफलता मिली और सफलताओं से जो प्रश्न हमारे सामने आये उनको देखते हुए प्लानिंग कमीशन ने जो उद्देश्य इस तीसरी योजना के हमारे सामने रखे हैं, वे स्पष्ट हैं। वे हैं पांच प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता, इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट, बेसिक इन्डस्ट्रीज़ का विकास, सेन्ट्रल फ्यूल और पॉवर का विकास, मानव-साधनों का उपयोग, बेकारी को मिटाना और असमानताओं को समाप्त करना और आर्थिक असमानता का विकेन्द्रीकरण।

इन लक्ष्यों को देखते हुए हमारी देश की तीसरी योजना १०,२०० करोड़ की बनने की सम्भावना है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : नई बातें बतावें हमें तो ?

श्री उपाध्यक्ष : I don't treat it as repetition.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साइज़ के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह साइज़ बहुत बड़ा है और यह बहुत महत्वाकांक्षी है, दूसरे देशों ने भी कुछ इसी तरह से कहा है। पर हमारे इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी को देखते हुए और जो प्रगति हमने अब तक की है उसको देखते हुए और विकास का जो टेम्पो हमने क्रिएट किया है और जनता में आगे बढ़ने की जो तैयारी देखने में आ रही है,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

इनको देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बेक लोग के रहते हुए भी मैं नहीं मानता कि यह कोई बहुत एम्बीशियस प्लान है, बल्कि मोडरेट प्लान है, फिट प्लान है और हमारे देश के बिल्कुल उपयुक्त प्लान है।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए राजस्थान की हमारी जो तीसरी योजना का प्रारूप हमारे सामने रखा गया है और जिस पर सुनने के लिये सारा सदन ज्यादा उत्सुक है और जिस पर उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त की है, उसके बारे में मैं भी अब अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसके पहले कि तीसरी योजना का क्या प्रारूप हो, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी दूसरी योजना में हमने कहां तक सफलता प्राप्त की है। इसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगा किन्तु सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बात मुख्यतया देखने की है कि इस दूसरी योजना से लोगों में उत्साह काफी देखने में आ रहा है और योजना को पूर्ण करने की तैयारी उनकी अपूर्व है। पहली योजना जो कुछ हैप–हैज़ार्ड वे में बनी, लोगों में उत्साह नहीं था; पर इन गये पांच वर्षों में योजना के मूल को जनता ने समझा है और लोगों में महान् उत्साह और योजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रबल भावना, कुछ करने की भावना, श्रमदान करके या अर्थदान करके कुछ करने की भावना घर घर में देखने को मिलती है, यह स्पष्ट नजर आ रही है। एक बात और है हमारी आर्थिक स्थिति की। यह सबको मालूम है कि पहली योजना में हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, पर इन गये पांच वर्षों में उसने अपने साधनों का काफी निर्माण किया और अपनी फाइनेन्शियल पोज़ीशन काफी ठीक की। तीसरी बात जो डेमोक्रैटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का महान् प्रयास हमने किया है, वह जनता की सुख–सुविधा की बड़ी योजना का एक अंग थी, इसने लोगों में योजना के विकास में सहयोग देने की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया है, तो यह भी प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है।

योजना में प्रायोरिटी और रिसोर्सेज़ की दृष्टि से इस योजना का निर्माण किया जा रहा है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे सदन के नेता ने भी कहा कि हमारी जो पर कैपिटा इन्कम है वह कम है। इस दृष्टिकोण से जब तीसरी योजना में पांच पर्सेन्ट की वृद्धि करनी है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा प्रेशर ऑफ डेवलपमैन्ट, हमारी प्रगति और विकास का रास्ता ऐसा होना चाहिये कि देश के दूसरे राज्यों के माफिक हम आगे बढ़ सकें। हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा।

दूसरी बात जो इसके बारे में होगी वह होगी इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की। जैसे कइयों ने कहा कि ठीक है, हमारा जो पहली योजना का बायस था वह कृषि की तरफ था। दूसरी योजना का बायस भी यही कृषि रहा और अगर इसका प्रारूप भी देखें तो इसका बायस भी एग्रीकल्चर है। ठीक है। यह होगा ही क्योंकि हमारी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था में हमने प्रयत्न भी किया कि इससे निकल कर इन्डस्ट्री पर जावें, पर नहीं जा सके, सभी में हमारा बायस एग्रीकल्चर ही रहा। और तीसरी में पूरा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले का इन्डस्ट्रियलाइजेशन हम नहीं कर सकेंगे जैसा दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। तीसरी मुख्य बात जिसकी हमारे

(श्री सोहनलाल भटनागर)

यहां प्रायोरिटी होनी चाहिए वह एम्प्लॉयमेंट की होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान के अन्दर एजूकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की उतनी समस्या नहीं हैं जितनी कि देश के दूसरे प्रदेशों में है। लेकिन गांवों के अन्दर जिनको कि हम अण्डर-एम्प्लॉयड कहते हैं उनकी संख्या लाखों की है और उनके जो पुराने धंधे थे खत्म हो गये हैं, उनके पास भूमि भी नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोल्व करना पड़ेगा।

चौथा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि जो एमिनीटीज़ गांव के लोगों को मिली हुई हैं उनमें वृद्धि हो। हमारे देश की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके प्रारूप को देखें और हमारे प्रधानमन्त्री के भाषणों को यदि हम देखें तो मालूम होगा कि इन दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर भी हमारी करोड़ों ग्रामीण जनता को, जो कि गांवों में रहती है. जो मूलभूत सुविधायें उनको होनी चाहिए थीं, वे हम नहीं दे पाये हैं और वे मूलभूत सुविधायें ३ हैं। पहली तो पाठशालाओं की, दूसरी वहां के पीने के लिए पानी और तीसरी सड़क या रेल से उसका एप्रोच रोड होना चाहिए, जो कि १॥ या २ मील से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन एमीनिटीज़ की दृष्टि से भी हमको इस योजना में प्रायोरिटी देनी होगी।

इसके बाद अगर हम रिसोर्सेज़ को लें तो देखेंगे कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने रिसोर्सेज़ प्राप्त किये हैं मैं उन बातों के विस्तार में नहीं आता। हमने इस योजना में जो १० करोड़ रुपये के बजाय १३ करोड़ के टैक्सेज़ लगाये और जो भी रिसोर्सेज़ हमारे सामने रखे हैं उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २० करोड़ के एडीशनल टैक्सेज़ इसमें रखे गये हैं और इसके बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने भी अपने भाव व्यक्त किये कि यह जो २० करोड़ रुपये के एडीशनल टैक्सेज़ कलेक्ट करने के टार्गेट्स रखे हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया कि हमारी जो सारी इकोनोमी है और हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें हैं वे सारी की सारी एग्रीकल्चर के ऊपर आश्रित हैं। इस दृष्टिकोण से जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा रहा है, यह सोचा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसका जो सरप्लस है वह एग्रीकल्चर सेक्टर का सरप्लस है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा स्टेट के लिए लेना पड़ेगा वरना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उस दृष्टिकोण से जो टार्गेट टैक्सेशन का रखा है वह बहुत ज्यादा नहीं आता। मेरा ऐसा विचार है कि उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। टैक्सों के बारे में जितने भी डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं उनके लिए सोचा जा रहा है कि इन्फ्लेशन न हो और प्राइसेज़ में वृद्धि भी न हो।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेविंग्स और लोन के लिए इसमें प्रोवीज़न रखा है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए मुझे जरूर शंका है। २० करोड़ का जो लोन प्राप्त करने के लिए लिखा है वह हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह १० करोड़ की व्यवस्था सेविंग्स के लिए

(श्री सोहनलाल भटनागर)

रखी है वह भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज़ जो स्टेट सेक्टर में अण्डरटेकिंग से होनी चाहिए मेरे ख्याल से इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में भी हम ऐसे स्टेट अण्डरटेकिंग्स नहीं ले सके हैं। राजस्थान के अन्दर जिसकी वजह से उसका लाभ सरकार को मिल सके। हमारे जो स्टेट के साधन हैं वे या तो इर्रिगेशन है या स्टेट ट्रेडिंग है या फिर नेशनलाइजेशन है। लेकिन इन चारों सेक्टर्स में देखें तो हम माइनस में चलते हैं। तो दूसरे जितने भी प्रदेश हैं और भारत को देखते हैं तो स्टेट अण्डरटेकिंग्स में रेलवेज़ ने या कॉर्पोरेशन ने काफी योगदान साधनों में दिया है, उसकी हम अपने यहां कमी देखते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इन साधनों में यद्यपि ८१ करोड़ रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी कठिनाई अवश्य होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में जो सेक्टर रखा है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर के बारे में जो कहा गया कि १० करोड़ की रकम रखी है, वह बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया हमारी सारी नीति एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर के अन्दर जो कुछ हमने किया है और किस तरह से हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट है कि बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि एग्रीकल्चर के अन्दर हमें साइन्स और टैक्नोलोजी को ले जाना है। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो समस्याएं हैं उनको हमें लेबोरेटरी में ले जाना है और उसका जो रिज़ल्ट है वह फील्ड में ले जाना है। इस दिशा में विकसित देशों ने काफी कामयाबी हासिल की है और उसमें हम नाकामयाब रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए जरूर कोशिश करेगा। दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेद की बात है कि हमने जो टार्गेट्स एचीव किये हैं वे काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल शंकित हूं कि गांव के अन्दर रहने वाली जनता में ५० से ४० प्रतिशत की वृद्धि करना एकदम सम्भव हो सकेगा क्योंकि जिस तरह की शिक्षा है और जिस तरह से गांव में रहने वाले बच्चों को कृषि के लिए समय नहीं मिलता व जिस तरह की शिक्षा प्रणाली है उसकी वजह से हम अपने टार्गेट्स को एचीव नहीं कर सकेंगे।

मैं एक बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा और वह है सिंचाई के बारे में। अगर हम दूसरे सेक्टरों को देखें तो हम उनमें वृद्धि देखते हैं लेकिन सिंचाई के अन्दर हमें वृद्धि नजर नहीं आती क्योंकि सिंचाई के अन्दर पहले ३५०० लाख रुपया था वहां अब २४०० लाख परुया रखा है तो इसमें कमी जरूर की है और इस साल जो कार्य पहले रखे थे वही कार्य रखे हैं, केवल १६ अन्य काम नये हैं। इसके अलावा जो लघु सिंचाई की योजनायें हैं उनके लिए जो रकम रखी है वह बहुत कम है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आज सदन के माननीय सदस्यों को पूरी तरह से विदित है कि लघु सिंचाई से हमें राजस्थान में कृषि की वृद्धि करने में काफी योगदान मिला है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पष्ट है कि १ लाख ४०

Page No.73

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हजार एकड़ भूमि लघु सिंचाई योजना से सींची गई है। इसलिए जो २ करोड़ की व्यवस्था लघु सिंचाई के लिए की है, १ करोड़ तो पुराने कामों के अन्दर खर्च होगा और १ करोड़ नये कामों के लिए खर्च होगा; मेरे ख्याल से तो यह रकम बहुत कम है, इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद मैं पॉवर के बारे में कुछ कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो श्री हरिप्रसाद जी ने बहुत कुछ कह दिया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आखिर में एक बात मैं, जो पॉवर के आंकड़े माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखे, उनके बारे में कुछ कहूँगा। एक बात विद्युत मंत्री ने कही और अभी कई माननीय सदस्यों ने भी कही, पर यह सही है कि हम बिजली का काफी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने ६० हजार किलोवाट के उत्पादन का टार्गेट रखा है, वह एक्चुअल नहीं है। हम देखेंगे तो मालूम होगा कि वह २० हजार के करीब ही होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत के लिए जो राशि रखी है वह बिलकुल ठीक है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय स्वयं काफी उत्सुक हैं क्योंकि जो पुराने सबक हैं वे उसको ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि विद्युत जो कि हमारी इन्डस्ट्रीज़ का बेस है उसके टार्गेट्स जल्दी से जल्दी, हम आशा करते हैं कि एचीव करने की कोशिश करेंगे।....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ मिनट और....

श्री उपाध्यक्ष : I regret, I cannot extend the time.

श्री सोहनलाल भटनागर : बैलेन्स रीजनल के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर आज भी वाद-विवाद हो रहा है, उस पर बहुत सी बातों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैं एक बहुत बड़ी समस्या जिसके ऊपर कि बहुत कम माननीय सदस्यों का ध्यान गया है, कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि हमारी जनता को या कार्यकर्ताओं को या जो भी अफसरान हैं या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को या जिस किसी को, क्या यह मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है कि जिसके ऊपर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का आधार खड़ा रह सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इसी पृष्ठभूमि को हमें बढ़ाना है और हमारे देश के लिये हमें कुछ करना है। योजना हमारी है और हमको इसे कार्यान्वित करना है। एक मिशनरी स्पिरिट के हिसाब से, वह मिशनरी स्पिरिट कि जिसके साथ हमको हमारी

(श्री अनूपसिंह)

पंचवर्षीय योजना लागू करनी चाहिए थी, वह लागू नहीं हुई। हमको यह देखना है कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना सामने आने वाली है और अब तक हमारी जनता में और हमारे कार्यकर्त्ताओं में वह जोश नहीं है, वह मिशनरी स्पिरिट नहीं है जो शायद इसके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है है कि हम बहुत पैसा खर्च कर दें, यह भी हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपये अमेरिका से प्राप्त कर लें, लेकिन उसको ठीक तरह से यूज़ करने का यदि हममें मनोवैज्ञानिक एटीट्यूड नहीं है तो मैं समझता हूं कि हमारी योजना किसी भी तरह आगे नहीं चल सकती। योजना की सफलता के लिए हम में यह भावना पैदा हो कि मैं प्रगति करना चाहता हूं और प्रगति हमारा अधिकार है। अगर इस मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रख कर काम किया जाता है तो कुछ प्रगति हो सकती है। आगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि इसी चक्कर में हमारी सर्विसेज भी हैं, हमारे कार्यकर्त्ता भी हैं, हमारे प्रधान भी हैं, हमारे पंच और सरपंच भी हैं, सब कोई इस चक्कर में हैं, सब में यह भावना है कि हमें अपने एरिया के लिए कुछ करना है, अपने सीमित वर्ग के लिए कुछ करना है। हम यह नहीं सोचते कि हमारे एरिया पर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पर डिविज़न है, डिविजन के बाद स्टेट लेवल भी है। उन सब तक वह बात नहीं पहुँचती है और इसीलिए हम जिन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे और शायद उन उद्देश्यों को तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद भी शायद हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हममें यह भावना होनी चाहिए कि हमारा अपना एरिया ही नहीं है, सारे राज्य और देश की प्रगति हमें करनी है। हमको चेष्टा करके, आमोद-प्रमोद और आलस्य छोड़कर आगे बढ़ना है; तो इस प्रकार की मिशनरी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद जनता के आर्थिक जीवन में कुछ सुधार कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि हम में सबसे बड़ी कमी इस बात की रही है और हम अब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं लेकिन जो प्रायोरिटी है वह किस तरह से फिक्स होनी चाहिए, नम्बर १ कहां हो, २ कहां हो ३ कहां हो, इस तरह की लिस्ट, एक क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वह अब तक शायद नहीं कर पाये हैं और हम यह सोचते रहते हैं कि हमारी योजना लागू नहीं हो रही है, जो हम एस्टीमेट्स करते हैं, अन्दाज करते हैं, जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, जो टार्गेट पूरा करना चाहते हैं वे पूरा क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए मैं तो यह समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमी यही है कि अभी तक हम प्रायोरिटीज़ ठीक तरह से फिक्स अप नहीं कर पाये हैं। यह प्रायोरिटी तभी फिक्स हो सकती है जब कि हम असली जरूरत को पहले सामने रखें, उससे कम को उसके पीछे रखें और उससे कम को उससे भी पीछे रखें। यह देखें कि सबसे बड़ी जरूरत किसकी है, आर्थिक दृष्टि से और आर्थिक जीवन से कनेक्ट करने वाली। यह जब तक नहीं होगा हम अपने लक्ष्य के नजदीक नहीं पहुंच सकते। जैसे सबसे बड़ी आवश्यकता है खेती की, हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के जरिए यह प्रूव करने की कोशिश

(श्री अनूपसिंह)

की गई है कि खेती का जो हमारा लक्ष्य था, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसको हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करने में बिल्कुल एतराज नहीं है कि हम जो कुछ भी तखमीने बनाते हैं वे एक प्रकार से इस तरह से होते हैं कि हम फलां खाद काम में लेते हैं इसलिए इतना प्रोडक्शन तो होगा ही, या हम इतने औजार काम में लेते हैं तो इतना प्रोडक्शन तो होना ही है, हम केवल पोटेंशियलिटी की ओर देखते हैं, असली फिगर्स, एक्चुअल रिटर्न्स क्या हैं, एक्चुअल फर्क क्या पड़ा, यह मालूम नहीं है क्योंकि आज दिन तक हमें यही मालूम नहीं है कि किस जमीन पर किस फर्टीलाइज़र को कितना काम में लिया। हमने कभी जमीनों का एनेलिसिस नहीं किया है, हमें यह मालूम नहीं है कि सैकड़ों तरह की जमीनें होती हैं जिनके लिए अलग अलग तरह के खाद की जरूरत होती है। कोई एसिडिक जमीन है, कोई पथरीली है व कोई मिट्टिली है। किसी पर्टिक्यूलर एरिया में किस तरह की जमीन है, एक तहसील में पांच-दस तरह की जमीनें होती हैं, क्या आज दिन तक किसी तरह भी हमने विश्लेषण किया है कि कहां पर कौन सा फर्टीलाइज़र काम देगा। जो फर्टीलाइज़र्स को लेकर हम बहुत सी बातें करते हैं, जिस पर बहुत बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं वह पर्टिक्यूलर फर्टीलाइज़र कई जगह तो बिल्कुल काम भी नहीं आया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमने यह फर्टीलाइज़र काम में ले लिया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ ही गया, ऐसा मान कर चलना मैं समझता हूं कि समस्या का सही निदान नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, मैं सिर्फ जनरल पोलिसी के लिहाज़ से अर्ज कर रहा हूं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको चलाने वाले बी. डी. ओ., वेटरनरी ऑफिसर्स, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, ए. इ. ओज़ होते हैं। हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारे ए. इ. ओज़ और इ. ओज़ को यह मालूम नहीं है कि कहां पर कौन सी खाद काम में ली जाय। इसमें उनकी भी गल्ती नहीं है क्योंकि एक अलवर का रहने वाला है और उसको बाड़मेर भेज दिया जाता है, एक भरतपुर का है उसे बाड़मेर या बाड़मेर वाले को भरतपुर भेज दिया जाता है; उनको यह पता नहीं होता कि यहां किस प्रकार की जमीन है। जैसी उन्होंने ट्रेनिंग पाई है और जो वे प्रेक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो उनको बहुत बड़ा डिफरेंस मालूम होता है। जो लोकल प्रेक्टिसेज़ हैं और जो आज के नये तरीके हैं, जो आधुनिक तरीकें हैं उनको किस तरह से को-ऑर्डिनेट करें, यह उनको अभी तक पता नहीं है। आप तो केवल यह समझ लेते हैं कि हमने इतना खाद काम में लिया, इतने औजार काम में लिए और हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, जो हमारा टार्गेट था वह एचिव हो चुका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि जो हमारे खेती के महकमे ने फिगर्स दिए हैं; जैसे गेहूं के लिए यह माना जाता है कि क्षेत्रफल है, ३० लाख एकड़ होगा और औसत उपज ८०० पौंड होगी उसी तरह से १९६५-६६ में यह मानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल ५० लाख एकड़ हो जायेगा और औसतन ९२० पौंड होगी और

(श्री अनूपसिंह)

उत्पादन २०. ७४ हो जायेगा । अब आप यह देखिए कि फिगर्स तो वही के वही रहे । जो जमीन आज है उससे ड्योढ़ी जमीन आपने ६५-६६ में अन्डर कल्टीवेशन लाने का विचार किया है और प्रोडक्शन बढ़ गया पूरा सवाया । यह एक आंकड़ों का जाल है । जब इतनी जमीन बढ़ गई तो इतना प्रोडक्शन भी बढ़ ही जायेगा, ऐसा हमारा अनुमान है लेकिन वास्तव में प्रोडक्शन होगा या नहीं । पहले औसत उपज आठ सौ पौंड थी और ६५-६६ में वह ६२० हो जायेगी यानी १२० पांच वर्ष में फर्क पड़ेगा, जो जमीन बढ़ेगी तो उससे नेचुअरली प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन वास्तव में बढ़ेगा या नहीं, यह हमें नहीं मालूम । इसी तरह से आगे जो के बारे में है । हमने माना है १५ हजार औसत क्षेत्रफल है और ६. ७० उत्पादन । आगे यह देखिए १५ की जगह २० हो गया, क्षेत्रफल सवाया हो गया और ६. ११ पर्सेन्ट की अनुमानित उपज जो है वह भी सवायी हो गई । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा जमीन काश्त में आयेगी, अन्डर प्लो ली जायेगी उसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि क्योंकि हमने इतना फर्टीलाइजर काम में लिया, या इतना फर्टीलाइजर काम में लेंगे तो उससे इतना प्रोडक्शन बढ़ जायेगा, या इम्प्रूव्ड सीड की वजह से या इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स की वजह से या सुधरे हुए तरीकों को काम में लाने की वजह से ही प्रोडक्शन बढ़ जायेगा तो यह हमारा अनुमान सही नहीं होता है । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि वह जील, वह रिसर्च करके कि जिससे हम वास्तविक स्थिति तक पहुंच सकें, जिससे हमारा प्रोडक्शन वास्तव में बढ़ सके वह चीज दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ।

अब मैं अर्ज करूंगा कि जैसे बीज के लिए कहा जाता है हमने चार ब्लॉक्स के बीच में एक बीज का फार्म बनाने की योजना की है, सीड प्रोड्यूसिंग फार्म । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्वयं के देखने में भी यह आया होगा कि हमारे गवर्नमेंट के फार्म किस तरह से चलते हैं और फिर गवर्नमेंट या समितियों के फार्म हैं उनसे हमारे एरिया में चार ब्लॉक्स के बीच में एक फार्म बीज सप्लाई करने के लिए रखा जा रहा है यह एक बड़ा फार फेचेड आइडिया है । एक फार्मर अपने फार्म पर कितनी मेहनत करता है, हर मुमकिन कोशिश करके अपने फार्म की प्रोड्यूस बढ़ाने की कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करके अपना खर्चा घटाने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक वह ऐसा नहीं कर पाया है । ऐसे फार्म आज तक सैल्फ सफिशियेंट या बेनिफिट में नहीं रहे हैं । आप उनकी बैलेंस शीट उठा कर देखिए, करीब २ सभी घाटे में चल रहे हैं, बहुतों का लोन लिया हुआ है। अब इतना सब कुछ होते हुए भी एक फार्मर अपनी चीज़ को देखते हुए प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है तो पंचायत समिति के अन्डर में जो फार्म रहेंगे, यह मान लें कि वह ४ ब्लॉक्स के अन्दर जो बीज की सप्लाई का एस्टीमेट है उसको पूरा कर सकेंगे, यह एक बिल्कुल मानने की बात नहीं है । एक पंचायत समिति से चलाया हुआ फार्म ४ ब्लॉक्स के लिए बीज की सप्लाई को कैसे कर सकेगा जबकि एक किसान अपनी खेती को करते हुए नहीं कर सकता है ! वहां पर

(श्री अनूपसिंह)

किसका काम बिगड़ता है, बी. डी. ओ. अपना करता है और पंचायत समिति अपना करती है। किसको गरज पड़ी कि ठीक करके बतावे। बीज खत्म हो जायगा तो भूखों मरना पड़ेगा। इतनी जील होते हुए भी किसान नहीं कर सकता है तो पंचायत समिति का फार्म किस तरह से चलेगा ? हम फिर भी बैठे रहें और वह बीज दे देंगे, यह बिल्कुल नामुमकिन बात है। इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्दर जो कोई भी सोच सकने वाले हैं वे सोच कर देखें तो मालूम पड़ेगा कि आज दिन तक कोई ऐसा फार्म नहीं है जो ठीक चल रहा हो और वाकई बीज देने के लायक बना हो।

आगे सबसे बड़ी बात आज हमारे इस आधुनिक समय में आ रही है, वह है बिजली की। इसमें जब तक यह हमारी क्षमता न हो जाय कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करें तब तक हम किसानों की हालत सुधारने के लायक नहीं हो सकते हैं। यह एक मानी हुई चीज़ है कि जब तक किसान अपने पास से खर्चा करता जायगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा इसलिए जरूरी यह होगा कि उसके खर्चे को मिनिमाइज़ करके उसके मार्जिनल प्रोफिट को बढ़ायें। उसका कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके और जो कुछ भी प्रोफिट बढ़ता है उस मार्जिन को बढ़ावें। यह हो सकता है कि बिजली से अन्यथा किसी तरह से नहीं हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, यह मानी हुई चीज़ है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह नहर पहुंच जाय, मगर प्रकृति ने ऐसा खाका राजस्थान का बनाया है कि हर जगह नहर नहीं पहुंच सकती है। यह मुमकिन नहीं है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसानों को अब बिजली ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुहैया करायें। यह नहीं हो कि छोटे-मोटे वर्कशाप लगे हुए हैं, छोटी-मोटी बिजली खर्च करने वालों ने पर्मिट ले ली हो, उसके अन्दर सारी बिजली की पॉवर खर्च हो जाय और किसान के लिए दिक्कत हो जाय मुहैय्या होना जिससे कि वह अपने फार्म्स के अन्दर मोटर लगा कर इर्रिगेशन सिस्टम को बदलेगा, लिफ्ट इर्रिगेशन को खत्म वह किस वजह से करेगा और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ायेगा। हो सकता है कि शहरों में वर्क आगे बढ़ जाय और रूरल एरिया है वह पिछड़ा का पिछड़ा रह जायगा, क्योंकि रूरल एरिया की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यह होता है कि शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति या जो कारोबार करने वाले हैं उनके पास में बिजली मुहैया हो जायगी और किसान, मैं समझता हूं, उससे वंचित रह जायगा। यह मैं आज चेतावनी के तौर पर अर्ज करूंगा कि आगे क्या होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं इस बात पर जरूर अर्ज करूंगा कि जहां पर खेती हो सकती है वहां पर खेती हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा एरिया मानसून एरिया है। हमको आकाश

(श्री अनूपसिंह)

की तरफ देखना पड़ता है। यह देखना पड़ता है कि बरसात होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो दूसरे रास्ते अख्त्यार करने पड़ते हैं जैसा कि इसी साल हो रहा है कि अकाल पड़ गया है तो लोगों को यह सोच पड़ रहा है कि यह साल कैसे निकाला जाय। माननीय उपाध्यक्ष, उस हालत में क्या होता है कि राजस्थान का काश्तकार खेती पर नहीं रह कर सेकन्डरी प्रोफेशन पर पड़ता है। वह सेकन्डरी प्रोफेशन उसका वेटरनरी और एनीमल हस्बेन्ड्री का है। कई जगह ऐसा है कि वह न सेकन्डरी प्रोफेशन है बल्कि प्राइमरी प्रोफेशन है। मैं यह अर्ज करूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ इलाका, जालोर का कुछ इलाका ऐसा है जिनमें यह जरूरी हो गया है कि उनके यहां बरसात फैल हो जाती है तो परवश होकर उन्हें इसी धन्धे को लेना पड़ता है। अब मैं यह अर्ज करूंगा और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने आज दिन तक इस धन्धे के लिए क्या किया है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के तहत, अपनी योजना के तहत उनको लेकर आपने क्या क्या चीजें उनको मुहैया की हैं। आप यह कहते हैं कि सांड देंगे, सांड भेजेंगे, अच्छे सांड देंगे, गायों के लिए तकावी देंगे। वह आप कब देंगे ? तब देंगे जब कि वे जानवर कहीं नहीं होंगे। वे सांड लायेंगे कहां से ? बुल हैं कहां ? मैं यह मानता हूं कि जो बुल्स पैदा करते हैं, जो बुल्स रखते हैं, उन ब्रीडर्स को आपने आज दिन तक किस तरह की मदद दी ? जोधपुर एरिया में एक ब्रीडिंग फार्म है जहां कि ७००-८०० गायें हैं, आज दिन तक उसको आपने क्या मदद दी। उन ७००-८०० गायों को एक अकेला आदमी अपने बूते पर चला रहा है। सारा घर और पूंजी बरबाद कर रहा है और जो कुछ पैदा होता है वह उस फार्म में होता है, जहां से बुल्स लेकर आप कहते हैं, आप बड़ा फर्क करते हैं। वह ब्रीडिंग का फार्म राजस्थान में सबसे बड़ा सिंदड़ी का फार्म है। उससे आप बुल्स लेते हैं, लेकिन उसके लिए आज दिन तक आपने क्या किया है ? इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि आज दिन तक लोगों पर बैठ कर, लोग पैदा करें और हम नफा लें यही किया है। तो माननीय उपाध्यक्ष, यह भी एक सोचने की बात है कि हमने उसमें क्या किया है। वे आदमी अपने मन से, पीढ़ियों से गायों की नस्ल सुधारने का काम करता आ रहा है और आज उसके पास गायों की प्योर ब्रीड है। उससे हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट बुल्स लेकर कहता है तो यह कहने की बात है कि हम मदद दे रहे हैं, लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि यह समस्या कई जगह है कि लोगों को पशु-पालन करना पड़ेगा, तो आपने यहां किस तरह का प्रावधान है ? पंचवर्षीय योजना में कम से कम मुझे देखने को नहीं मिला है कि हमारे यहां किसानों को फेसिलिटी देने का किस तरह का क्या खाका है ? इन ५ वर्षों के अन्दर कितने एरिया को चराई के अन्दर ले लिया गया है और ५ वर्षों के बाद कितना लेंगे। ५ वर्ष पहले के छोड़ कर घास को पैदा करने के लिए कितना एरिया रखा जायगा और ५ वर्ष में कितना दूसरा एरिया आयेगा। इस तरह से साइन्टिफिक तौर से रेग्युलेराइज्ड वे में चराई के लिए जमीन को छोड़ने का, काश्त नहीं होने का प्रोविज़न कहीं पंचवर्षीय योजना-

(श्री अनूपसिंह)

में नजर नहीं आ रहा है और माननीय उपाध्यक्ष, हमारी आशा शायद निराशा में नहीं बदल कर रह जाय और हमारा पशुधन खत्म हो जाय ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सिर्फ उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा सा टाइम लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Please finish within a minute or two.

श्री अर्जनदास : I think the debate was to be extended, Sir.

श्री अनूपसिंह : इसमें और रखा गया है अश्व प्रजनन के लिए, घोड़ों की ब्रीडिंग को सुधारने के लिए एक केन्द्र होगा । मैं अर्ज करूंगा कि केन्द्र होगा कब ? जबकि घोड़ों की नस्ल ही खत्म हो जायगी तब ऐसा केन्द्र होगा ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक खाका बनाने का विचार है कि एक प्रजनन केन्द्र बनाना है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वे खत्म हो चुके हैं, और खत्म होते जा रहे हैं । आज दिन तक उन ब्रीडर्स को प्रोत्साहन नहीं मिला और अच्छे घोड़ों की नस्ल खत्म हो गई । माननीय उपाध्यक्ष, यह कहने की बात होती है कि यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन हिन्दुस्तान को आजाद हुए १४ वर्ष हो गये हैं, आज दिन तक उनकी नस्ल सुधारने के लिए और कायम रखने के लिए कोई चीज़ नहीं की है । यह मैं मानता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा कि हमारे यहां जो घोड़ों की नस्ल थी वह हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं नहीं थी और वैसे घोड़े आज आपको नहीं मिलेंगे । यह दूरदर्शिता का नाम है कि आज दिन तक कोई उनकी मदद नहीं की । कहते हैं कि सेन्टर से ले रहे हैं तो किस दिन उसका फायदा उठायेंगे, लेकिन किस दिन उसका उनको फायदा पहुंचेगा, यह आगे देखने की चीज़ रहेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष, यही हाल ऊंटों का है । ऊंटों वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हर एक टोले में मैं देखता हूं कि ऊंट होते हैं उनके लिए चरने की कोई जगह नहीं है । कहीं चले जाते हैं तो उनको जूते मारे जाते हैं, जेल में ठूंस देते हैं, इस तरह से हैरास किया जाता है कि कहीं नहीं जा सकते हैं । ग्रेजिंग ग्राउन्ड कोई छोड़ी हुई नहीं है इसलिए लाचार होकर उनको लोगों के खेतों में जाना पड़ता है जबकि फसल नहीं होती है । इसलिए ऊंटों की नस्ल भी खत्म होती जा रही है ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री अनूपसिंह ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (वैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सिर्फ श्री अनूपसिंह को सुन रहा हूं ।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इसी तरह से भेड़ और ऊन के विस्तार की बात की जा रही है । मैं समझता हूं कि भेड़

Page No.80

(श्री अनूपसिंह)

और ऊन एक दिन खत्म होकर रहेगी, चाहे आप इस कान से सुनें या उस कान से सुनें। इसके लिए कोई प्लॉन नहीं है और इस पंचवर्षीय योजना को देखते हुए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसके अन्दर जिसकी बातें इतनी लम्बी-चौड़ी करते हैं कि राजस्थान ४८ प्रतिशत हिन्दुस्तान की ऊन का प्रोडक्शन करता है पर उसके लिए करते क्या हैं राजस्थान में ?

(३ म० प०)

राजस्थान के अन्दर इन रेबारियों को या भेड़ पालकों को मदद क्या दी जाती है, यह किसी ने बताया नहीं। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस खाते में लिखा है ? कहने को कह देते हैं कि लोग करते हैं उससे फायदा उठावें और हम डींग हांकते हैं कि हमने कर दिया। कहने की बात और है और करने की बात और है। यह तो वैसी बात हुई कि "तू कह काजी मैं कहूं हाजी"। जो आपस में बातें करते हैं क्या वे किसी दूसरे पर लागू होती हैं ?...

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude your debate.

श्री अनूपसिंह : Yes, Sir, I am concluding it.

इसके साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि रोड डेवलपमेन्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट चीज है राजस्थान के लिये उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। सब से बड़ा कारण यह है कि वे कह देते हैं कि क्या करें, वहां पानी नहीं मिलता, मुरड नहीं मिलती, फेसिलिटीज़ नहीं, जाने-आने के रास्ते नहीं इसलिये वहां जावें कैसे ? मैं कहता हूं कि अरे साहब, रास्ता नहीं है इसलिये आपको रोड बनाने के लिये कहते हैं, यदि वहां पर पानी हो, मुरड हो, आने-जाने का रास्ता हो तो आपको रोड बनाने के लिये क्यों कहते....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot exceed after three.

श्री अनूपसिंह : हमारे यहां के० पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियरों की लिथॉर्जी है, उनका आलस्य है, उनमें हिम्मत नहीं है कि कन्डीशन को फेस करके काम कर सकें। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और इन्जीनियरों में जो लियार्जी है उसको निकालें और उनमें मिशनरी स्पिरिट डालें जिससे वे अपने देश के लिये हर मौसम में काम कर सकें। रोड बनानी है तो बनेगी; इस तरह की भावना उनमें डालें तो काम हो सकता है, अन्यथा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister for Industries will make a reply now.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर प्रारूप सदन के सामने प्रस्तुत करने के बाद आज तीन रोज से उस पर बहस हो रही है। माननीय सदस्यों ने अलग अलग पहलुओं पर तृतीय पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान के लिये बनाई गई है, उसके बारे में अपने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जहां तक उद्योग का सवाल है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, चन्द बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और वे इस प्रकार से हैं :

"जहां तक राज्य सरकार की उद्योग नीति है वह १९५६ में जो इन्डस्ट्रियल रिज़ोल्युशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का हुआ उससे किसी प्रकार से भी भिन्न नहीं हो सकती। राजस्थान में भी उसी नीति का प्रतिपादन करना है। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल यह बात बताई थी कि जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है उसमें इस बात का यकीन होना चाहिये कि वह जो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा वह सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, सरकार उस पर किसी प्रकार से अन्कुश नहीं रखेगी। मैं इस बारे में स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि जो दो सेक्टर्स बताये हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वे भी इस इन्डस्ट्रियल रिजोल्युशन में साफ हैं। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो निश्चित तौर से पब्लिक सेक्टर में ही होंगे और कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं और मिले-जुले भी हो सकते हैं और तीसरे ऐसे उद्योग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में ही होंगे।"

जहां तक प्राइवेट सेक्टर में पूंजी लगाने का सवाल है, हमारा विधान है और उसी के अनुसार जो कुछ कार्यवाही होती है वह की जाती है। माननीय सदस्य का यह ख्याल था कि क्योंकि अभी हाल में यहां की टैक्सटाइल मिल्स की हालत खराब होने से जो पुराने स्टेट्स के जमाने में बनी थी बहुत अर्से से चल रही थी, उनकी मशीनरी खराब हो गई थी इसलिये उनमें से कुछ बन्द हो गई थीं और कुछ का उत्पादन कम हो गया था, इसलिये आज से साल भर पहले टैक्सटाइल मिल्स की हालत खराब होने से राजस्थान में जो टैक्सटाइल मिल्स थीं उन पर विचार किया गया और मैं आज सदन के सामने इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने साल भर में जिन टैक्सटाइल मिल्स को ठीक करने का कार्य किया उससे आज स्थिति सुदृढ़ हुई है, वे अच्छी तरह से चलने लगी हैं और कुछ नयी टैक्सटाइल मिल्स के लिये लाइसेन्स लेने में कामयाब हुए हैं। मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि जो कदम सरकार ने उठाया वह उठाना चाहिये था। उसका नतीजा सब के सामने आया। हमारे यहां पर तीन मिल्स बिल्कुल स्क्रेप थीं; जैसे किशनगढ़ मिल, विजयनगर मिल और माधोमिल भीलवाड़ा। ये तीनों स्क्रेप की गईं और इनके बजाय तीन नयी मिल्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात-चीत करके उनको स्थापित करने के लिये लाइसेन्स लिया गया; एक किशनगढ़ में, एक भीलवाड़ा में और एक भवानीमंडी में। इसी तरह से उदयपुर टैक्सटाइल मिल की बात भी आई। उसको सरकार ने लोन दिया। इसका काम जारी है। मैं आशा करता हूँ कि मार्च, ६१ तक यह मिल भी मशीनें लगाकर कार्य शुरू कर देगी। इसी तरह से तीन और टैक्सटाइल मिल्स थीं जिनकी हालत ठीक नहीं थी; एडवर्ड मिल मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और कोटा मिल। कोटा मिल के बारे में निश्चय हो चुका है। ४०-५० लाख रुपये लगा कर जनवरी, फरवरी माह तक इसका काम चालू कर दिया जायगा। एडवर्ड मिल और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स को सरकार ने अपने

(श्री रिवत्रचन्द धारीवाल)

नियंत्रण में लिया। जब किसी अन्डरटेकिंग को सरकार अपने नियन्त्रण में लेती है तो उसका कारण होता है। बगैर कारण के किसी प्राइवेट पर्सन की अन्डरटेकिंग को सरकार के नियंत्रण में चलाने की जरूरत नहीं होती। उनका मेनेजमेंट खराब था, मेवाड़ टैक्सटाइल-मिल पर कर्जा था और वह ६-७ महीनों से बंद थी, डेढ़ दो हजार मजदूर थे वे बेकार हो गये थे। एडवर्ड मिल की भी ऐसी ही हालत हो रही थी। वह बहुत पुरानी मिल थी। उसको मोडर्नाइज़ड बनाने पर अच्छी मशीन लगी और अब वह अच्छा काम कर रही है। इस दृष्टि से सरकार ने इनको अपने नियंत्रण में लिया। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दोनों ही मिलें अच्छी तरह से चल रही हैं, मुनाफा भी है, गोकि सरकार ने मुनाफे की नीयत से इसे नहीं लिया क्योंकि मुनाफा सरकार को मिलने वाला नहीं है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट था और लेबर में और भी अनएम्प्लॉयमेंट फैलने वाला था इसलिये उसे खत्म करने के लिये सरकार ने रुपये दिये और चलाने की व्यवस्था की और मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिला। मैं समझता हूं, यह स्वस्थ नीति है। किसी प्राइवेट पर्सन के ऐसे अन्डरटेकिंग को देखते हैं, अव्यवस्था को देखते हैं तो सरकार हस्तक्षेप करती है। इसमें मुनाफा सरकार को नहीं मिलेगा, अन्डरटेकिंग को ही जायगा, लेकिन लोसेज़ होंगे तो सरकार बर्दाश्त करेगी। इस दृष्टि से दोनों मिलों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था। मैं समझता हूं, सदन इसको एप्रिशियेट करेगा कि टैक्सटाइल मिल्स की हालत ठीक की। जो कि बहुत पुरानी थी, जो ठीक प्रकार चलती नहीं थी, उसकी हालत सुधारने में, उसको मॉडर्नाइज करने में, रिहेबिलिटेशन करने में हमने आगे कदम उठाया है। उसको एन० आई० डी० एस० से लोन मिल जायगा। इस तरह मॉडर्नाइज करें, इस तरह से प्रोग्राम दिया है, वह धीरे धीरे करना भी चाहती है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के वक्त हमारे पास कुछ उद्देश्य हों, उन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया जाना चाहिए और बनाया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जहां तक उद्योग का सवाल था, कुछ रुपया हमको मिला और वह करीब ३ करोड़ ६६ लाख, ७० हजार था। पहली पंचवर्षीय योजना तो जो थी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा जोर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में एग्रोकल्चर सेक्टर पर उतना जोर नहीं रहा, जितना प्रथम पंचवर्षीय योजना में रहा, मगर उसमें इन्डस्ट्रीज़ को ज्यादा महत्व दिया गया और उस पर जोर लगा और धीरे धीरे एक टेम्पो बना हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय बनाने के वक्त क्योंकि राजस्थान में जहां कि इन्डस्ट्रियल साइड के अन्दर हम पिछड़े हुए थे, उसको धीरे धीरे, टेम्पो को केच अप करने में समय लगा। वैसे इसमें दो-तीन सालों के अन्दर काफी प्रगति की गई और तीन करोड़ ७० लाख में से ३ करोड़ २१ लाख खर्च कर सके हैं। इस सेक्टर में अलबत्ता जो शोर्ट फाल हुआ है; वह भी सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। हैंड लूम डेवलपमेंट के लिए ५८ लाख ५६ हजार था, वह खर्च कर दिया गया है, इसमें कोई शार्ट फाल नहीं हुआ। वूलं इन्डस्ट्री के लिए ११ लाख ८ जार था,

(श्री सिखबचन्द धारीवाल)

उसमें से ८ लाख ७० हजार खर्च हुआ है, इसमें शोर्ट फाल २ लाख ३६ हजार का हुआ है। खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़, इसमें कोई शोर्ट फाल नहीं है, ड्रग इन्डस्ट्री, जिसमें लोन देते हैं। इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का सवाल है और दूसरी स्कीमें हैं, वे सारी मिला कर दो करोड़ रुपये की थीं, इनमें से १ करोड़ ८७ लाख, ८६ लाख हमने खर्च किया है। इनमें शोर्ट फाल हुआ १४ लाख का। हैंडी क्राफ्ट में ३५ लाख ४८ हजार था, जिसमें से २२ लाख ७१ हजार खर्च किया, इसमें शोर्ट फाल हुआ है १२ लाख ७५ हजार का। इनडस्ट्रियल एस्टेट में ७१ लाख थे, इसमें से ४२ लाख १६ हजार खर्च कर सके और इसमें शोर्ट फाल हुआ है २८ लाख ८१ हजार का। वेट्स एन्ड मेजर्स में कुछ शोर्ट फाल हुआ है, क्योंकि ऐसी स्कीम नहीं थी, वह स्कीम भी नहीं रही है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जहां तक लघु उद्योग का सवाल था, कुछ स्कीम्स इस प्रकार की थीं जिन्हें, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया या दूसरे बोर्ड मन्जूर नहीं कर लें, तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, इस वास्ते कुछ शोर्ट फाल हुआ हैं और इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में निवेदन करूं कि हम दो साल, तीन साल से केच अप कर सके हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो तब तक इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनना मुश्किल हो जाता है। कुछ इस प्रकार की स्कीम्स हैं, जिनमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर सकें, इस प्रकार की कोशिश करेंगे। इस तीसरी योजना बनाने के सिलसिले में मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम बनाते हैं, जैसे देश का प्रोडक्ट बढ़े, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बढ़े, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़े, माइनिंग सेक्टर के अन्दर प्रोडक्शन बढ़े, इस प्रकार जब ओवर ऑल प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, तो नेशनल इन्कम बढ़ती है, यह माना हुआ सवाल है। तो प्रोडक्शन बढ़े, जो मैन पॉवर है, उसको युटिलाइज़ कर सकें, मैन पॉवर को एम्प्लॉयमेंट दे सकें।

तीसरी बात यह है कि मैन पॉवर को ज्यादा से ज्यादा लोन्स दे सकें, ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारी नेशनल इन्कम भी बढ़ सके। तो इस प्रकार की चीजें हैं, उनको देख कर हमको हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना बनानी है और जैसा कि आपको इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अलग-अलग तरह के आंकड़े मिले हैं, उनसे आपको पता चलेगा।

उद्योग विभाग की तरफ से जिस प्रकार की सहायता छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिए दी गई, इसका नतीजा क्या आया? सवाल यह देखने का है कि दरअसल उन असिस्टेन्स व उन फैसिलिटीज़ का, जो स्टेट ने उन लोगों को ग्रान्ट की, उनका नतीजा हमारे पास क्या आया? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जो असिस्टेन्स, या जो लोन हम देते हैं, इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने में या सब्सिडी इन पॉवर देते हैं या और प्रकार की हैंड लूम इन्डस्ट्री के अन्दर शेअर केपिटल को खरीदने के लिये लोन देते हैं या रुपया देते हैं, या अच्छे लूम्स देते हैं, या पॉवर लूम की स्कीम है, इस प्रकार के जो स्टेट की तरफ से कार्य करने

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के थे, उन सबका नतीजा यह हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां २०० इन्डस्ट्रीज़, यानी ४०० एक साल में इनकी वजह से लगी हैं और उनमें ६४० इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री, ६२ नॉन फेरसमेटल इन्डस्ट्रीज़, १५० केमिकल इन्डन्ट्रीज़ व १०० दूसरी और इन्डस्ट्रीज़ धीरे धीरे लगीं। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी हुआ, इनके अन्दर, जैसा कि आपको बताया कि ३२१ लाख रुपया हम खर्च करेंगे और राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ने जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ इनको दी हैं, उसका रुपया अगर हम ८० लाख मान लें, तो करीब ४०१ लाख रुपया होता है, तो एक तरह गवर्नमेंट असिस्टेन्स समझ लिया जायगा, वह भिन्न भिन्न आदमियों को मिला। यह असिस्टेन्स देने के बाद दूसरे प्राइवेट पर्सन्स, जो इन्टरप्रिन्योर्स हैं, उनका कितना हुआ। वैसे टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जितना पैसा गवर्नमेंट का इन्वेस्ट होता है, उसका करीब करीब दुगना होता है, इस प्रकार ८०२ लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से १२०३ लाख इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का और उनका, दोनों का मिला कर हुआ है। इसका रिज़ल्ट, जैसी कि श्री लोकनाथन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुछ रेश्यो बताये हैं, इसमें २४ हज़ार जोब्स, इस सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे मिली और थर्ड फाइव इयर प्लान में जो असिस्टेन्स देना चाहते हैं, उससे करीब ५० हज़ार को जोब्स मिलेंगी। थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर, जिसके आपके सामने विवरण भी दिये गये हैं, उसके अवलोकन से प्रतीत होगा कि किस प्रकार सहायता सरकार की ओर से दी जाती है और देनी चाहिए? उसका थोड़ा ढांचा आपके सामने रखा था। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मुलाहिजा करेंगे तो जो फाइनेन्शियल असिस्टेन्स हम देते हैं, उसमें या तो हम डाइरेक्ट लोन्स की शक्ल में देते हैं या गारन्टी की शक्ल में। गारन्टी इस प्रकार से करते हैं कि स्टेट गारन्टी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने एप्रूव की है और उसके अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शिड्यूल्ड बैंक्स अपोइन्ट कर देगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर, वह डिस्ट्रिक्ट मुकर्रर करने के बाद, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पॉइलट प्रोजेक्ट्स के लिए शिड्यूल्ड बैंक्स अलग अलग आदमियों को लोन्स देगी और वह स्टेट की गारन्टी पर देगी। स्टेट गारन्टी दे देती है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : स्टेट बैंक ने कौनसे डिस्ट्रिक्ट्स को इन्टेन्सिव वर्क के लिए सिलेक्ट किया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जयपुर डिस्ट्रिक्ट।

मेरा निवेदन था कि डाइरेक्ट लोन हमारे थ्रू राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से लोन्स एन्ड असिस्टेन्स ओवर एन्ड अबव स्टेट गवर्नमेंट देती है, इस प्रकार से क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक इन्स्टिट्यूशनल फाइनेन्सिंग है, डाइरेक्ट लोन्स दिये जा सकते हैं, ताकि असिस्टेन्स मिल सके। इसी तरह से इन्डस्ट्रियल एस्टेट का कार्य हो रहा है और अगली तीसरी पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ ७५ लाख खर्च

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

करने का प्रावधान है । इसके साथ साथ यह स्कीम निकली है कि कुछ लोग मिल कर, कम्पनी बना कर, इन्डस्ट्रियल एस्टेट कम्पनी या इन्डस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लें, कुछ रुपया इकट्ठा कर लें, तो स्टेट गारन्टी करके उनको लोन दिला देगी और उससे इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन जायेंगे । इस तरह से जो प्रोग्राम रखा है उससे फायदा हो सकता है । इसलिये मैंने जो निवेदन किया कि जो रुपया हमने रखा है वह अलग अलग स्कीमों के अनुसार रखा है, लेकिन गारन्टी देकर जो रुपया रखा गया है वह अलग है। लोग-बाग इसमें आगे आवें तो आगे बढ़ सकते हैं ।

इसी तरह से वर्किंग शेड का रुरल ऐरियाज़ में भी प्रावधान रखा है और इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट का जो हमारा बैकवर्ड एरिया, डेफर्ड एरिया है । उनमें जाकर हम कुछ इन्डस्ट्रियल एरिया के वर्क शेड के लिए पर्सुएड कर सकते हैं । कुछ ऐसे वर्कशेड मिल जाते हैं तो उनमें उद्योग लग सकते हैं, उसका भी प्रावधान रखा है ।

इसी तरह हम चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग मिले और स्माल इन्डस्ट्रीज़ के लिए कॉर्पोरेशन बनाने का भी प्रावधान है और वह ५० लाख की पूंजी से बनना चाहिये । इसके दो डाइरेक्टर होंगे; एक तो प्रोटेक्शन फॉर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को वे हेल्प करेंगे और दूसरा रॉ मेटीरियल जितना भी उनको मिलना है उसको पूरा करें और सप्लाई करें । इस प्रकार का प्रावधान होने से उन लोगों की डिफिकल्टीज़ जो होती हैं काफी दूर होंगी जिनको वे कॉमर्शियल बेसिस पर हल नहीं कर सकेंगे ।

इसी तरह से खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज़ को भी सहायता देने का प्रावधान रखा है । इसके अलावा हैन्डलूम और हैन्डीक्राफ्ट की स्कीम है जो इसमें बताई गई है । इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में हमारा क्या टार्गेट होगा इस पर भी आपने मुलाहिज़ा किया होगा तो उसमें दिया गया है कि जो हमारा टार्गेट है उसके अनुसार हम करीब करीब २० हज़ार आदमियों को फुलर टाइम एम्पलोयमेंट दिला पायेंगे । इसका मतलब यह होगा कि वे लोग दूसरे काम भी कर सकते हैं । वे अधिकतर काम उद्योग में ही करेंगे । उद्योग के सम्बन्ध में ५० हज़ार आदमी ऐसे होंगे जिनको होल टाइम काम मिल सकता है । तो मेरे निवेदन करने का यह मतलब है कि सरकार का जहां तक सम्बन्ध है सरकार हेल्पिंग हैन्ड देती है । इसके बगैर छोटे उद्योग फलने वाले नहीं हैं । इसके अलावा और भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं और आपको सुन कर खुशी होगी कि हमने सेन्टर चालू कर रखे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बीकानेर में वुलन एन्ड कारडिंग, फिनिशिंग सेन्टर है । अब वह ठीक प्रकार से चलाया गया है । इससे उन लोगों को वुलन इन्डस्ट्रीज़ के बारे में काफी कार्य हुआ है । यह तो उनको मदद देने के जरिये है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे २ जितने भी उद्योग लगाने वाले हैं उनको सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद देकर उनको हर प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ।

आपने अभी राजस्थान में भी देखा कि

Page No.86

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कुछ राजस्थान के लोगों का भी उद्योगों के प्रति विचार हुआ और वे आगे भी आये और काम करने की इच्छा रखते हैं और हमारे यहां टेम्पो भी बना है। मैं इच्छा रखता हूं कि हर प्रकार से सरकार उद्योग के बारे में जागरूक रहे। इसके बारे में जो भी रीज़नेबल फैसिलिटीज़ हैं और हो सकती हैं, हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि यहां पर पॉवर सप्लाई दूसरी जगहों से बहुत महंगी होती है और बाहर दूसरे स्थानों पर पॉवर सप्लाई सस्ती मिलती है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो दूसरे देशों के मुकाबले में यहां पर बिजली का पॉवर महंगा मिलता है उसका यह कारण है कि वहां हाइडल पॉवर जेनरेट हुई है। उसकी वजह से रेट्स कम हैं, लेकिन हमारे यहां पॉवर पोज़ीशन जिस प्रकार थी और आयन्दा होने वाली है उसमें निश्चित तौर से रेट कम होगी। अब सरकार ने जो कन्सेशन देने का तय किया है वह यह है कि पहले तीन आना युनिट था। अब २० हज़ार युनिट पर मन्थ खर्च करेंगे। उसको दो आना रखा है। इसके अलावा उसको सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार से १॥ आने की सप्लाई करने का रखा है। यह सारे पॉवर की स्थिति पर निर्भर है। अभी अभी पॉवर....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने अभी पॉलिसी को डिक्लेअर नहीं किया है। २० हज़ार से कम खर्च करेगा उसके लिए आपने कोई पॉलिसी डिक्लेअर नहीं की है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमने नहीं की है, इसकी जरुरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे पॉवर में है। हम उनको सब्सिडी देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जितनी सब्सिडी देने को थी, हमने खर्च कर दी। अब तो वैसे भी हाइडल पॉवर आने वाली है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद और भी पॉवर चीपर मिलेगा। मैं समझता हूं कि कुछ स्लेब्स के अन्दर....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लोरिफिकेशन चाहता हूं। भारत सरकार की इन्डस्ट्रीज़ को पॉवर देने की रेट में कन्सेशन की पॉलिसी है। क्या आपने राजस्थान में भी उसी प्रकार के कन्सेशन देने की घोषणा की है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार की नीति है उसमें उन्होंने यह जरूर कहा है कि छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको १॥ आना पर युनिट से ज्यादा में पॉवर नहीं मिलनी चाहिये लेकिन हम अपनी स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है, मगर भारत सरकार की पॉलिसी को आपने माना है। मगर उसको मानने के बाद में आपने उस पर अमल नहीं किया और अपनी मान्यता के विपरीत करते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जहां तक हो सकता है स्टेट को १॥ आना से ज्यादा नहीं लेना चाहिये। हमने इसीलिये सब्सिडी का

Page No.87

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

प्रावधान रखा है। अगर दो आना आता है तो आधा आना सब्सिडी के रूप में दे देते हैं। तो इस हिसाब से भी उनको डेढ़ आना में पॉवर मिलता है। उनको सब्सिडी देने का प्रावधान है इसलिये दो आने में भी उनको सब्सिडी मिलने पर १॥ आना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will please conclude now.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार से उद्योगों को अलग अलग प्रकार से दिये जाने का प्रावधान था। मैंने आपको निवेदन किया कि जो हमारी टैक्सटाइल मिल्स हैं उनको मदद दी और जिस प्रकार से दी है उसकी भी स्थिति मैंने आपके सामने रखी है।

अब उन इन्डस्ट्रीज़ के बारे में जो विभाग की ओर से बजट पेश किया है उसमें बताया गया है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की कौन–कौन सी ऐसी इन्डस्ट्रीज़ हैं जो हमारे राजस्थान में लगाने के लाइसेन्स हो चुके हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि १० या ११ करोड़ रुपयों के लगभग तो इनमें इन्वेस्टमेंट हो जायेंगे। जैसा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में, मैं समझता हूं कि हमारी फर्टेलाइजर, जिन्क स्मैल्टर, लिनग्नाइट, कैमिकल इन्डस्ट्री और दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हमारे यहां लगें तो उनमें करीब करीब ६० करोड़ लार्ज इन्डस्ट्रीज़ में और स्माल इन्डस्ट्रीज़ में २० करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसा कि लोकनाथन की इन्टेरिम रिपोर्ट में बताया गया है। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५.०४ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तो एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट होगा वह १२६.६४ का होगा।

तो मैंने यह निवेदन किया कि इस प्रकार से इन्डस्ट्रीज़ का रोल नेशन की इकोनोमी को बढ़ाने में काफी है। माननीय सदस्यों ने भी राय व्यक्त की। उसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्पोर्टेन्स तब तक रहेगी जब तक कि सेल्फ सफिशियेन्ट न हो जावें। साथ साथ इन्डस्ट्रीज़ भी ज्यादा से ज्यादा हों। उसके जरिये ही हमारी इकोनोमी बढ़ सकती है और ज्यादा पोटेन्शियल दे सकती है। इसमें भी दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए हर सूरत से हमारे यहां इन्डस्ट्रीज़ ज्यादा से ज्यादा लगें। सरकार द्वारा आश्वासन दिये गये थे। सरकार ने कन्सेशन्स को भी अनाउन्स किया। उसके बाद एक टेम्पो बना। काफी आदमी आते हैं। बाहर से भी आते हैं। उनकी इन्डस्ट्रीज़ यहां पर लगाने की भावना भी है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां इन्डस्ट्रीज़ की बहुत आवश्यकता है और लोगों की यहां पर लगाने की भावना भी है। यहां पर ऐसे लोग इन्डस्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं जो एक्सपीरियेन्स्ड पर्सन्स हैं, जिन्होंने बाहर जाकर इन्डस्ट्रियलाइजेशन किया। कन्सेशन्स नहीं देते हैं तो नहीं कर सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा पॉवर उपलब्ध कर सके और इन्डस्ट्री पनप सके। उनको बिजली सस्ती मिल जाय, ट्रान्सपोर्ट की फेसिलिटी उनको मिल जाय और रॉ–मैटियरल की फैसिलिटी मिल जाय तो इससे इन्डस्ट्रीज़ पनप सकती हैं। जैसे बीकानेर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा खर्च हो

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रहा है और दूसरे में नहीं। इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। मैं यह भी जानकारी दूंगा कि बीकानेर में २८ करोड़ रुपया फर्टीलाइज़र फेक्ट्री में खर्च होगा। पलाना लिग्नाइट में खर्च होगा। अगर वह ले लिया जाता है तो और दूसरी बहुत सारी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनमें वहां पर खर्च किया जा सकता है। यह चीज़ हर एक जगह की इकोनोमी पर ज्यादा डिपेन्ड करती है कि कहां पर ज्यादा फैसिलिटी मिल सकती है और कहां पर नहीं। आइरन स्टील प्लान्ट राजस्थान में नहीं लगाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Why not ? Big iron plants of this type are not to be installed....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That can be of a low blast furnace but it cannot be a big steel plant because we have not got that iron ore....

मेरा निवेदन था कि यह हर एक जगह की इकोनोमीज़ पर डिपेन्ड करेगा और कन्डीशन्स पर डिपेन्ड करेगा।

श्री श्रीभानसिंह : I think then the House will like to have such an Industries Minister who can justify the case for a big steel iron industry in the State...

श्री रिबचन्द धारीवाल : Case for putting a low blast furnace is justifiable and we are trying and we might have it.

श्री पी० के० चौधरी : In the private Soctor or in Public...?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Not in the public Sector .

इसीलिए मैंने यह निवेदन किया था कि जहां पर जैसी कन्डीशन्स होंगी। लिग्नाइट का उदयपुर में नहीं लगा सकते हैं। जहां जैसी कन्डीशन्स होंगी उसी प्रकार वहां इन्डस्ट्री लगाई जावेगी। मुझे इतना ही निवेदन करना था कि राजस्थान में हर प्रकार से इन्डस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। माननीय सदस्यों की भी इच्छा है और चाहते हैं कि इन्डस्ट्रीज़ हों। मैं समझता हूं कि हम आपके सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से तृतीय पंचवर्षीय योजना पर सदन में बहस चल रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी योजना हो, उसका आधार वित्तीय होता है। बिना धन के कोई भी योजना आपकी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती है और धन के साधन भी जितने हम अपने राज्य में जुटायेंगे और बढ़ायेंगे उतनी वह योजना या उस योजना का फल स्थायी रूप से हमारे हाथ लगेगा। यह सही है कि आज जैसी जगत की परिस्थिति है उसमें कोई भी एक देश या कोई भी एक राज्य केवल अपने

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ही वित्तीय साधनों से विकास की बड़ी २ योजनायें पूरी नहीं कर सकता है इसलिए दूसरे देशों की सहायता या राज्यों की सहायता आवश्यक हो गई है फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जितने हम अपने वित्तीय साधन बढ़ायेंगे उतनी ही हमारे राज्य की स्थिति मजबूत होगी। इस दृष्टि से मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अपने राज्य के अन्दर हम अपने अन्दर के वित्तीय साधनों को दिन प्रति दिन दृढ़ करते जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, १९५७ के प्रारम्भ में करीब ११ करोड़ के साधनों का अन्दाज हमने किया था और १३.४० करोड़ तक हम पहुँच गये। जो हमने अनुमान किया था उससे ज्यादा हमने उसमें सफलता प्राप्त की। वैसे १०५ करोड़ का हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उसमें हमें कुल ३१ करोड़ के साधन जुटाने थे, उसमें से १३ करोड़ ५० लाख के साधन टैक्सेशन से जुटाने थे। ३१ की जगह ४० करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

कृषि के आधार पर और उससे उत्साहित होकर तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में दुगुनी योजना है और जो वित्तीय साधन उसके लिए हम जुटाना चाहते हैं वे हैं ८१.७७ करोड़, लगभग ८२ करोड़ के। योजना दुगुनी है तो वित्तीय साधन भी दुगुने रखे हैं। इस तरह से ८१ करोड़ के साधन जुटाने का हमने संकल्प किया है। और हमें यह पूरी आशा है कि हम उन साधनों को जुटा लेंगे फिर भी अभी प्लानिंग कमीशन से विचार–विनिमय अन्तिम रूप से होना बाकी है और यह मान कर चलना चाहिये कि संभवत: ८१ करोड़ में से भी साधन जुटाने का जो हमारे ऊपर भार है वह हम पर कम आये। वैसे हमारी तैयारी तो पूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही इस बारे में उल्लेख किया था और उनके द्वारा वित्तीय साधनों पर भी प्रकाश उस समय डाला गया था फिर भी माननीय सदस्यों के लिए कुछ और रोशनी मैं भी आपके सामने यहां डाल दूं।

आप यह पूछ सकते हैं कि जो हमने थर्ड फाइव इयर प्लान का फ्रेम आपके सामने दिया, उसमें ९८ करोड़ ८४ लाख, करीब करीब ९९ करोड़ के वित्तीय साधन जुटाने का प्रश्न रखा था।

बाद में फिर हमने जब दुबारा विचार किया तो हमने ज्यादा कन्ज़र्वेटिव साइड में अपने अनुमान रखे। पहला जो फ्रेम रखा गया उसके बाद तीन, चार, पांच महीनों का जो अनुभव हुआ उससे लाभ उठाकर कुछ मदों में कम रकम हमने मानी, जैसे बैटरमेंट लेवी है वह दो साल से हम बराबर देखते आ रहे हैं इसमें बहुत कम रकम वसूल होती है। वह रकम हमने उसमें से निकाल दी। इस प्रकार से जो हमने ८१.७७ लाख के साधन माने हैं उनमें रेवेन्यू अकाउन्ट में जो रकम प्राप्त करेंगे खर्चे के बाद वह करीब ११.९१ यानी १२ करोड़ के करीब समझ लीजिये, है। केपिटल अकाउन्ट ४९.८६ लाख और नये अतिरिक्त करों से बीस करोड़ रुपया हम प्राप्त करना चाहते हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) :

(श्री चन्दनमल वैद)

क्या इन बीस करोड़ में वे १३॥ करोड़ भी शामिल हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ओवर एण्ड अबव और लेंगे । इसके अलावा और भी हो सकते हैं दूसरे भी हो सकते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : ये १३॥ करोड़ के अलावा २० करोड़ के नये कर और लगेंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, ये बीस करोड़ नये हैं । तो जो यह कहा जाता है कि इतने करों का भार जनता किस प्रकार उठायगी, यह जो एक प्रकार ध्वनि निकलती है कि कहां तक लोग इसको बर्दाश्त करेंगे । मैं यह अपनी भाषा में कह रहा हूं, मैं आपके सामने बता देता चाहता हूं कि हमारी कमर टूटी नहीं जा रही है, हम तो सीना तानकर खड़े हो रहे हैं और जो करों का भार बीस करोड़ का रखा गया है वह बिल्कुल अधिक नहीं है, दूसरे राज्यों के मुकाबले अब भी बहुत कम हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि करों का इन्सीडेन्स किस किस राज्य में कितना कितना है, हमारे अपने राज्य में ११.६ है वह भी इस वक्त है । इसके मुकाबले :

आन्ध्र में	१२.१३
आसाम में	१४.५३
बम्बई में	१५.४१
मद्रास में	११.६०
मैसूर में	१२.५१
पंजाब में	१४.६३
राजस्थानों	११.६

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उड़ीसा में कितना है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उड़ीसा में ५.३५ है । क्या आप उड़ीसा की तुलना राजस्थान से करेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या ये डाइरेक्ट टैक्सेज़ या इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ भी इसमें शामिल हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों ही मिलाकर मानना चाहिये । मैं तो आपको मोटे तौर पर आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो २० करोड़ के अतिरिक्त कर लगा रहे हैं, यह ऐसी चिन्ता करने लायक स्थिति नहीं हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा प्रान्त जिसको मानते हैं उसको आप ज्यादा कर भार से लादना चाहते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : करों का भार बढ़ेगा तो आखिर पोटेन्शियलीटी देख कर ही हमारी जो पोटेन्शियलीटी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं । राजस्थान में यह कर लगना कोई चिन्ता का विषय नहीं हैं । यह जरूर है कि हम विकास के क्षेत्र में कुछ राज्यों से पिछड़े हुए हैं, किन्तु हमारी अन्तर्निहित शक्ति काफी ज्यादा है इसलिए यह बीस करोड़ रुपया जो हम कर के रूप में वसूल करना चाहते हैं इसमें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

तीन बातों के ऊपर जैसा कि मैंने पहले सदन में निवेदन किया, उन दृढ़ आधारों पर ये अनुमान बनाये गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने ८१ करोड़ के साधन तय किये हैं उनके लिए काफी ठोस आधार हैं और जो कर लगाने की बात कही है उससे किसी को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मानता हूँ, अगले वर्षों में और भी अधिक भार बढ़े और अधिक कर लगाने की भी गुंजाइश यहां पर है। इसलिए हमें इतने से कर से चिन्तित नहीं होना चाहिये, और भी कर लगाने की आवश्यकता हो तो वह भी लग सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जो राजस्थान सरकार ने रखी है उस पर विचार हो रहा है। मेरी समझ में यह जो २१२ करोड़ की योजना रखी है इससे भी ज्यादा रखते तो कोई बात नहीं थी लेकिन इस योजना के बारे में जिस तरह से २१२ करोड़ की बना कर रखी है उससे भी कम की रखना चाहिये था। आज राजस्थान के अन्दर कम खर्चे में ज्यादा काम हो ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिये। राजस्थान में दो पंचवर्षीय योजना पूरी होने आयी हैं, प्रथम योजना में जितना रुपया लगा है उतना राजस्थान में काम नहीं हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी। रुपया जरूर खर्च हो जाता है, योजनायें जरूर बनती हैं, लेकिन जितना रुपया खर्च होता है उतने रुपये का काम वास्तव में होता नहीं है यह सब जानते हैं और मैं भी यही मानता हूं। आज इस योजना को प्रेक्टिकल रूप में देखा जाय तो यह जो प्लान में हम रुपया रख रहे हैं यह बड़ी मेहनत और जनता के पसीने की कमाई का पैसा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपके पास कितना है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : व्यक्तिगत तो मेरे पास मेरे कपड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह सब जो सरकार चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं वे यदि यह मान लें कि यह जो रुपया खर्च हो रहा है वह हमारा है, तो जहां आप २१२ करोड़ रुपये में इतना काम कर सकते हैं जिसकी कीमत ३०० करोड़ रुपये तक हो सकती है, लेकिन हर आदमी आज यह मानता है कि सरकार का रुपया दूसरा है और हमारा रुपया दूसरा। इसलिए जहां सरकार का रुपया खर्च होता है वहां अपना आठ आना ही खर्च करेंगे। आज ये दो चीजें चल रही हैं; एक तो सरकार के रुपये को अपना रुपया नहीं समझा जाता, इसीलिये जो योजना में काम होना चाहिये उतना काम नहीं हो पाता। इसलिये मेरा निवेदन

Page No.92

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है कि सरकार के रुपये में और अपने रुपये में फर्क न समझ कर काम किया जाय तो इतने से रुपये में बहुत बड़ा काम हो सकता है।

आज राजस्थान सरकार ने पंचायतों के आधार पर योजना बनाने की स्कीम सोची लेकिन मैं कई दफा इस विधान सभा में यह कह चुका हूँ कि जहां सरकार यह मानती है तीसरी योजना हमारी पंचायतों से बनकर आये, वह नहीं आयी। जयपुर ज़िले के अलावा दूसरे जिले की पंचायतों से यह योजना बनकर नहीं आयी फिगर्स जरूर वहां से इकट्ठे कर लिये हैं। डीसेन्ट्रलाइजेशन होने के बाद भी उन प्रधानों, एम. एल. एज़., पंचों और सरपंचों को पता नहीं है कि पंचायत के आधार पर योजना बन रही है। यह जरूर है कि जयपुर जिले में जिस तरह की योजना बनी उस तरह दूसरे जिलों में भी पंचायत के आधार पर योजना बनाते, तो माननीय उपाध्यक्षजी, जरूर जनता को मालूम होता कि यह जो योजना है, हम से पूछ कर बना रहे हैं और हमें पूछकर इस पैसे का उपयोग करना चाहते हैं। यह मैंने देखा। जनता में हम भी गये अफसर भी गये और उनको यह मालूम हुआ कि आज हमारे जिले में अफसर, एम. एल. ए., पंच, सरपंच और प्रधान एक साथ बैठकर योजना बना रहे हैं और इसमें जो धनराशि खर्च होगी वह हमारी राय से होगी और इसके अलावा हमारा भी एक फर्ज है कि हम भी उतनी धन-राशि इकट्ठा करें श्रमदान से या पैसे से या किसी और तरह से और इससे अपने यहां विकास के काम करावें। पर इसमें भी सूचना बहुत थोड़े समय पहले मिली; बीस दिन पहले, जब कि योजना के बनाने से करीब एक महीने पहले तो सूचना मिलनी चाहिये थी। अच्छी तरह से तो सात-आठ महीने पहले पंचायतों को पूछना चाहिये था तब मालूम होता कि कौनसे जिले में पानी की कमी है और कौनसे जिले में नोन इरिगेशन की खामी है, कौनसे जिले में सड़कों की कमी है और कौनसे जिले में स्कूलों और डिस्पेन्सिरियों की कमी है और कौन से जिले में लोग धनराशि राजस्थान सरकार को डेवलपमेंट के कामों के लिए देने को तैयार है और कौनसा जिला, जहां धनी-मानी लोग नहीं हैं श्रम से धन के बराबर काम देने को तैयार हैं। पहले भी जितनी योजनाएं बनीं वे पंचायतों के आधार पर पूरी तरह से नहीं बनीं।

श्री उपाध्यक्ष : विदेशों का क्या अनुभव है आपका ? कैसे बनती हैं वहां योजनाएं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : विदेशों में मैंने पहले भी हाउस में बताया था, दो पंचवर्षीय योजनाएं रशिया में, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना..

डॉ० बहादुरसिंह : वहां तो सप्तवर्षीय है।

श्री उपाध्यक्ष : अब पांच हो गई, आपके जाने के बाद।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सप्त होगी, मैं फर्स्ट प्लान बोल रहा था। फर्स्ट प्लॉन जो बनी उसमें प्लानिंग कमीशन के कमिश्नर, मिनिस्टर आदि से हमारा डेपुटेशन मिला

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

और उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका के आधार पर यह योजना पहले बनाई और उसमें सफल नहीं हुए। पर दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो बन रही हैं वे पंचायतों के आधार पर हम बना रहे हैं और हमें इस बात का विश्वास है कि पंचायतों के आधार पर योजना बनाने से हमारे को सारी जगहों की जरुरतों के फिगर्स मालूम होंगे और इसमें हम सफल होंगे।

उन्होंने बताया कि पंचायतों के आधार पर बनी योजना हमारे पास है। जब योजना उनकी बन रही थी उस वक्त ही मैं उधर गया था क्योंकि पंचायतों के आधार पर योजना बनाने से, उनका ऐसा ख्याल था कि हमें जनता का काफी सहयोग मिलेगा, धनवान लोग तो यहां हैं नहीं कि जो रुपया हमें दें, पर श्रम से हम विकास कर सकें, ऐसी उनकी भावना थी।

जब दूसरी योजना बनने की शुरूआत थी तब भी मैंने हाउस में यह बात कही थी और जब उसके बनने की शुरूआत नहीं हुई थी उसके पहले भी बार बार इस हाउस में कहा था कि तीसरी योजना जो हमारी बने वह पंचायतों के आधार पर बने और योजना के चालू होने के साल भर पहले से पूरी तरह से पंचायतों के पास से आ सकती थी। परन्तु हमारे जयपुर जिले में भी बीस दिन पहले इन्होंने इत्तला दी और उसके पास भी पूरे फिगर्स नहीं थे जिले के अन्दर कि जिसके आधार पर बनाई जावे। तो मैं दूसरे जिलों के अन्दर जहां कि मैंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि उन जिलों के माननीय सदस्य और प्रधान और पंच और सरपंच ने और अधिकारियों ने इतनी दिलचस्पी इसमें बनाने में नहीं ली और उन्होंने तीसरी योजना पंचायत के आधार पर नहीं बनाई।

अब जो योजना आज पेश हो रही है हाउस के सामने, वह ऊपर के आधार पर पेश हो रही है, जैसे कि दो पहले की योजनाएं ऊपर के आधार पर पेश होने से उसके अन्दर आज जनता यह नहीं जानती—स्त्री और पुरुष, कि हमारी यह जो योजना है वह हमारे आधार पर बनी है या ऊपर से जो कुछ हुआ है उसके आधार पर बनी है, वह उसकी ही मानते हैं। तो यह तीसरी योजना भी उसी तरह से हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे समाप्त करेंगे आप ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : और माननीय उपाध्यक्षजी, जो आज मेरा ऐसा कहना है कि जो आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार की तरफ से जितने भी नेशनलाइजेशन तरीके पर, डिपार्टमेंटल तरीके पर काम होंगे इस योजना के उनमें सरकार अधिक सफल होगी। जो योजना के काम ठेके पर और प्राइवेट सेक्टर के आधार पर चलाये जावेंगे उनमें सरकार का भी रुपया लगेगा ही क्योंकि पूंजीपति अपने पैसे को पूरा उसमें नहीं लगाना चाहता, वह तो सरकार से अधिक लेना चाहता है। तो सरकार से अधिक रुपया लेकर और थोड़ा रुपया अपना खुद का लगा कर कोई काम करता है तो उसमें जनता को और सरकार को लाभ नहीं होने देगा वह और इसमें भी काफी देर लगती है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

Page No.94

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

महाराज आप....

श्री उपाध्यक्ष : यह अध्यक्ष का आसन है, मैंने बार बार आपको कहा कि 'महाराज' शब्द से आसन को सम्बोधित न किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी, मैं भूल जाता हूं साहब, पांच मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनिट और दूँगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: माननीय उपाध्यक्षजी, जो इन्डस्ट्री लगाई जावे फर्टीलाइज़र का प्लान्ट या फूलोराइट का प्लान्ट लगाये जावे, तो सरकार इन्हें पब्लिक सेक्टर के आधार पर लगावें। रुपये की सरकार को कमी नहीं है। मैं आपको इस बारे में विश्वास दे सकता हूं कि आप अगर राजस्थान सरकार की तरफ से कदम इधर बढ़ावेंगे तो जनता का हर आदमी पूरी तरह से आपको सहयोग देने को तैयार है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : आप कितना देंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं एक करोड़ रुपया ले आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो प्लानिंग में एक करोड़ रुपया और बढ़ा देना चाहिये। आपका एक करोड़ रुपया और जोड़ दिया जावे इसमें ?

श्री दिलीपसिंह (बारां) : आप रशिया से भी ले आवेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रशिया से लेने को तैयार हों तो मैं बहुत ला दूँगा आपको।

तो इससे लोगों की बेकारी दूर होगी और जो रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का लगेगा उसका सदुपयोग होगा। पब्लिक सेक्टर से जनता का बड़ा भला होगा। प्राइवेट सेक्टर को हम जानते हैं। पहले भी कई इन्डस्ट्रीज़ को काफी रुपया दिया हुआ है, स्टेटों के वक्त में भी काफी रुपया दिया गया था उस रुपये का भी रिटर्न आज तक राजस्थान सरकार को नहीं मिल रहा है। वह रुपया तक आना दूर की बात है। इसलिये आज उम्मीद करूंगा कि राजस्थान में पब्लिक सेक्टर में सरकार काम करेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर इन्डस्ट्री सरकार ने खोलकर उसमें रुपया दिया तो वे लोग वापिस सरकार को रुपया रिटर्न करेंगे या कुछ रिटर्न देंगे, यह मुझको उम्मीद नहीं है।

(४. म. प.)

जिस प्रकार हमारे राजस्थान के अन्दर कई तहसीलें ऐसी हैं कि जिनके अन्दर एग्रीकल्चर के बारे में पहले इतना रुपया खर्च हुआ और आगे भी हो रहा है परन्तु कई तहसीलें ऐसी हैं कि वहां पर आज भी इरिगेशन के लिए कोई रुपया खर्च नहीं हुआ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने हैं। दूसरे जिलों में जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं वहां जयपुर जिले के अन्दर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से आशा करता हूं कि आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में जयपुर जिले का ध्यान रखेंगे....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगा।

डॉ० बहादुरसिंह : जयपुर जिले में कौनसी बड़ी नदी पर प्रोजेक्ट बनायेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान ने शिक्षा के अन्दर काफी तरक्की की है, लेकिन स्वास्थ्य के अन्दर तरक्की नहीं की। स्वास्थ्य के अन्दर जितना रुपया पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था इस बार उससे बहुत कम रखा है, उतना ही रखा है; नहीं, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा रखा है....

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है।

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा तो अच्छा है, लेकिन मेरे भाइयों का अच्छा नहीं है; तो मेरा हो या नहीं, इससे क्या ? तो माननीय उपाध्यक्षजी, एजुकेशन और स्वास्थ्य ये दोनों चीजें मनुष्यों की अच्छी होंगी तो दुनिया की जितनी भी योजनायें हैं वे चल सकेंगी। एजुकेशन अच्छी हुई और स्वास्थ्य खराब हुआ तो वह योजना कैसे चलेगी ! तो पहले तो शरीर का काम हो वह सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज़ है और राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य में बहुत कम रुपया रखा है। इसके अन्दर ज्यादा रुपया रखना चाहिए जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बढ़े और ज्यादा उन्नति कर सकें। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, स्वास्थ्य की चिन्ता होना स्वाभाविक है और अभी अन्त में जो माननीय सदस्य बोले उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ ४७ लाख थे, अब उसके बजाय तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ ७० लाख हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इस सदन के अन्दर तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में जो भाषण हुए उनको गौर से सुनने की और समझने की कोशिश की और अगर मैं यह कहूं, कुछ माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, तो कुछ ने तो इस अवसर पर भी उसी प्रकार भाषण देना पसन्द किया कि जैसा राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर आम तौर से यहां पर अपनी तरफ से चर्चायें होती हैं। मैं उनके विस्तार में इसलिए नहीं जाऊं तो मुझे क्षमा किया जायेगा क्योंकि उसकी आवश्यकता इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के चर्चा के दौरान में न हो, इसलिए मैं प्रयत्न यह करूंगा कि जहां तक सम्भव हो सके मैं उन्हीं चीजों के बारे में अपनी बात कहूं कि जो योजना से सम्बन्धित बातें हैं और दूसरी चर्चाओं के बारे में अपने आपको ज्यादा कहने के अन्दर न उलझूं। सबसे पहले तो जो अन्तिम बोलने वाले माननीय सदस्य थे उनकी बात को लेकर चलूं। उन्होंने कहा कि पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा योजना बनवाई गई; लेकिन अभी जो आंकड़े, जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर ही चर्चा की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो

Page No.96

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ये आंकड़े अभी तैयार किये गये हैं इन आंकड़ों को तैयार करने के अन्दर जो पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अन्दर अलग अलग ट्रैन्ड्स रहे हैं उनका ख्याल रखा गया है और अन्तिम रूप से जिला परिषदों के और पंचायत समितियों के क्या प्लान बनें, वह तो जब केन्द्र में जाकर सारा स्वरूप इसका क्या बनता है उसके बाद ही उसको अन्तिम रूप दिया जा सकता है। उसको पहले अन्तिम स्वरूप देना सम्भव नहीं हो सकता। लेकिन डीसेन्ट्रलाइजेशन की वजह से किन किन चीजों के ऊपर जोर देना चाहिए और क्या पंचायत समितियों में ऐसी योजनाओं के बारे में, जिनके लिए मैन पॉवर के यूटिलाइजेशन की दृष्टि से और आर्थिक साधनों की दृष्टि से पचायत समितियों योग देने में सफल होंगी, उन बातों का ख्याल इसमें रखा गया है। यहां पर चर्चा के दौरान में, उपाध्यक्षजी, इस बात को कहा गया कि हमारी यह तृतीय पंचवर्षीय योजना भी ज्यादा कृषिप्रधान योजना है और इसके अन्दर हमें उद्योग के लिए और उसकी तरक्की के लिए जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी वह कम है और इसी सिलसिले में इस बात को भी कहा गया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए औद्योगिक प्रगति होना आवश्यक है। कृषि की प्रगति या कृषि के ऊपर आधारित योजना पर हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने राज्य की पंचवर्षीय योजना को देश की पंचवर्षीय योजना से अलग नहीं देख सकते और हमें इस बात को लक्ष्य में रख कर चलना होगा कि हर योजना यदि राज्य के आधार पर बनाई जाये कि उसके अन्न की पूर्ति के लिए कितने अन्न की आवश्यकता है और सारे देश की आवश्यकता को ध्यान में रख कर योजना नहीं बनाई जाये तो वह राष्ट्रीय योजना नहीं बन सकती। बल्कि आधार यह बनाना होगा कि देश की जो कम से कम आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो और उसके साथ ही साथ इस बात को भी लक्ष्य में रखा जाये कि जो देश के विभिन्न प्रदेशों के अन्दर पोटेन्शेलिटी है, जो उसकी शक्ति है, देश भर की ताकत बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सकता है उसका जब हम लक्ष्य लेकर चलते हैं तो औद्योगिक प्रगति के लिए, कृषि की प्रगति के लिए भी हमें जरूर विचार करना होगा। केवल यही नहीं, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, इन्टेन्सिव कल्टीवेशन होना इस बात के लिए भी आवश्यक है कि जो आज भी ७० प्रतिशत के करीब गांवों में रहने वाली जनता है, चाहे जमीन उनके पास हो, उससे अधिक उत्पादन करें और अपनी आय में वृद्धि करें। क्योंकि उनकी आय की वृद्धि तो किसी और सेक्टर में करने से नहीं हो सकती। वे खुद खेती से पैदा करें, उनको सिंचाई के साधन ज्यादा मिलें, फर्टीलाइज़र ज्यादा मिले, अच्छा सीड मिले और उनकी आमदनी भी अवश्य बढ़े। उसकी तरफ देखना जरूरी होगा क्योंकि इस समय भी हमारे प्रदेश की ५० प्रतिशत से ज्यादा और भारत में भी करीब–करीब उससे कम लेकिन उसके आस-पास जो हमारी कुल आय है वह जाकर कृषि से हमको मिलती है और उस आय की वृद्धि सारे प्रदेश के ऊपर काफी असर डालने वाली होगी। अगर उसके अन्दर २० प्रतिशत भी बढ़ोत्तरी होती है तो जिसको कि हम पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

केपिटा कहते हैं उसके ऊपर काफी असर होता है। इसलिए हम कृषि की बात को कतई भुला कर नहीं चल सकते। दूसरी बात यह भी जरूर है कि आज जिस औद्योगीकरण की बात करते हैं उसके लिए आवश्यक है कि औद्योगीकरण हमारा ज्यादा तेजी से तभी हो सकता है जब कि खेती का उत्पादन बढ़े। जैसे मेम्बर्स स्टेबिलाइजेशन की बात करते हैं वह तभी सम्भव है जब कि कृषि का उत्पादन बढ़े क्योंकि आज जब प्लान की रचना की जाती है तो यह सवाल भी उठ खड़ा होता है कि भाव बढ़ जायेंगे। भाव बढ़ने से रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए सोचा जाना चाहिए और सोचा जाता है।

मैं भी इस बात से सहमत हूं कि प्लान को ठीक तरह से चलाने के लिए प्राइसेज़ स्टेबिलाइज़ हों और आवश्यकता हो तो मैं व्यक्तिशः और और लोग भी जो यहां पर उपस्थित हैं इस बात को मानते होंगे कि आवश्यकता हो तो स्टेट ट्रेडिंग भी हो उसके लिए, लेकिन प्राइसेज़ स्टेबल हों, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर भी इस चीज़ ने काफी असर डाला है। हमारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर इसने असर डाला, यहां तक कि हमारी स्वास्थ्य की योजनाओं और सड़कों की योजनाओं पर इसने असर डाला और रात-दिन कोई न कोई समस्या खड़ी होती है और इस तरह से यह स्पायरल बन जाती है और यह मंहगाई जो है वह सारी योजनाओं पर असर डालती है। उसको खत्म करने के लिए देश में यह वातावरण बन रहा है कि इंडस्ट्रीयलाइजेशन करना चाहिए लेकिन इसके लिए हम खेती का उत्पादन न बढ़ाएं तो प्राइसेज़ स्टेबल कभी हो नहीं सकतीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि देश को आज जहां पर कि हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता हैं वहां खेती का उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यह प्रथम आवश्यकता है क्योंकि उसके बिना आज आप मशीनरी बाहर से मंगाएं उसके लिए फोरिन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है, और चीजों पर भी खर्चा करना पड़ता है, उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि अगर आज हम खाने की चीजें बाहर से मंगाते हैं, चाहे वह गेहूं हो, चावल हो तो उससे उतना औद्योगीकरण हो नहीं सकता। यदि कृषि का सुधार हो जाता है, हम बाहर से खाने-पीने की चीजें मंगाना बन्द कर देते है तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हमें और मदद मिलती है। यह बड़ा बेसिक सवाल है। कोई यह समझे कि खेती में डेफिसिट रह कर औद्योगीकरण कर सकें तो यह सम्भव नहीं हो सकता और इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य रखा गया और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य रखा जा रहा है। लेकिन सारी योजना केवल कृषि तक ही सीमित कर दें और हम औद्योगीकरण न करें तो भी हम पिछड़ जाते हैं। दोनों साइड को बराबर मान कर, बेलेंश करके चलना होगा यह समझते हुए कि आज के युग के अन्दर बिना औद्योगीकरण विकास के, फिर चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे देश की प्रगति का सवाल है, आगे बढ़ सकना कठिन है। तो कृषि का उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन या उद्योगों की प्रगति इन दोनों को अलग अलग करके नहीं चल सकते। ये दोनों चीजें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साथ साथ जुड़ी हुई हैं और हमें दोनों ही दिशाओं के अन्दर प्रगति करनी है। इन सारी योजनाओं पर निगाह डालें तो स्पष्ट तौर से मालूम होगा कि कहां, किस क्षेत्र के अन्दर जो कुछ हमने प्रावधान किया है उसके मुकाबले में औद्योगीकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हैं, उसका ख्याल रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हम जब कभी इसके बारे में विचार करें, औद्योगीकरण के बारे में तो हमें यह अच्छी तरह समझ कर चलना है कि औद्योगीकरण के लिए, उद्योगों के विकास के लिए या माइन्स के आंकड़ों में हमने कितने करोड़ रुपये प्रोवाइड किए हैं। औद्योगीकरण में एक तरफ तो पब्लिक सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्ट्रोल करती है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है जिसे प्राइवेट पार्टीज इंडस्ट्रीज के रूप में लगाती हैं। वही सब से बड़ा इसके अन्दर, इंडस्ट्रीयलाइजेशन में पार्ट प्ले करने वाली चीज होती है। दोनों ही चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि बिजली का प्रावधान कितना है और उसके अनुसार ही आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे सामने दिक्कतें रहीं, कमियां रहीं औद्योगीकरण की दिशा में, उसका मूल कारण हमारे सामने बिजली की कमी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कदम हमने इसके लिए उठाए, उसके बारे में हमारे जो इस विद्युत विभाग के मंत्रीजी हैं उन्होंने आपको बताया और मैं भी संक्षेप में पहले बतला चुका हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में और उसके साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए भी इसमें सोचा गया है। किसी भी योजना को केवल पांच साल के लिए ही समझ कर कभी नहीं चलना चाहिए, प्लान के आगे का एक प्रोस्पेक्टिव व्यू लेकर चलना है। दस, पन्द्रह या बीस साल तक यह चलने वाली हैं, इनका असर पड़ने वाला है। उस लिहाज़ से ही बिजली के लिए हमने यह रखा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी बिजली उपलब्ध हो सके और उसके बाद चौथी योजना के बारे में भी कहा गया कि पौंग डेम, ऑटोमिक पॉवर वगैरह से ज्यादा से ज्यादा बिजली प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। बिजली के अन्दर आम तौर से यह मान्यता है कि बिजली को जब खर्च करने का सवाल आता है इंडस्ट्रीज के अन्दर, एक किलोवाट बिजली कन्ज्यूम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, अगर मैं गलत न होऊं, तो करीब २, नौ सौ साठ रुपये के आस पास एक किलोवाट बिजली को युटिलाइज़ करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो इससे अन्दाज होता है कि जितनी पॉवर हम यहां पर करने वाले हैं उसको युटिलाइज़ करने के लिए कुल मिला कर, चाहे वह पब्लिक सेक्टर हो चाहें वह प्राइवेट सेक्टर हो, किस तरह से रुपया लग सकता है। यह ठीक है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कुछ हिस्सा होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ और चीजों में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, दूसरे इन्वेस्टमेंट भी काफी मात्रा में करने पड़ेंगे, उस पॉवर को युटिलाइज़ करने के लिए। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो आवश्यक चीज है पॉवर, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए प्लान के अन्दर ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस ४५ करोड़ रुपये के जरिए जैसा मैंने आपको बताया कि करीब तीन लाख किलोवाट बिजली तृतीय पचवर्षीय योजना में राजस्थान को मिल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सके, इसकी व्यवस्था की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे जो पॉवर जेनरेट हैं, सच बात तो यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही एक प्रकार से इस इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियलिटी मिलने वाली है राजस्थान को और इस बात को हमें ध्यान में रख कर चलना है। मैं समझता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान दिया गया है। यह ठीक है कि और ज्यादा हम कर सकते तो अच्छा होता। लेकिन चारों तरफ, सब सेक्टर्स को बेलेन्स्ड तरीके से चलाना होता है और इसीलिए ज्यादा खर्च करना सम्भव नहीं हो सका है, जितना सम्भव हो सका उसकी व्यवस्था की गई है।

मैं, यहां पर उपाध्यक्षजी, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने कि शायद जनसंघ की नीति को भी एक तरह से इसके साथ साथ कहने का प्रयत्न किया और अपने ढंग से औद्योगीकरण के बारे में भी कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह कहा कि राजस्थान के अन्दर जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वे राजस्थान में इस वजह से इंडस्ट्रीज़ लगाने को तैयार नहीं हैं कि उन्हें पूरा प्रोटेक्शन नहीं है और इसीलिए उन्हें राजस्थान में इंडस्ट्रीज लगाने का अट्रेक्शन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कलकत्ते की विज़ीट के बारे में भी कुछ कहा कि प्रोटेक्शन अगर राजस्थान में मिले तो हम इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात को सोच सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलकत्ते में प्रोटेक्शन के बारे में तो मुझसे किसी ने यह नहीं कहा कि प्रोटेक्शन की कोई राजस्थान के अन्दर कमी है। इतना जरूर है कि जब इंडस्ट्रीज़ के इंस्टालेशन की बात-चीत होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स यह चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फेसीलिटीज़ मिलें, ज्यादा से ज्यादा कंसेशन्स हों और वे इसकी बात करते हैं। वही बात कलकत्ते में भी आई और रात दिन सामने आया करती है। हमने भी अपनी तरफ से इसके लिए एक तरह की लिबरल पॉलिसी अनाउन्स की कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ लगाई जायं तो क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। कैपिटलिस्ट्स का जहां तक सवाल है राजस्थान में अगर वे आएं और उद्योग लगावें तो कहां तक इन्डिवीजुअल प्रोटेक्शन का सवाल है वह राजस्थान में उपलब्ध न हो, ऐसी तो कोई बात नहीं आई है। इस प्रोटेक्शन की बात को डिफाइन करते हुए कहा गया कि भीलवाड़ा के अन्दर एक मिल बन्द हो गई, उसको अगर लोन दिया जाता तो वह ठीक होता। इस सम्बन्ध में विस्तार से तो हमारे उद्योग मंत्रीजी आपको बतला चुके होंगे कि उस मिल की क्या स्थिति थी और उस हालत में जो कुछ करना सम्भव हो सकता था, किया गया था। लेकिन उस तरह के प्रोटेक्शन को तो शायद इस सदन के माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाय। जहां पर इतना अधिक कर्जा हो, इतना ट्रांजेक्ट हो जाय उनको लोन देना और यह कहना कि मिल चलाओ, मैं समझता हूं कि इंडिवीजुअल इन्डस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्शन देने की डेफिनिशन में आता हो वह बात तो अलग है, लेकिन हमारे लिए यह कभी सम्भव नहीं था। वैसे हम खुद चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो उद्योग लगाना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
चाहते हों वे उद्योग लगाने के लिए आवें और मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि आज जितनी पॉवर हमारे यहां पर इस फर्स्ट स्टेज में, जिसे मैं कहूं भाखरा से उपलब्ध होगी, हमारे और पॉवर हाउसेज़ से होगी, चम्बल से होगी, उसके यूटिलाइज़ेशन के लिए जितने उद्योगों की आवश्यकता है उन उद्योगों के बारे में बातचीत करीब २ फाइनेलाइज़ सी हो चुकी है और बिजली यहां पर खपत नहीं होगी या उद्योग नहीं लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहां पर उद्योगों के लिए काफी उत्साह है लोगों के अन्दर आसपास में, कलकत्ता, बम्बई और दूसरी जगहों में और बराबर एन्क्वायरीज़ आती हैं।

मैंने आपके सामने कुछ बड़े उद्योगों के बारे में शुरू में कहा था और यह निश्चित मानकर चलें कि राजस्थान में उद्योगों के लिए लोगों में उत्साह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज जितनी बिजली उपलब्ध है उसके अनुसार इन्डस्ट्रीज़ लगाने के लिए लोग उत्सुकता के साथ राजस्थान के अन्दर आ रहे हैं। राजस्थान औद्योगीकरण तेजी से होने वाला है, आने वाले वर्षों में। इसकीमुझे कोई शंका नहीं है। ६२ तक अपने यहांजितनी बिजली उपलब्ध होगी उसके लिए बातें कर चुके हैं, बल्कि यहां तक कि १९६३-६४ में प्रतापसागर और दूसरी जगह से बिजली उपलब्ध होगी उस दृष्टि से प्लान किया जा रहा है,क्योंकि आज हम कमिट करने की पोज़ीशन में नहीं हैं। इस हद तक लोगों का उत्साह है फिर भी एक बात को कहकर, एक अच्छा औद्योगीकरण का वातावरण हम कलकत्ता भागकर या बम्बई जाकर बनाते हैं उसके लिए यहां पर एक भाषण दे दें कि उद्योग के विकास के लिए उत्साह नहो है, तो उत्साह हम जानते हैं कि कितना है और कितना नहीं है। केवल कहने मात्र से उस उत्साह के बारे में परिवर्तन नहीं होता है। वह दिखाते हैं बहुत उत्साह प्राइवेट कैपिटल के लिए, उस उत्साह को दिखाने के लिए कहने में कोई एतराज नहीं है मुझे। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है एक निश्चित नीति के अनुसार जो सिद्धान्त इस कांग्रेस के हैं, प्राइवेट कैपिटल के बारे में, ब्रॉड इश्यूज़ उसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जिन पॉलिसीज़ को सभी समझते है। उन्होंने कहा कि नेशनलाइज़ नहीं कर लें, इसका बड़ा खतरा है लोगों के दिलों के अन्दर कि कहीं नेशनलाइज़ नहीं कर दें। तो, उपाध्यक्ष महोदय,नेशनलाइज करने के बारेमें एक निश्चित नीति जारी की जा चुकी है। भारत सरकार की एक निश्चित नीति है कि मौजूदा धन्धों में से किन क्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर में काम करना है। इसके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि देश के विकास के लिए आज इतनी गुन्जायश है कि पब्लिक सेक्टर में जो कुछ किया जा रहा है उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है कि काफी काम किया जा सकता है। यह सिद्धान्त सब कोई मानेंगे कि कुछ बेसिक इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनका देश के आर्थिक जीवन के साथ गहरा जुड़ा हुआ सम्बन्ध होता है। उन चीजों को पब्लिक सेक्टर के अन्दर चलाया जाय तो उपयुक्त रहेगा; जैसे स्टील, पेट्रोल के मामले का काम है तथा और चीजें हैं उन चीजों को पब्लिक सेक्टर में रखा जाता है तो, मैं समझता हूं, किसी को इसके बारे में एतराज नहीं होना चाहिए। यह एक सिद्धान्त की बात है कि जब हम यह चाहते हैं कि हमारे देश का एक सोशलिस्टिक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पेटर्न बने तो सोशलिस्टिक पेटर्न बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर इफेक्टिव तरीके से काम करे और उसकी नोन टैक्सेशन रेवेन्यू है वह देश के विकास में लगे। एक तरफ हम कहना चाहते हैं कि टैक्सेशन नहीं हो, दूसरी तरफ हम कहते है कि पब्लिक सेक्टर नहीं हो और तीसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि उद्योगपतियों को उत्साह नहीं है, तो ये सारी बातें उचित नहीं हैं। आज देश के अन्दर प्राइवेट कैपिटल के लिए, ऐसा मैं समझता हूं कि इन्डिपेन्डेन्स के बाद जितनी ऑपोर्चुनिटीज़ मिली हैं और जितना इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है वह सारे देश में स्पष्ट है। राजस्थान के लिए मैं कह चुका हूं कि राजस्थान के लिए लोगों में काफी उत्साह है और उसके परिणाम कुछ तो अभी नजर आ रहे हैं सामने और कुछ परिणाम बहुत निकट भविष्य के अन्दर और राजस्थान में नजर आयेंगे। लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं एलान कर दूँ कि बस ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइज़ेशन नहीं होगा, हम किसी चीज़ के अन्दर इन्टरफियर नहीं करेंगे, उनका प्रोटेक्शन होगा। तो मैं समझता हूं कि यह निश्चित नीति है हमारी इन मामलों में, और कोई नया एलान करने की जरूरत नहीं है। हम यह एलान नहीं करेंगे कि सारी बसेज़ का नेशनलाइज़ेशन हो जायगा। जिस एक्सटेन्ट तक फन्ड्स हमारे पास होंगे उस हद तक हम नेशनेलाइज़ करेंगे। नेशनलाइज़ नहीं करें, यह हमारी नीति नहीं है। फण्ड्स की ऐवेलिबिलिटी पर नेशनेलाइज़ेशन की नीति आधार रखती है। उसके अनुसार हम करने के पक्ष में हैं।

जहां तक प्रोटेक्शन देने का सवाल है, तो प्रोटेक्शन से मतलब फेसिलिटीज़ से है। तो हम पहले ही क्लिअर एनाउन्समेंट कर चुके हैं और आज भी कई डिफिकल्टीज़ होंगी, उनको फेसिलिटी देने के बारे में तो सरकार सोच सकती है। और दूसरी जो मूल बातें हैं वे सारी केन्द्र से सम्बन्धित हैं और केन्द्र ने इस मामले में इन्डस्ट्रियल रिज़ोल्युशन के जरिये और बड़ी पॉलिसीज़ से बहुत कुछ स्पष्ट कर रखा है और मैं समझता हूं कि उस तरह की सारी चीजें होते हुए आज देश के अन्दर इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

एक–दो सदस्यों ने कहा कि मुनाफा होते हुए भी वह दूसरों के पास जाय, लाभ सब उनको नहीं मिले तो उद्योग नहीं पनप सकते है। यह उद्योग के पनपने के लिए रुकावट है, ऐसी स्थिति आज देश के अन्दर नहीं है। मैं समझता हूं कि जानने वाले जानते हैं कि अमेरिका के अन्दर आज इस देश के लिए यह कहा जाता है कि इंडिया के अन्दर मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट है ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। जानने वाले सब समझते है कि फेवरेबल क्लाइमेट है या नहीं। अगर नहीं होती तो इंडिया के अन्दर इतना कैपिटल इन्वेस्ट होने का सवाल नही आता। राजस्थान के अन्दर यह कहा जाता है कि फेवरेबल एटमोस्फियर नहीं है। दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त फर्टीलाइज़र फैक्टरी का सवाल था तो अब एक नहीं, तीन–तीन प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स इस बात के लिए उत्सुक हैं कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खोलने का उनको मौका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिया जाय कि राजस्थान के अन्दर वे इन्डस्ट्री लगायें। वह आज २५ करोड़ की इन्डस्ट्री है। प्रोटेक्शन का सवाल आज कहां से नया आ गया है ? नया कोई करें, उसका तो प्रश्न ही नहीं आता है। भूल से कोई उनको मिल गया होगा हैदराबाद में जिसको यहां आना नहीं होगा उसने आपको कह दिया होगा और आपने यहां कह दिया। किसी प्रकार के उद्योग लगायें उसके मामले में उत्साह की किसी प्रकार की कमी की बात आती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो हमारा प्लान है, जो हमने बनाया है और जो देश का प्लॉन है ११५० करोड़ रुपया कुल मिलाकर स्टेट्स को कॉन्ट्री-ब्यूट करना है स्टेट के प्लान के अन्दर, तो फिर आबादी के लिहाज़ से, उस अनुपात से राजस्थान के अन्दर ८१ करोड़ वह कॉन्ट्रीब्यूट करे, बाकी हिस्सा केन्द्र की तरफ से मिलना चाहिए। अगर हम उसको बिल्कुल आबादी के आधार पर देखें तो इस एक हद तक ठीक है कि ११५० करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा राजस्थान पर ४२ करोड़ रुपया आ सकता है और उस हिसाब से प्लान को भी हम देखें तो प्लान भी १६६ करोड़ के करीब हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से उसको देखना होगा। जहां उस प्रोपोर्शन से कम अपना हिस्सा समझ कर चलें वहां उसी पर्सेन्टेज पर हम अगर लगायेंगे तो जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि आबादी के लिहाज़ से स्टेट प्लान १६६ करोड़ के करीब हो जायगा। हम अपनी तरफ से २१२ करोड़ का बनाना चाहते हैं। राजस्थान केनाल को स्टेट सेक्टर में नहीं समझते, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस मायने में उसको हमारे सीलिंग के ऊपर दिया जाय। स्टेट सेक्टर में आपको बनाना है क्योंकि वह हमारे यहां पर बनती है। यह बात अलग रही कि उसको स्टेट सेक्टर में रहने दिया जाय, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वह सीलिंग से बाहर रहे, जिस बात को करीब करीब कई माननीय सदस्यों ने कहा। हमारा प्लान २५७ करोड़ रुपयों के करीब पहुँचता है और २५७ करोड़ में से राजस्थान केनाल को हटा दें तो २१२ करोड़ रहता है। तो उस स्थिति में हम पर जिम्मेदारी उस प्रोपोर्शन से ज्यादा आती है और उस प्रोपोर्शन से ज्यादा जिम्मेदारी आये और हमारी जितनी केपेसिटी है उसको देखते हुए हम बातचीत करें और यह लक्ष्य नहीं हो सकता है कि इस बात की कोशिश करें, तो जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कहां से देने वाले हैं ? राजस्थान के अन्दर हम प्लान भी बनाना चाहते हैं, हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को जितना संभव हो उतना अधिक रख कर इस बात की कोशिश करना चाहते हैं कि राजस्थान जो कुछ इस बारे में एफर्ट्स कर रहा है, मुश्किल से वह एफर्ट्स कर रहा है, उसको निगाह में रखते हुए राजस्थान को जो प्लान मिला है उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको पूरा कर सकें और इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि टैक्सेशन का वजन हम पर पहले से ही ज्यादा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में और ज्यादा डाला जाने वाला है। वह टैक्सेशन का भार ठीक नहीं है और राजस्थान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इस प्रकार की बात इसमें कही गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि आज जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश के अन्दर टैक्स का भार आया उस टैक्स के भार के बारे में मुझे जहां तक जानकारी है ऐसा माना जाता है कि उस टैक्स का भार दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना देश पर पड़ा वह करीब २२ प्रतिशत ऑफ दी टोटल आउटले, जिसको हमें कहना चाहिए उसके हिसाब से और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो टोटल आउटले बनता है उसके आधार पर पड़ेगा वह आंकड़ा २४ प्रतिशत के करीब है; तो जो पंचवर्षीय योजना अमल में होती है और उस पंचवर्षीय योजना की वजह से जो असर यहां पैदा होता है उनको निगाह में रखकर चलना होगा और उसको निगाह में रख कर चलें तो इससे मालूम होगा कि जो टैक्स करना चाहते है वह एग्ज़िस्टिंग लेवल पर ज्यादा प्रेशर न पड़े इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अधिक प्रेशर न पड़े, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्कम जेनरेट हो उसका कुछ हिस्सा वापिस आना चाहिये। तभी तो विकास हो सकता है और तभी प्लान चल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। प्लानिंग कमीशन ने इन फिगर्स को तय किया। जैसा कि एक सज्जन ने कहा कि २१२ करोड़ का ही प्लान क्यों बनाया गया, ४०० करोड़ का प्लान हो सकता था। मैं समझता हूं कि ४०० करोड़ का प्लान बनाना ज्यादा आसान हो जाता है बजाय २१२ करोड़ के। मैं जब प्लान को लेकर बात करने जाऊं तो यह स्थिति होनी चाहिये जिसके कारण यह कह सकूं कि जो साधन चाहिये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिये उसमें राजस्थान अपना हिस्सा अदा करेगा और वह प्लान देश की हालत को देखते हुए वाजिब बनना चाहिये और वही मिल सकता है। क्योंकि आज हर एक प्रदेश विकास करना चाहता है और कांट्रीब्यूशन करना चाहता है। आज मध्य-प्रदेश और यू. पी. ने बड़े प्लान बनाकर भेजे, इसलिये यह समझना कि बड़ा प्लॉन बनाया इसलिये बड़ा हो जायगा और हमने छोटा बनाया इसलिये हमें थोड़ा मिलेगा, ठीक नहीं है। बड़ा प्लान बनाना आधार नहीं हो सकता। आधार वह होगा कि व्यवहारिक दृष्टि से कौनसा ठीक है। हमने व्यवहारिक दृष्टि से बनाकर पेश किया है, हम भी उसको कहीं ज्यादा बना सकते थे। लेकिन हमने व्यवहारिकता को ध्यान में रख कर इस दृष्टि से प्लान बनाया है कि कोई भी व्यक्ति इसको निपक्ष दृष्टि से देखे तो वह इसको समझ सके और अपने आपको संतुष्ट कर सके कि हमारी मांग वाजिब है। राजस्थान के लिये इस दृष्टि से, सारी व्यवहारिक चीजों को देखकर कि क्या हमारे रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, क्या हमारी आवश्यकता है इनको देखते हुए क्या मिलना संभव हो सकता है; इन सारी बातों को लक्ष्य में रख कर इन आंकड़ों को तैयार किया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है।

मैं मानता हूं कि सभी लोग उत्सुक हैं कि राजस्थान का तेजी से विकास होना चाहिये, बड़ा प्लॉन होना चाहिये। तो मैं समझता हूं, इतना मान कर चलें कि हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण भी सामने रखना चाहिये। हम राजस्थान नहर के लिये पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि वह सीलिंग से बाहर रहे। इतना करते हुए भी यदि यह अलग रहता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर आने वाली है, हमें बहुत बड़ा काम करना है, देश के लिये और राजस्थान के लिये जो एफर्ट्स हैं उनके द्वारा पूरा करना है क्योंकि एक तरफ की बात करने से काम पूरा नहीं हो सकता। दूसरी योजना को हमने पूरा किया तो तीसरी योजना में उनको पूरा करना असंभव नहीं है। इसके लिये सबका सहयोग अब तक मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा करके हम चल सकते हैं। इस दृष्टि से हमने अच्छा प्लान बनाकर प्रस्तुत किया है।

राजस्थान नहर के लिये यह कहा गया कि केन्द्र ने वादा किया था कि केन्द्रीय सेक्टर में यह नहर रहेगी, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद ऐसा कहा था. यह मानकर चलता हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें शायद उनको मुगालता हुआ है, ऐसा मुझे मालूम हुआ। वह यह है कि एक प्लान पीरियड के बीच में जब कोई प्लान बनता है या एक प्लान बन जाने के बाद जब कोई योजना शुरू होती है तो वह केन्द्रीय सेक्टर में शुरू होती है। जैसे भाखरा प्रोजेक्ट प्रथम प्लान के बाद शुरू हुआ लेकिन दूसरी योजना में वह केन्द्रीय सेक्टर में नहीं रहा ! इसी तरह से राजस्थान केनाल दूसरे प्लान के बीच में शुरू हुई इसलिये यह कहें कि केन्द्र की जिम्मेदारी है तो यह गलत-फहमी है। असल में एक प्लान पीरियड के बीच में शुरू हुआ तो अब भी केन्द्रीय सरकार की ही जिम्मेदारी है, ऐसा कहना वाजिब नहीं होगा। किसी स्टेज में उन्होंने यह कहा हो कि हम पूरा कर देंगे, ऐसा नहीं कहा है। बल्कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे साधनों के बाहर है इसलिये इसको लक्ष्य में रखकर केन्द्र को सहायता देनी चाहिये, यह कहना ठीक होगा बजाय यह कहने के कि वे मुकर रहे हैं।

यह भी कहा गया कि हम राजस्थान नहर पर क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, हमको इससे क्या लाभ होने वाला है और हमें इससे क्या एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है या थर्ड प्लान में हमें इससे क्या लाभ होने वाला है। ऐसा कह कर हम गलती करते हैं। इसका रिटर्न जो एग्रीकल्चर के ऊपर होता है उसमें देरी होती है, लेकिन मनी वेस्ट हो रही है यह गलत समझे हैं क्योंकि सारी नहर बनाने में २०-२० हजार लेबर को काम करना पड़ता है। तो यह बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। इसलिये यह कहना कि राजस्थान को इससे एडवान्टेज नहीं है, गलत है। यदि कोई यह समझ कर चले कि तीसरे प्लान में पूरी नहीं होगी तो चौथे प्लान में नहर पूरी होगी और चालू होगी तो यह बात भी नहीं है क्योंकि यह योजना इतनी बड़ी है कि उसके पूरा होने में समय लगेगा। और कामों में रकम लगाने का असर जल्दी पड़ता है और इसमें रकम लगाने का असर जल्दी नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान में रख कर हम भी जहां-जहां आवश्यकता होगी पूरी तरह से लगायेंगे, यह निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो पहले पब्लिकेशन निकला है उसमें पर केपिटा इन्कम शायद २८२ उन्होंने कोट की थी। इस फिगर में और अभी जो फिगर आया उसमें अंतर कैसे हुआ ? यह बात ठीक है कि उसमें जो फिगर दिया था उसका आधार ईस्टर्न इकोनो-

Page No.105

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिस्ट नाम का जो जरनल निकलता है उसके आधार पर फिगर दिये थे। मैंने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि हमारे पास नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स और नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड साइन्स एंड रिसर्च के फिगर्स थे वे दिये थे। मैंने यह भी कहा था कि इसको टेन्टेटिव समझना चाहिये क्योंकि इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। लेकिन वह एक्सपर्ट बॉडी है। पहली राय ईस्टर्न इकोनोमिस्ट्स की थी। इन दोनों के पर-केपिटा इन्कम के फिगर्स में कुछ फर्क पड़ता है लेकिन ईस्टर्न इकोनोमिस्ट्स की राय को प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार नहीं किया है। अब भी जो फिगर्स बनते हैं वे फाइनली बन गये हों, यह बात नहीं है, अब भी चर्चा चली रही है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेन्स की है उसके फिगर्स बताये थे। मैं फिगर्स कोट अपने नहीं कर रहा था, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन्स के अलग अलग फिगर्स आये, इसलिये अंतर आया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक भाषण के दौरान में यह कहा गया कि राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो पहले के बैंक लॉग़ एम्प्लॉयमेंट के थे उसमें सैकन्ड फाइव इयर प्लान में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा सारी चीजें सर्वे के प्रोसेस के बाद होती है। प्लानिंग कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद रीसेन्टली लिखकर भेजा है, जिसके बारे में फिर चर्चा होगी और फिर निर्णय होगा। इसके बारे में एक दो वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं: "The back log of unemployed in the State in the beginning of the Plan was estimated at 1. 86 lakhs and new entrants to the labour force at 4.50 lakhs. In other words, total job requirements were estimated at about 6.36 lakhs for the Plan period. It may, however, be stated that the subsequent date collected in the course of some of the surveys indicate that these estimates were slightly on the high side. In the context of actual perfermance as well as for the fact that the magnitude of the problem was slightly over-estimated in the beginning of the Plan, view is possible that the level of unempleyment in the State by the end of the Plan is not likely to differ much, from that which was obtaining when the Plan was framed." इसका मतलब यह है कि प्लानिंग पीरियड के बीच जो हमारे यहां एडीशनल लेबर आया वह प्रोवाइड करीब-करीब हो जायगा। जो बैंक लोग आते है वे सर्वे के आधार पर, प्रिलिमिनेरी या यों कहिये कि रिडक्शन आया है। एक्च्युअली डिसक्शन के बाद क्या फिगर बनता है वह देखने की बात रहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार हम एचीवमेंट को यह समझते हैं कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इस तरह से सोचते है। असल में इस मामले में काफी प्रोग्रेस कई सेक्टर्स में हुई है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, उस बारे में ख्याल रख कर चला गया है।

एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, शायद मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था, हमारे मंत्री महोदय ने कहा होगा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक गांव के अन्दर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, वह विस्तार की बात तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उन्होंने कही होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, विलेज इन्डस्ट्रीज़ और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो हमारी पॉवर जेनरेट होगी, उसका १५ पर्सेन्ट इसके लिए रखा जाय, यह निर्णय किया है जिससे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कुओं के लिए, दूसरी चीजों के लिए साथ साथ उपलब्ध हो सके, उसकी योजना बनाई जाय, जिससे पॉवर अधिक से अधिक खर्च की जा सके।

यह भी इस दौरान में कहा गया कि माइनर इर्रिगेशन के साधन उपलब्ध कराने के राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग इलाकों के लिए प्रयत्न किये जायं। मैं समझता हूं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न और दूसरे, जो चर्चा के दौरान में आये, उस सब के ऊपर राजस्थान सरकार, जो सारा प्लान तैयार कर रही है, उसमें देखेगी, वहां डिरक्शन और करेगी कि किस प्रकार से क्या किया जा सकता है जिससे राजस्थान का प्लान ऐसा बने जिसके जरिये लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जो कि पंचायतों में और दूसरी जगह काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिल सके और राजस्थान का विकास ऐसा हो सके, जिसके जरिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तक ऐसी स्थिति में आ सके कि राजस्थान भी काफी बढ़ा हुआ नजर आये। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि राजस्थान के अन्दर काफी पोटेन्शियलिटीज़ हैं और राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश रहे, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में पब्लिक सेक्टर के जरिये, प्राइवेट सेक्टर के जरिये लोगों के एफर्ट्स के जरिये सब तरह राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश नहीं रहेगा, राजस्थान निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। इसमें सभी सदस्यों से निवेदन करना है, इस प्रकार के कार्य के अन्दर, जिससे राजस्थान आगे बढ़ सके, सहयोग दें और सहयोग देने के लिए जैसा कहा है, प्लान ज्यादा से ज्यादा बने, उसमें सबका सहयोग है। मैं आशा करता हूँ कि प्लानिंग करना है, उसके अन्दर आवश्यक चीज़ है कि सबका सहयोग मिलेगा। इन बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ४ बज कर ४३ मिनट पर शुक्रवार दिनांक ६ सितम्बर, १६६० के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, ८ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ　　　　　　　　　　स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक　　२६६६

गत वर्ष भरतपुर जिले में टूटे हुए बंधों के क्षेत्र से सिंचाई दरें लेने की मनाही ।

चूरू जिले में बेरोजगारी की समस्या ।

जालोर जिले के कृषि फील्डमैन के टी. ए. बिल्स का भुगतान ।

गांव देहातु, तहसील शेरगढ़ के हरिजन ।

पुराने अनुभवी कम्पाउन्डर्स की पदोन्नतियां ।

चूरू जिले की अदालतों में पेन्डिंग मामले ।

जयपुर नगर की सफाई व्यवस्था ।

लिमिटेड कम्पनीज़ द्वारा धन राशियों के गबन इत्यादि की शिकायत ।

गांधीनगर तथा बापूनगर (जयपुर) में प्रसूति गृह ।

सब-इन्सपेक्टर पुलिस, चिड़ावा द्वारा श्रीमती तारामनी देवी के साथ बलात्कार ।

बीकानेर जिले के कृषकों हेतु लोहे तथा इस्पात का कोटा ।

स्त्रियों के भ्रष्टाचार की रोक ।

चराई की दर की वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण ।

पुलिस थाना बगड़ी के क्षेत्र में सन् १९५८ से हुई चोरियां ।

बांसवाड़ा जिले के मुअत्तिल पुलिस कर्मचारी ।

जयपुर नगर की गटर लाइन ।

स्पेशल केसेज़ की पुलिस जांच ।

जोड़ बीड़, बीकानेर ।

सिटी बस सर्विस, जयपुर ।

सरकारी नियमों, आज्ञाओं एवं विज्ञप्तियों का पुस्तकाकार प्रकाशन ।

अस्पताल, बाड़मेर ।

ग्राम पंचायत रतनपुरा (चूरू) ।

Page No.108

स्कम्भ

किशनगढ़ के पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन-व्यवस्था।

राजस्थान नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र में सड़कों का निर्माण।

चोरियों व डकैतियों के रजिस्टर हुए मामले।

दन्त चिकित्सालय।

हटीला की हत्या का मामला।

बनास बांध।

एस. पी. द्वारा थानों का मुआयना।

गांधी अस्पताल भीलवाड़ा को भूमि।

मत्स्य निरीक्षकों की नियुक्तियां।

सदन की मेज पर रखे गये नियम। २७५६

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, ने होम (बी-१) विभाग अधिसूचना संख्या एफ. १ (४) (१४) एच. बी. जी. आर १।६०, दिनांक १६ अगस्त, १६६० को, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ (डेवलपमेंट) नियम, १६६० प्रकाशित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

स्कम्भ

प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार २७५७

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा दिनांक ६ सितम्बर, १६६० को प्रस्तुत किये गये निम्नांकित प्रस्ताव पर आज भी विचार किया गया:—

"राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा से संबंधित विभिन्न मदों के ज्ञापन, जिनकी प्रति दिनांक २ सितम्बर, १६६० को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय।"

बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री तेजमल बापना
(२) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
(३) श्री आबिद अली
(४) श्री हरिप्रसाद यादव
(५) रावराजा श्री सरदारसिंह
(६) श्री सोहनलाल भटनागर

स्तम्भ

(७) श्री अनूपसिंह

(८) श्री मुक्तिलाल मोदी

श्री हरिश्चन्द्र. निर्माण मन्त्री, श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री ने अपने अपने विभागों से सम्बन्धित मामलों का स्पष्टीकरण किया।

बहस का उत्तर श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा किया गया।

सदन की बैठक ४ बजकर ४३ मिनट पर शुक्रवार दिनांक ६ सितम्बर, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

स्तम्भ

गुरूवार, दिनांक ६ सितम्बर, १९६० की कार्य सूची

(१) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन (संशोधन) विधेयक से १९६० प्रवर समिति के प्रतिवेदन अनुपूरक उपस्थापना अनुदानों की मांगें १९६०-६१)

(क) मांग संख्या ५८ मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

(ख) मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५६-विविध

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१० का उत्तर देखिये)

LIST OF TANKS

S. No.	Name of Bund	Name of Tahsil	Remarks.
1	2	3	4
1.	Hindola Bund	Bharatpur	
2.	Par Bund	,,	
3.	Doondi Bund	Bayana	
4.	Jaisora Bund	,,	
5.	Nauharda Bund	,,	
6.	Baseri Bund	Roopbas	
7.	Gahlow Bund	,,	
8.	Sona Bund	,,	
9.	Kandholi Bund	,,	
10.	Mahalpur Kachi Bund	,,	
11.	Mortha Bund	,,	
12.	Sirondh Bund	,,	
13.	Samantgarh Bund	,,	
14.	Bachondi Bund	,,	
15.	Barkhera Bund	Weir	
16.	Bijwari Bund	,,	
17.	Nayagaon Bund (Halena)	,,	

1	2	3	4
18.	Bajera Bund	Weir	
19.	Sarsena Bund	„	
20.	Ballara Bund	Nadbai	
21.	Rena Bund	„	
22.	R. T. Bund	Dholpur-Bari	

———————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ का उत्तर देखिये)

तालिका

क्रम संख्या.	नाम	धन	माह
१.	श्री रूपसिंह फील्डमैन	रु० २०७.७१	जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर व नवम्बर, १६५६ ।
२.	श्री ऊमारामजी फील्डमैन	रु० १७.०६	अगस्त, १६५६ ।
३.	श्री ओंकार सिंह फील्डमैन	रु० ६६.६८	जून, जुलाई, अगस्त, १६५६ ।
४.	श्री विजयसिंह राठौड़	रु० १८०.१४	फरवरी, अप्रेल, १६५६ अगस्त १६५६
		रु० २६.८१)	दो ट्रांसफर बिल हैं ।
		रु० १७५.८६)	जून १६५६ ।

————

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३० का उत्तर देखिये)

	छोटा ब्लॉक	बड़ा ब्लॉक	
गाय, बैल और घोड़ा	२) रु०	४) रु०	वार्षिक
भैंस व भैंसा	३) रु०	६) रु०	वार्षिक
झोटी	१) रु०	२) रु०	वार्षिक
गधा	१) रु०	२) रु०	वार्षिक
भेड़-बकरी	१।) रु०	२॥) रु०	वार्षिक केवल आठ मास के लिये ।
ऊंट	१०) रु०	१०) रु०	वार्षिक

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४१ का उत्तर देखिये)

सूची पत्र-ग्रामों की डूब में आ रहे हैं

तहसील	ग्राम
१	२
	१ बीसलपुर
	२ बटेरा
	३ चोपड़ा चोपड़ी
	४ सूरजपुरा
	५ बालापुरा
	६ थली
	७ नया गांव
	८ रतनपुरा
	९ सांकरवाड़ा
	१० दोवलावास
	११ सुजानपुरा
	१२ भंवरथला
	१३ ठीकरीया
	१४ सरसड़ी
	१५ सांडला
	१६ बनेरिया खुर्द
	१७ मानसिंह पुरा
	१८ तलवासा

१	२
	१६ डावर कला
	२० चोसला
	२१ इन्दोली
	२२ कासिया
	२३ खेजड़ी
	२४ देवपुरा
	२५ वास चतरा
	२६ इन्द्रपुरा
	२७ नगेड़िया
	२८ कुनेड़ा
	२९ चन्थली
	३० दुदावास
	३१ रावता
	३२ कालेड़ा
	३३ थाडोला (दाना का झोपड़ा व वास चतरा)
	३४ थाड़ोली
	३५ नयावास
	३६ बाड़ा का पुरा

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ का उत्तर देखिये)

विवरण पत्र (अ)

क्रमांक	थाने का नाम जिसका निरीक्षण किया गया	निरीक्षण का दिनांक	दिनांक जब कि निरीक्षण रिपोर्ट थाने को भेजी गई	टिप्पणी
१	२	३	४	५
१.	तारानगर	३१-१२-५६ से १—१-५७ केवल रात्रि विश्राम		
२.	रतन नगर	२६—६-५७ से १—७-५७	५—७-५७	
३.	सरदार शहर	२८—५-५७ से ३—६-५७	२०—७-५७	
४.	तारानगर	५—६-५७ से ६—६-५७	२२—७-५७	
५.	भाधू	४—७-५७ से ६—७-५७	१२—७-५७	
६.	सुजानगढ़	३—८-५७ से ५—८-५७	२८—८-५७	
७.	राजगढ़	३०—८-५७ से ६—६-४७	४-११-५७	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
८.	हमीरवास	८-१२-५७ से १०-१२-५७	२—१-५८	
९.	सूव	१०-११-५७ से १२-१२-५७	२—१-५८	
१०.	डूंगरगढ़	२४-१२-५७ से २७-१२-५७	२—५-५८	
११.	रतनगढ़	२८-१२-५७ से १—१-५८	२—५-५८	
१२.	राजगढ़	२५—२-५८ से २८—२-५८	२८—३-५८	
१३.	घाघू	२४—४-५८ से १—५-५८	१७—६-५८	
१४.	हमीरवाल	२५—६-५८ से २७—६-५८	२०-११-५८	
१५.	भीमसर	३०—६=५८ से २—७-५८	२८—८-५८	
१६.	डूंगरगढ़	२३—७-५८ से २७—७-५८	२४-११-५८	
१७.	तारानगर	३०—७-५८ से १—८-५८	१६-१०-५८	
१८.	रतनगनर	२—६-५८ से ५—६-५८	१४-११-५८	
१९.	खेजड़ा	२७—६-५८ से २८—६-५८	१७-११-५५	

१	२	३	४
२०. शंभू	३०—६-५८ से २-१०-५८	२०-११-५८	
२१, सुजानगढ़	४-१२-५८ से ७-१२-५८	२२—३-५६	
२२. जिलली	१६-१२-५८ से १७-१२-५८	१३—६-५६	को थाने में पहुँची जिस पर एस पी के दस्तखत १५-४-५६ के हैं।
२३. रतनगढ़	३०-१२-५८ से १—१-५६	३०—४-५६	
२४. फतहपुर	३—५-५६ से ७—५-५६	२२—८-५६	
२५. रामगढ़	७—५-५६ से ६—५-५६	१७—८-५६	
२६. श्री माधोपुर	८—६-५६ से १२—६-५६	५-१०-५६	
२७. लछमनगढ़	१३—६-५६ से १५—६-५६	२२—२-६०	
२८. नेचवा	१७—६-५६ से १६—६-५६	३—१-६०	
२६. खाटू	२६—६-५६ से २-१०-५६	५—३-६०	
३०. सिंहरावत	१७-१०-५६ से १६-१०-५६	२३—३-६०	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
३१.	रघुनाथ गढ़	२२-१०-५६ से २५-१०-५६	१०—३-६०	
३२.	खंडेला	२३-११-५६ से २६-११-५६	१०—३-६०	
३३.	दातारामगढ़	६-१२-५६ से ९-१२-५६	२६—२-६०	
३४.	नीम का थाना	१२-१२-५६ से १६-१२-५६	२५—३-६०	
३५.	पाटन	२०-१२-५६ से २२-१२-५६	२३—३-६०	
३६.	थोई	३०-१२-५६ से २—१-६०	२९—४-६०	
३७.	सदर (सीकर)	५—९-५६ से ७—९-५६	१—३-६०	
३८.	कोतवाली (सीकर)	२५—८-५६ से २७—८-५६ एवं १२-९-५६	२८—१-६०	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ का उत्तर देखिए)

सूची

न० शु०	नाम व्यक्ति जिनकी भूमि अवाप्त की गई	अवाप्त कब की गई	रकबा
१.	२.	३.	४.
१.	श्री कल्याण वल्द भेरू माली श्री नेमीचन्द वल्द कन्हैयालाल महाजन	यह भूमि सन् १६४६ में मेवाल सरकार के समय अवाप्त की गई थी।	१। ३ १ १
२.	श्री कल्याण वल्द भैरू, मोहन वल्द कल्याण गुलाबप्यारा, श्रीकिसन, गोकल वल्द ऊंकार माली	,, ,, ,, ,,	३
३.	श्री कल्याण वल्द भैरू, मोहन वल्द कल्याण	,, ,,	५। २
४.	श्री काना वल्द जवाना माली श्री नेमीचन्द कन्हैयालाल	,, ,,	१।।। ३
५.	श्री मथुरा वल्द चौथमल महाजन	,, ,,	।।। ४
६.	श्री काना वल्द जवाना कल्याण वल्द भैरू माली	,, ,,	१
७.	श्री गोकल वल्द ऊंकार माली	,, ,,	।।
८.	श्री गंगाराम, रामसुख पिता श्रीराम काना वल्द जवाना, मांगीया वल्द दला, कल्याण भैरू माली	,, ,,	। ४
६	श्री गंगाराम, रामसुख पिता श्रीराम माली	,, ,,	६ ३
१०.	श्री गुलाब प्यारा पिता श्रीकिसन माली	,, ,,	२।। ३
११.	श्री बालू वल्द मांगिया दला माली	,, ,,	१। १

१	२	३		४
	श्री नेमीचन्द कन्हैयालाल पिता चान्दमल महाजन	,,	,,	१।
१२.	श्री हरिवल्लभ वल्द हजारी महाजन	,,	,,	३। ३
१३.	श्री गिरधारी वल्द श्रीसुराम ब्राह्मण	,,	,,	३। २
१४.	श्री रामसुख वल्द गोकललाल, कन्हैयालाल पन्नालाल महाजन	,,	,,	२। २
१५.	श्री रूपचन्द इन्दरमल पिता अणदीराम महाजन रामलाल मथुरालाल सोभाणी	,,	,,	२। २
१६.	श्री बालूलाल वल्द फूलचन्द महाजन जोजै	,,	,,	३ २
	सोहनसिंह राजपूत	,,	,,	२
१७.	श्री फतहराम वल्द रामनाथ महाजन	,,	,,	४॥। २
१८.	श्री धंकल वल्द लछमन, मदनलाल वल्द रामसुख	,,	,,	१ ३
१६.	श्री चुन्नीलाल वल्द बद्रीलाल बछु	,,	,,	। २
२०.	श्री भैरू मोहन पिता कजोड़ कुम्हार	,,	,,	६। ४
२१.	श्री भैरू मोहन पिता कजोड, हरिवल्लभ वल्द हजारी गिरधारी वल्द धूलाराम ब्राह्मण	,,	,,	।
२२.	श्री रामलाल नानूराम पिता कासीराम महाजन	,,	,,	॥।
२३.	श्री बीलानाम रास्ता	,,	,,	१॥।
				५३ । २

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ८ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६८९	१४	श्री श्रीमानसिह	श्री श्रीमानसिंह
२६९६	अन्तिम से२	पड़ी है।	पड़ी हैं।
२६९७	शीर्षक	२६९७	२६९७
,,	२१	कच्ची है	कच्ची हैं
२६९९	१४	उपयोग लाते	उपयोग में लाते
२६९९	२५	Iimited	limited
२७०७	अन्तिम से३	ने प्र व	ने प्र ड
२७११	४	number of	number of the
,,	६	roganisation	organisation
२७१२	१६	व्ययस्था करण	व्यवस्थाकरण
२७१३	५	श्री वेनराम	श्री बेनाराम
,,	अन्तिम से५	के मुत्तिअल	के मुअत्तिल
२७१५	नीचे से २	ररपमानेन्ट	परमानेन्ट
२७१६	,, ,, ४	नियम हैं ?	नियम हैं।
२७२१	१५	अजमेर	अजमेरी
२७२३	दीचे से ६	रिटन पमिशन	रिटन पर्मिशन
२७२५	७	कोड़ा पंचायत	कटेड़ा पंचायत
,,	१९	की कहां	कहा
२७२६	अन्तिम से८	थोडी ही है।	थोड़े ही है।
,,	अन्तिम	श्री पुरूषोतमलाल	श्री पुरुषोत्तमलाल
२७२८	१३	सिचक योग्य	सिंचन योग्य
२७३१	२०	तो है ही	तो हैं ही
२७३४	अन्तिम से२	जो हां,	जी हां,
२७३५	प्रथम	कम्पन्सेशन	कम्पेन्सेशन
२७४१	२	hypothettical	hypothetical
,,	अन्तिम	लिबरर्टी	लिबर्टी
२७५२	अन्तिम	श्री अनोपसिंह	श्री अनूपसिंह
,,	११	,, ,,	,, ,,

Page No.123

(२

१	२	३	४
२७५६	१४	दुकानदार	दुकानवार
,,	१६	साला में विक्री	सालों में बिकी
२७५८	७	करुंगा	करूंगा
२७५९	५	मेजाबांध	मेजा बांध
२७६०	१७	टैकिनकल	टैक्निकल
२७६१	शीर्ष	बाना)	बापना)
२७६२	२२	एमो	एम्रो
२७६४	१८	सकते है ।	सकते हैं ।
२७६५	२	के नाम	केनाल
२७६७	५	बाफना	बापना
२७६८	१८	कर पावेगे	कर पावेंगे
,,	२९	के शुरूआत	के शुरुआत
२७६९	६	की शुरूआत	की शुरुआत
२७७४	२९–३३	करासू में अप्रेल....अगस्त में	करासू में अप्रेल में, भीमसर में अप्रेल में, सुडसर में अप्रेल में, तारापुर में अप्रेल में, थावना में अप्रेल में, सुजानगढ़ में अप्रेल में, चिड़ावा में जुलाई में, झुंझुनू में मई में, शार्दूलशहर में अगस्त में व पृथ्वीराजपुरा में अगस्त में
२७७५	९	yest	yet
,,	१४	Lecal	Local
२७७६	१	इलेक्शनस	इलेक्शन्स
,,	२	पर ज	पर जो
२७८२	१७	विच इन्क्यूलड्स	विच इन्क्लूड्स
२७८३	१२ व १४	सेटस	सेट्स
,,	२४	थे	ये
२७८४	५	लिनग्राइट	लिग्नाइट
२७८५	४	मैगावाट	मैगावाट ;
,,	७	फइाव	फाइव
२७८७	९	सर्व	सर्वे
२७८८	४	ओरिजिलन	ओरिजिनल
,,	११	अगेस्ट	अगेन्स्ट

१	२	३	४
२७८६	२०	की है	के है
,,	नीचे से ३, ४ ५, ६, ७, ८	राजस्थान............०.४५	राजस्थान कैनाल एरिया १.७५ करोड़्स। रोड्स इन चम्बल एरिया १.६ करोड़्स स्टेट हाइवेज़ १.७८ करोड़्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स १.८१ करोड़्स, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स ७.२७ करोड़्स, माइनर सी० डी० वर्क्स १.६४ करोड्स, रोड्स टू माइन्स क्वेरी ०.४५
२७९१	१४	बीचमेंट	बिटूमेंट
२७९२	१५	जालोरल	जालोर
२८००	नीचे से ७	और	और
२८०२	शीर्ष	रूपरे–खा	रूप–रेखा
२८०३	नीचे से ८	एक तरफ	एक की तरफ
,,	,, ,, ६	३४, २३	३४.२३
२८०५	९	वह	वहां
,,	नीचे की पंक्ति	रुपया	रुपया में
२८०६	२	लिटिगेट	लिटिगेंट
२८०७	६ व ७	देने में नहीं	देने नहीं
२८०९	२८	बर्डर्ड	बर्डर्न्ड
२८१४	२३	बी० एस० स०	बी० एस सी०
२८२०	नीचे से ५	जाता है !	जाता।
२८२३	१८	है।	है।
,,	२२	में	मैं
,,	२६	नयों	क्यों
२८२४	१६	हाइड्रोइलेक्टिक	हाइड्रोइलेक्ट्रिक
,,	१८	निवेतन	निवेदन
२८२६	११	पदार्थो	पदार्थों
२८२८	३२	रहा। और	रहा और
२८३१	१४	कॉपोरेशन	कॉर्पोरेशन

१	२	३	४
२८३२	नीचे से १२	पडया	रुपयां
२८३७	शीर्ष	श्री	श्री
२८४३	अन्तिम	दी ।	दी ?
२८४६	शीर्ष	रू–परेखा	रूप–रेखा
२८४८	११	के०	के
,,	१६	लियार्जी	लिथार्जी
२८४६	१४	अन्कुशश	अंकुश
२८५२	अन्तिम	८ जार	८ हजार
२८५३	१६	मतलव	मतलब
२८५४	२६	ग्रान्ट की,	ग्रान्ट कीं,
,,	२३	कारडिंग	कार्डिंग
२८६०	१३	क्लोरिफिकेशन	क्लेरिफिकेशन
२८६१	नीचे से ६	फर्टेलाइजर	फर्टिलाइज़र
२८६२	नीचे से ४	मैटियरल	मैटीरियल
,,	१३	बट	बढ़
२८६३	१	इन्डस्ट्रिय	इन्डस्ट्रिय
२८६४	४	Soctor	Sector
,,	नीचे से ६	ओर	और
२८६८	२	राजस्थानों	राजस्थान में
२८६६	११	औ,	और
२८७१	नीचे से ७	धनर–ाशि	धनराशि
२८७६	शीर्ष	रूपरे–खा	रूप–रेखा
२८७७	नीचे से ३	और ज्यादा	और वे ज्यादा
२८८२	नीचे से ८	बेलेंश	बैलेंस
२८८५	१	ब्यवस्था	व्यवस्था
,,	नीचे से ६	इंडस्ट्रीड	इंडस्ट्रीज़
२८८६	१३	कहां	जहां
२८८७	२२	राजस्थान औका योगीकरण	राजस्थान का औद्योगीकरण
२८६४	१७	निपष्न्न	निष्पन्न
२८६६	६	लभ	लाभ
२८६७	४	इन्स्टीटयूट	इन्स्टीट्यूट
,,	नीचे से ७	है ।	हैं ।

१	२	३	४
२८६८	६	date	data
,,	१०	perfermance	performance
,,	१४	unempleyment	unemployment
२९००	नीचे से ४	तद्न्तर	तदनन्तर
२९०६	७	विधेयक से	विधेयक
,,	८	प्रवर समिति के प्रतिवेदन अनुपूरक उपस्थापना अनुदानों की मांगे १९६०-६१	(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन) अनुपूरक अनुदानों की मांगे १९६०-६१
२९१४	नीचे कालम४	१७-११-५५	१७-११-५८